हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार 18 मार्च, 1980

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)1
स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)21
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(13)22
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)42
नेमिंग आफ मैंबर	(13)50
अध्यक्ष द्वारा घोशण– राज्यपाल के अभिभाशण तथा बजट की आम चर्चा पर अपोजी ान तथा ट्रेजरी बैंचिज को दिये गये टाईम संबंधी	(13)52
वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस चर्चा तथा मतदान	(13)53
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– श्री बलदेव तायल द्वारा	(13)62

वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(13)63
बैठक काा समय बढ़ाना	(13)98
वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(13)98

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ मे प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होंगे।

Crop Insurance

***1629. Chauhri Jagdish Kumar Baniwal, Chudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Agriculture be please to state whether thee is any scheme under consideration of the Government to introduce Crop Insurance in the Stat; if so, the details thereof and the time by which it is likely to be implemented and; if not, the reasons therefor?

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): इस संबंध मे आरम्भ मे फसलों की ओलो द्वारा होने वाली हानि के बारे बीमा करने की स्कीम बनाने के लिये एक सब कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष, वित्तयुक्त राजस्व, हरियाणा है। इस सब कमेटी को भारत सरकार

के सामन्य बीमा निगत से विचार विम र्ा कर के स्कीम बनाने के लिये कहा गया है।

क्योंकि इस सब कमेटी की सिफारि ो अभी तक प्राप्त नही हुई है, इसलिये स्कीम का ब्यौरा तथा जितने समय मे इस को राज्य मे कार्यन्वित किया जायेगा, उसे बारे मे इस समय सूचना देनी संभव नही है।

डॉ. मंगल सैनः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि सन् 1947 से भारत सरकार और स्टेट सरकार फसल के बीमा के लिये वक्तन फवक्तन कोि ा ा करती रही है। इस संबंध मे कई कमेटियां भारत सरकार ने भी बनायी और स्टेट सरकार ने भी बनायी। आखिर मे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह मामला बड़ा गम्भीर और लम्बा चौड़ा है। जी.आई.सी. ने अपनी स्कीम दी लेकिन वह भी प्रेक्टिकेबल नजर नही आयी । सन् 1979 मे ब्रिगेडियर रण सिंह की अध्यक्षता मे एक मीटिंग हुई थी, उसमे चौधरी सतबीर सिंह जी भी थे और दूसरे मैंबर साहेबान भी थे। उन्होंने सूखे और फलड आदि के बचाव की सारी स्कीमों को छोड़कर एक ही बात दायरे मे ले जी कि ओलावृश्टि से बचाव की स्कीम को ही लिया जाये। उसके बाद एक सब कमेटी बनायी गई जिसके अध्यक्ष एफ.डी.आर. साहब है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि ओलो से फसल का नुकसान होने के बारे मे

जो सब कमेटी बनायी गई है, क्या उसमे किसानो के प्रतिनिधि या एम.एल.एज. साहिबान को भी भाामिल करेंगे, दूसरे वह कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

सरदार तारा सिंहः यह कमेटी पहली सरकार ने ब्रिगेडियर रण सिंह की अध्यक्षता मे बनाई थी। अगर एम.एल.एज. साहेबान भी उसमे भाामिल होना चाहते है तो हमें कोई एतराज नही, हम उनको हर वक्त भाामिल करने के लिये तैयार है। मैं अर्ज कर दूं कि यह स्कीम बम्बई मे डा. डांउकारने ने बनाई थी और राजस्थान मे भी यह स्कीम हैं इन स्कीमो के बारे मे हमारी कमेटी गौर कर रही है। कितना टाईम लगेगा, यह मैं कुछ नही कह सकता। जहां तक चौधरी संत कंवर जी का सुझाव है कि इस कमेटि एम.एल.एज. और प्रोग्रैसिव फामर्ज को लिया जाये, उनको हम लेने के लिये तैयार है।

श्री अध्यक्षः सरकार को कोई एतराज नही है, दूसरे लोग भी मैंबर्ज लिये जा सकते है।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, सरसो, तोरिया और आलू की फसल पांच साल मे, दो साल मे या तीन साल मे पाले या कोहरे से बर्बाद हो जाती है। क्या सरकार इस कमेटी के स्कोप मे इन फसलो को भी भाामिल करेगी ?

सरदार तारा सिंहः जो जी.आई.सी. की स्कीम थी उसमे यही डिफिकल्टी थी कि उसमे मेन मेन इलाकों की मेन क्रप्ट ही

रखी गई थी यानी पैडी और व्हीट को रखा गया था दाले ओर आयल सीडज को नही रखा गया था। ब्रिगेडियर रण सिंह की अध्यक्षता मे जो कमेटी बनी थी उसने इसीलिये उसको रिजैक्ट किया था।

श्री अध्यक्षः यह इतना वास्ट सब्जैक्ट है जिस पर काफी विचार करने की जरूरत है। भाुरू मे ओलो की स्कीम को ले लिया जाये अगर एक स्कीम ही पार हो जाये तो भी काफी है। हर स्कीम को चलाये तो कोई भी पूरी नही होगी।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, जो कदम सरकार ले रही है वह बड़ा अच्छा कदम है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो ुसले टिड्डी दल से खत्म हो जाती है, क्या इस स्कीम मे उसको भी भाामिल करेंगे?

सरदार तारा सिंहः हमे चाहाते है कि इस स्कीम की भाुरूआत ओलो से की जाये, फिर कहत ाली को ले ले। इस तरह से अहिस्ता अहिस्ता तीन चार चीजों को ले ले। कमेटी ओला, फल्ड और टिड्डयों से होने वाले नुकसान को बेस बना कर रिकमैंड करेगी। भाुरू मे ओला का ही हो जाये तो बड़ी अच्छी बात है। बंबई की स्कीम मे काफी चीजे भाामिल है इसलिये जमींदारो को प्रीमियम काफी देना पड़ता है। सरकार किसान का भला करना चाहती है, बुरा करना नही चाहती। टिड्डी दल से तो कभी दस साल के बाद नुकसान होता है लेकिन जमींदार को

प्रीमियम हर फसल का देना पड़ेगा। इसलिये यह स्कीम अभी ठीक नही रहेगी। जिन फसलों आदि से साल दो साल मे नुकसान होता है उनको पहले लिया जाये। टिड्डी दल की स्टेज तो कभी कभी आती है इसलिये जमींदार को प्रीमियम अधिक देना पड़ेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सरकार ने जो कमेटी कांस्टीच्यूट की थी, उसने क्या प्रोग्रेस की है और कितनी उसकी मीटिंग्ज हुई है ?

सरदार तारा सिंहः उस कमेटी की तीन मीटिंग्ज हो चुकी है। वह कमेटी बम्बई और जयपूर जाकर उनकी स्कीमें ले कर आयी हतै। हम ने डॉ. मैटीरियल मांग लिया हे कि वह देना भी बडा मु ाकल हैं वे कहते है कि हरियाणा की सारी नहरो और गांवो का एक फुट के कागज पर नक ाा हो। स्टेट मे पिछले दस सालो मे कितनी क्राप हुई, लौंगीच्यूड और ऐल्टीच्यूड की दोनो तरफ की डिस्क्रि ान, कितना नुकसान हुआ, कितना मुनाफा हुआ और किस तरह से हुआ यह सारी सुचना उसमे होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ महकमा माल का नुकसान भी मांगा है। इन सारी चीजों को सक्रूटेनाइज करने मे काफी टाईम लगेगा।

चौधरी जगदी ा कुमार बैनीवालः क्या मंत्री महोदय बताने की कश्ट करेंगे कि कपास और नर्मा को भी इस स्कीम मे इन्क्लूड करेंगे ?

सरदार तारा सिंहः मैंने पहले ही बताया है कि इन फसलों को नही रखा है। जो फसल ओले से तबाह होती है उसको ही रखा है।

स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्तों को प्रीमियम के बारे मे भी बता दू। जी.आई.सी. वालो ने कहा कि 1 करोड़ 63 लाख रूपये किसान पहले बर्दा ात करे और चार करोड़ से कुछ ऊपर कोआप्रेटिव वाले करे। मोटे तौर पर इसका प्रीमियम 30 परसैंट, 15 परसेंट और 5 परसैंअ बताते है।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, आदमियो की कमेटी बनी थी जिसमे मैं, ब्रिगेडियर रण सिंह और चीफ मिनिस्टर साहब थे। जी.आई.सी. वालो से इस स्कीम के बारे मे हमारी बातचीत हुई थी लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया थां फिर हमने सुझाव दिया था कि अगर जी.आई.सी. रोड़ा अटकाती है तो कोई दूसरी स्कीम चालू की जाये। हमाने ऐसा विचार बनाया था कि सैंट्रल कोआप्रटिव बैंक के अंदर जमींदारों से आठ आने या एक रूपया एकड़ के हिसाब से जमा करवा लिया जाये। इस तरह का रिलीफ फंड क्रियेट किया जाये और जब भी ऐसी स्थिति आये तो उनको पैसा दे दे दिया जाये। क्या कमेटी इस बारे मे भी विचार करेगी ?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मैं असल बात बतानी भूल गया। मैंने तीन मैंबरो की कमेटी बता दी लेकिन उसमे 17

मैंबरान थे। उस कमेटी ने यह फैसला किया था कि बाकी सारी आइटम्ज को ड्राप कर दिया जाये केवल ओलो द्वारा होने वाली हानि को ही इस स्कीम मे भाामिल किया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप मिनिस्टर महोदय को अलग से मिल कर डिसकस कर ले क्योंकि इस सवाल पर काफी सप्लीमैंटरीज हो चुकी है।

डॉ. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान है कि मंत्री और आनरेबल मैंबर बीच मे इधर उधर आते जाते रहते है यह अच्छा हनी लगता, इसलिये इन को बंद किया जाये।

Mr. Speaker: I did not notice any body. I would request the Hon'ble Ministers and Members to please observe the decorum in the House and not to breach the same.

Roads constructed under the scheme "Food for Work"

***1645. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state—

(a) whether thee is any scheme under consideration of the Government to convert the Kacha roads constructed under the scheme "Food for Word" into metal led roads; and

(b) if so, the time by which it is likely to be done?

विकास मंत्री (राव राम नारायण):

(क) नही जी।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्र न उत्पन्न नही होता है।

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय, 'काम के बदले अनाज' की जो स्कीम सरकार ने चालू की है उस के तहत गांवो मे कच्ची सड़कें बनई गई है। उन पर 15 करोड़ रूपया भारत सरकार का खर्च हुआ है। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि गांवो के अंदर जो मिट्टी का काम हुआ है, उसको सुरखित रखने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राव राम नारायण: जितनी लिंक रोडज पर मिट्टी का काम हुआ हे वह तो पी.डब्ल्यू.डी. के अंडर टेक करेगा। हमारी सरकार ने यह कमिटमैंट की है कि सन् 1981 तक सभी लिंक रोजड पक्की कर दी जायेगी। जो पंचायत एरिया मे अर्थ वर्क हुआ है, उसको पंचायत देखेगी। जो गांव की फिरनी है। उसको गांव की पंचायत खुद पक्की बनायेगी। अगर पंचायत के पास पैसा नही है तो गवर्नमैंट भी उसकी मदद देगी।

डॉ. बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों को लिंग रोड़ नही दिया गया है और वे पी.डब्ल्यू.डी. की स्कीम के तहत भी नही आते, यदि उन रोड़ज पर 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत मिट्टी

डाली दी जाये तो क्या सरकार उनको पक्का करने का आ वासन देगी?

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया है कि जो गांवो की फिरनी है, उन को सरकार पक्का नही करेगी। यदि पंचायत पक्का करना चाहती है तो वह कर सकती है। यदि पंचायत के पास रिसोर्सिज नही है तो गवर्नमैंट मदद देगी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अभी मंत्री जी ने बताया है कि गांवो मे जो 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत कच्ची रोड़ बनायी जायेगी, उसको सरकार बिल्कुल पक्का नही करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन पंचायतो के पास फण्ड नही है, कया उनकी मदद कर सकती है?

श्री अध्यक्षः जो पंचायत गवर्नमैंट से मदद लेना चाहेगी उसे मदद दी जायेगीं मंत्री महोदय ने इस बारे मे बता दिया है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि अगर दो गांव मिल कर 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत किसी लिंक रोड़ या एप्रोच रोड को बना दे, तो क्या ऐसी सड़को को पक्का किया जायेगा ?

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय ने कहा है कि पंचायत अपने फण्ड से पक्की करेगी लेकिन अगर पंचायत चाहेगी तो गवर्नमैंट उनको मदद दे सकती है।

श्री लहरी सिंह मेहराः क्या गवर्नमैंट ने ऐसा कोई फण्ड रखा हुआ है ?

राव राम नारायणः अध्यक्ष महोदय, हमने उनकी रिक्वायरमैंट के हिसाब से फण्ड अलाट कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायत का महकमा और पी.डब्ल्यू.डी. आपस मे को–आर्डिने ान करके गांवो मे जो अर्थ वर्क हुआ है, उसको पक्का करने के लिये तैयार है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने जो सुझाव दिया है यह बहुत अच्छा सुझाव है। हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत जहां पर दो गांवो ने मिल कर मिट्टी डाल दी है, उस सड़क को पहले पक्का किया जाए।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने गढ़वाल और टटोली का भी पुल देखा और सिसरोल की एप्रोच रोड को भी देखा है। यह पुल जो बनाया गया है, उल्टा और टेढ़ा बनाया गया है। छछरोली वाली सड़क को जहां से गांव वाले चाहते है वहां से नही बनाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से

जानना चाहूंगा कि क्या उस पुल का एस्टीमेट बन चुका है और जो सड़क है, उसको जहां से गांव वाले चाहते है, वहां से बनाया जायेगा ?

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपका कोई सवाल नही बनता। मेहरबानी करके आप अलग से नोटिस दे दे या सी.एम. साहब से बाद मे उनके कार्यालय मे मिल ले।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत जहां पर मिट्टी का काम हुआ है, उसका पक्का करने के लिये मंत्री जी ने जवाब बिल्कुल नही मे दिया है। लेकिन उन्होंने बाद मे कहा है कि 'फूड फार वर्क' का काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस 'फूड फार वर्क' स्कीम को ड्राप तो नही करना चाहती ?

चौधरी भजन लालः हमने इस काम को ड्राल नही किया है बल्कि यह काम पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा है। हमने इस साल भारत सरकार से पहले साल की अपेक्षा अधिक अनाज मांगा है। राव साहब ने कहा है कि लाल डोरे मे और आबादी देह मे सरकार पक्की सड़के नही बनायेगी। भाायद माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि गवर्नमैंट आबादी देह मे पक्की सड़कें नही बनाती, गांव वाले या पंचायत खुद बनाती है। पंचायत बपने फण्ड से पक्का करना चाहे तो कर सकती है। जैसे कि राव साहब पहले ही

कह चुके है अगर पंचायत चाहे तो सरकार उसकी मदद कर सकती है।

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, यह जो मौजूदा 'अनाज के बदले काम' की स्कीम चल रही है, उसके तहत कई जगहों पर जिस गरीब मजदूर ने काम किया है, उसको तो मजदूरी नही मिली है और गांव मे जो ट्रेक्टर वाले है, ट्रक वाले है, उनको मिट्टी डालने के पैसे दिये गये है। क्या यह बात सरकार के नोटिस मे हे कि 'अनाज के बदले काम' स्कीम के तहत भी गरीब आदमियों को काम न देकर ट्रैक्टर वालो से और बड़े किसानो से मिट्टी डालने का काम करवाया गया है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के नोटिस मे कोई ऐसी बात आयी हो कि जिस गरीब आदमी ने मिट्टी डालने का काम किया है, उसको पैसे नही दिये गये, वह हमारे नोटिस मे लाये, हम उसकी बाकायदा इंकवायरी करवाकर जिस किसी ने कोई गलत काम किया है, उसके खिलाफ एक ान लेंगे। अलबत्ता एक बात कहीं कहीं पर जरूर हुई है। कई जगह का मिट्टी दूर से उठाकर लानी पड़ती है जो कि हयूमैनली पौसीबल नही है। इसलिये यह हो सकता है कि किसी किसान के पास ट्रैक्टर हो, उससे मिट्टी डलवायी गयी हो और उसे पैसे दिये गये हो। जैसे मैने पहले कहा है कि कई जगह पर मिट्टी एक एक दो दो मील से उठाकर लानी पड़ती है तो कि एक गरीब

आदमी के लिये पौसीबल नही है। इसलिये कुछ मिट्टी ट्रैक्टरो से भी डलवायी गयी है।

श्री गुलजार सिंहः जैसे कि मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि गांवों के अंदर फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहक कच्चे रास्ते बिल्कुल कम्पलीट हो चुके है। उनको पक्का करने के लिये जिन पंचायतों के पास फन्डज नही है, उनको सरकार इमदाद देगी ताकि वे अपनी सड़कें पक्की करवा सके। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन पंचायतों को फण्डज देने का क्राइटेरिया क्या होगा, जिसके तहत वह उन्हें इमदाद देगी ?

राव राम नारायणः वहां का जो डिप्टी कमि नर होगा, वह उस पंचायत के रिसोर्सिज को मद्देनजर रखते हुए कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिये फण्डज की अलाटमैंट करेगा।

श्री फतेह चंद विजः मंत्री महोदय ने यह बताया कि लाल डोरे के अंदर 'अनाज के बदले काम' स्कीम के तहत जो कच्चे रास्ते बनाये गये है, उनको पक्का करवाने के लिये अगर पंचायतो के पास कम है, तो उनकी मदद की जायेगी। क्या मंत्री महोदय मैंचिंग ग्रांटस के रूप मे ऐसी पंचयतों को पैसा देंगे यानी जितना पेसा पंचायतें दे उतना ही पैसा सरकार उन को दे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंचिग ग्रांटस पंचायत फंड्ज के हिसाब से नही दी जा सकती। अगर सारे गांव वाले कुछ पैसे इकट्ठे करें तो सरकार उनको मैंचिंग ग्रांट दे

सकती है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पंचायतो के पास फण्डज नही है इसलिये वे कैसे काम करेंगी ? उसके लिये पंचायत महकमे के जो फण्डज है, वे हर ब्लाक मे पंचायत समितिज को डिस्ट्रिब्यूट किये जाते है। वह आगे गांव की इमदाद के लिये, चाहे वहां पर कुंए बनाने हों या गलियां करवानी हों, पैसा पंचयतो को देती है।

Quota of jobs reserved for Ex-Servicemen in the Cooperation Department

***1607. Chaudhri Partap Singh Thakran:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) the quota of jobs reserved for Ex-Servicemen in the services togetherwith the actual percentage of such personnel existing at present in the Cooperation Departement;

(b) the percentage of the quota referred to in part (a) above filled up in the Cooperation Departement through S.S.S. Board and the Public Service Commission from 1-4-79 to dat; and

(c) whether there is any deficiency in the percentage of Ex-Servicemen in the above said Departement; if so the steps taken or proposed tobe taken to make up this shortfall?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण की मात्रा निम्न प्रकार है:–

सीधी भर्ती द्वारा–

(i) 5 प्रति ात एवं द्वितीय श्रेणी के पदो में।

(ii) 20 प्रति ात तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के पदों में।

पदोन्नति द्वारा–

भून्य।

हरियाणा के गठन के प चात् मंजूर हुये पदों के विरूद्ध भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पद तथा उन पदो के विरूद्ध की गई भर्ती का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) 1–4–79 से आज तक एस.एस.एस. बोर्ड/लोक सेवा आयेाग के माध्यम से कोई भर्ती नही की गई है। इसलिये इस इस अवधि मे भूतपूव्र सैनिकों के लिये किसी कोटे की भर्ती का प्र न पैदा नही होता।

(ग) हरियाणा के गठन से लेकन भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रति ाता से अधिक हैं अतः इसमे कोई कमी नही है।

श्रेणी	1.11.22 के प चात् स्वीकृत हुए पद		भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने वाल पद		1.11.66 के प चात् भर्ती किये गये भूतपूर्व सैनिकों की प्रति ातता		कमी, यदि कोई हो
	पदो की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या	संख्या	प्रति ाता	संख्या	प्रति ातता	
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी–1	9			5 प्रति ात			भून्य
श्रेणी–2	12	8		5 प्रति ात	4	52 प्रति ात	भून्य
श्रेणी–3	485	354	71	20 प्रति ात	109	31 प्रति ात	भून्य

श्रेणी–4	78	78	16	20 प्रति ात	19	24 प्रति ात	भून्य
जोड़	584	440	87		132		भून्य

एक आवाजः स्पीकर साहबस, हमे तो सवाल का जवाब ही नही मिला है।

चौधरी राम लाल वधवाः सर, जवाब तो है लेकिन ये आगे पीछे लगे हुए है। मुझे तो इसको ढूंएने मे पांच मिलट लगे है। इस सवाल का जवाब सवाल नं. 1474 के बाद लगा हुआ है।

Mr. Speaker: I am sorry if any mix up has taken place. Replies were received late at night yesterday from the Government. But we will ensure that in future no such mistake occurs.

मैंबर साहेबान, यह कहावत है कि लड़ाई के दौरान सारी पब्लिक भगवान को और फौजियों को याद करती है और जैसे ही लड़ाई खत्म हो जाती है वैसे ही वह भगवान को भी भूल जाती है और फौजियो को भी भूल जाती है, मै इस बात के लिये अपनी गवर्नमैंट को मुबारिकबाद दूंगा कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन का पूरा ध्यान रखा है और कोटे से ज्यादा इन्हें दिया है।

एक आवाजः ये तो कहते है कि 1979 के आद कोई भर्ती ही नही की है।

श्री अध्यक्षः मैं तो सरकार की बात करता हूं कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन का पूरा ध्यान रखा है, इसलिये यह मुबारिकबाद की पात्र है।

चौधरी गंगा रामः मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता है कि सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंक, सोनीपत मे 15 एक्स सर्विसमैन जोकि गनमैन और चौकीदार की पोस्टों पर लगे हुए थे, इस सरकार ने उसकी सर्विसिज को टर्मीनेट कर दिया है, इसका क्या कारण है?

ठाकुर बीर सिंहः इस प्र न का इससे कोई ताल्लुक नही है क्योंकि डिपार्टमैंट का उससे कोई संबंध नही है। वहां पर पहले चौधरी गंगा राम जी चेयरमैन हुआ करते थे। इन्होंने जिस तरह से आदमी लगाये थे, उसी तरह से हटा दिये गये होंगे।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मैंने यह सवाल इसलिये पुछा है क्योंकि यहां पर कह रहे है कि हम एक्स सर्विसमैन की हिफाजत कर रहे है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन 15 एक्स सर्विसमैंनों को क्यों हटाया गया है, जिन्होंने 6 महीने तक नौकरी की हुई थी ?

श्री अध्यक्षः यह तो बैंक से संबंधित है, मगर मिनिस्टर महोदय इसका जवाब देना चाहे तो दे सकते है।

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, डिपार्टमैंट का इससे कोई ताल्लुक नही है।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, सवाल के जवाब मे यह कहा गया ळे कि प्रोमो ान के लिये कोई रिजर्वे ान नही है। जैसे कि दूसरी कैटेगरीज के लिये प्रोमो ान के लिये रिजर्वे ान है, वैसे ही एक्स सर्विसमैन के लिये भी रिजर्वे ान होनी चहिए। क्या सरकार एक्स सर्विसमैंन के लिये भी प्रोमोशन मे रिजवे ान करने के लिये विचार करेगी ?

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, प्रोमो ान के मामले मे कोई रिजर्वे ान नही है। जितनी भी भर्ती की गयी है, सारी डायरैक्ट की गयी है। जब उनका नम्बर सीनियरिटी के हिसाब से आये तथी उनको प्रोमो ान मिल सकती है।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि एक्स सर्विसमैन के मामले मे प्रोमो ान के लिये कोई रिजर्वे ान नही है। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि जैसे हरिजनो के लिये प्रोमो ान के मामले मे रिजर्वे ान है, उसी तरह से एक्स सर्विसमैन के लिये भी, जो दे ा के लिये मरते है, कोई रिजर्वे ान इन प्रोमो ान करने का विचार है ?

ठाकुर बीर सिंहः जी नही।

Mr. Speaker: Government instructions were put up to me कि ि ाडयूल्ड कास्टस के लिये क्लास थ्री और क्लास फार मे 20 प्रति ात रिजर्वे ान है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस सदन मे करीब सभी सदस्य अकसर एक बात डिस्कस करते है कि कोआप्रे ान डिपार्टमैंट के अंदर जितनी भी भर्ती होती है चाहे वह एक्स सर्विसमैन की हो या किसी दूसरी जाति की हो, एक्पलायमैंट एक्सचेंज के भारू नही की जाती। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इतनी इररैगुलैरिटीज की जाती है कि संडेज को लोगो को अपने घर बुलाकर चण्डीगढ़ मे मंत्री महोदय उनको अप्वायंटमैंट करवाते है। मेरे पास इस बात का सबूत है कि लड़कों को अपने घर बुलाकर अप्वायंटमैंट आर्डर्ज दिये जाने के बारे मे टेलीफोन किया जाता है ? (व्यवधान व भाोर)

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने सवाल उठाया है उसके बारे मे मैं यह कह दूं कि हमारे इस डिपार्टमैंट मे तीन एजेन्सीज है। (ाोर एवं व्यवधान)

Shri Surrender Singh: Speaker Sahib, I have the proof. Let the Minister deny. The hon. Minister is eveding the reply. (Interruptions)

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि इस डिपार्टमैंट मे तीन ऐजेंसीज है, जिनके जरिये हम भर्ती करते है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, एजंसियों की बात नही है। The hon. Minister is again evading the reply. (Interruptions)

Thakur Bir Singh: No, I am not evading the reply, (Interuupeions).

Mr. Speaker: This quetion refers to the percentage of reservation for Ex-servicemen.

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सब ********** का काम है। (ाोर एंव व्यवधान)

ठाकुर बीर सिंहः ******* तो स्पीकर साहब, इनके घर मे होती होगी। (ाोर)

Mr. Speaker: Next quetion, Shri Hira Nand Arya.

Shifing of Education Board of Bhiwani

***1471. Sh. Hira Nand Arya:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the entire Haryana Education Board has been shifted to Bhiwani; if not, the time by which it is lilely to be shifted; and

(b) whether the construction of Education Board Building has been started at Bhiwani; if not, the reasons therefor?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भाांति देवी):

(ए) ि ाक्षा बोर्ड की दो भााखाएं भिवानी बदली जा चुकी है, जिन्होंने 1—1—80 से किराये की इमारत मे कार्य भाुरू कर दिया है। कार्यालय तथा रिहाय ाी

स्थान की उपलब्धि और बोर्ड की अपनी इमारत पूर्ण होने पर समस्त कार्यालय भिवानी मे फेज्ड मैनर मे बदला जायेगा।

(बी) नही जी, सरकार ने वर्श 1976 मे बोर्ड के कैंपस के निर्माण हेतु भिवानी मे 113 एकड़ 6 कनाल, 16 मरले भूमि अभिग्रहण की थी। बोर्ड ने मुआवजे के रूप मे 968100 रूपये अदा किये थे। भूमि के मालिकों ने मुआवजे की बढ़ोतरी के लिये जिला जज भिवानी की अदालत मे केस दायर कर दिये है। अगर उनकी दलील स्वीकार हो जाती है तो बोर्ड को 5000000 रूपये की रा ि ा अदा करनी पड़ेगी। निर्माण कार्य को भ्ारू करने का मामला बोर्ड के विचाराधीन है।

डॉ. मंगल सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने अपने उत्तर मे बताया हे कि बोर्ड के कार्यालय ने 1—1—1980 से किराये की इमारत मे कार्य भ्ारू कर दिया है। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि जो भूमि बोर्ड की इमारत के लिये भी जानी थी, क्या उसका कब्जा सरकार ने ले लिया है, अगर कब्जा ले लिया है तो कब लिया है ?

*Expunged as ordered by the Chair.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जमीन एक्वारयर कर ली है और जमीन हमारे कब्जा मे आ गयी है। उस पर काम भुरू है, जब तक बिल्डिंग बन कर तैयार नही हो जायेगी तब तक बोर्ड का कार्यालय वहां पर नही जा सकता। जब बिल्डिंग बन कर तैयार हो जायेगी, एजुके ान बोर्ड का दफतर भिवानी मे ि ाफट कर दिया जायेगा।

डॉ. मंगल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया। मैंने इन से पूछा था कि जमीन का कब्जा कब मिला ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इस वक्त डेट तो हमारे पास नही है। जमीन का कब्जा हमने ले लिया हैं और एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा दे दिया गया है। कब्जे की डेट के बारे मे ये हमें लिखकर भेज दे, हम उनको बता देंगे।

डॉ. मंगल सिंहः स्पीकर साहब, भूमि के मालिकों ने मुआवजे की बढ़ौतरी के लिये अदालत मे केस दायर कर रखा है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बिल्डिंग का कार्य कब भुरू हुआ था और वह कब तक पूरा होने की आ ाा है?

श्रीमती भाांति देवीः स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि 20 जुलाई, 1977 को पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया कि एजुके ान बोर्ड का दफतर चण्डीगढ़ मे

ही रहना चाहिए। उसके उपरांत जब हमारी सरकार आई तो हमारी कैबिनैट ने 12–9–79 को यह निर्णय लिया कि एजुके ान बोर्ड का कार्यालय भिवानी के अंदर ही बदला जाये।

चौधरी हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया। मैंने यह कहा था कि इस बिल्डिंग का काम कब भ्रुरू हुआ था और कब तक यह बिल्डिंग बन कर तैयार हो तायेगी ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मैंबर को यह बताना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग के लिये 1976 मे जमीन एक्वायर की गई थी और उसके बाद बिल्डिंग का काम भ्रुरू हो गया था। जिस सरकार को मास्टर हुक्म सिंह जी स्पोर्ट करते थे और चौधरी देवी लाल जी उस सरकार के मुख्य मंत्री थे, यह काम उन्होंने अपने राज्य मे बंद कर दिया था और यह कह दिया था कि बोर्ड का दफ्तर भिवानी मे नही ले जाया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद फिर वह निर्णय लिया । बिल्डिंग का काम भ्रुरू कर दिया है। ज्यों ही बिल्डिंग बन कर तैयार हो जायेगी, बोर्ड का दफतर भिवानी मे चला जायेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, सरकार ने एजुके ान बोर्ड का दफतर और दूसरे कई बडे बड़े दफतरों को भी यहां से ि ाफ्ट करने के बारे मे निर्णय लिया है। क्या इन बड़े बड़े दफतरों को यहां से ि ाफ्ट करने से हरियाणा का जो चण्डीगढ़ के ऊपर एवार्ड का हक है वह खत्म नही हो जायेगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन दफ्तरो का वास्ता ज्यादा से ज्यादा फील्ड के लोगो से पड़ता है क्योंकि उन लोगो को छोटे मोटे कामों के लिये चण्डीगढ़ आना पड़ता है। जो जरूरी दफ्तर होंगे जैसे बिजली बोर्ड का दफ्तर है, सारा बिजली बोर्ड नही, कुछेक ब्रांचिज जिनसे लोगों को जरूरतों के मुताबिक जरूरी समझा जाएगा, उसको ही चण्डीगढ़ से ि ाफट किया जायेगा ताकि लोगो को छोटे मोटे कामों के लिये यहां न भागना पड़े। एजुके ान बोर्ड का वास्ता सारे प्रांत से है। भिवानी को इसके लिये सैंट्रल प्लेस समझा गया, इसलिये एजुके ान बोर्ड का कार्यालय, बिल्डिंग बनने के बादे भिवानी को इसके लिये सैंट्रल प्लेस समझा गया, इसलिये एजुके ान बोर्ड का कार्यालय, बिल्डिंग बनने के बाद भिवानी मे ि ाफट कर दिया जायेगा।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं मुख्य सचिव महोदया से जानना चाहता हूं कि क्यायह उनके नोटिस मे है कि बोर्ड की बिल्डिंग की तामीर का सामान जैसे लोहा, ईंटे, और दूसरी चीजे जो थी, उनको लोग उठाकर ले गये है। और उस सामान का काफी मिसयूज हुआ है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो बात अभी माननीय सदरू ने इस सदन के सामने कहीं है, उनहोंने पहले कभी हमारे नोटिस मे यह बात नही लाई। हम इस बात की जरूर जांच करवाएंगें अगर कही भी किसी ने तिनका भर भी उठाया होगा तो उस आदमी के खिलाफ एक ान लिया जायेगा। इसके अलावा मैं

एक बात बता देना चाहता हूं कि एक बात मेरे नोटिस मे अव य आई थी कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने जिस मे श्री हीरा नंद आर्य ओर मास्टर हुक्म सिंह जी भी मिनिस्टर थे, उस वक्त यह काम बंद करवा दिया था और सारे का सारा सामान किसी दूसरे महकमे को अलाट कर दिया था। फिर भी हम इस बात की जांच करवायेंगे कि अगर किसी प्राईवेट आदमी ने या किसी और ने वहां से सामान उठाया होगा, तो उसके खिलाफ अव य सख्त कार्यवाही की जायेगी।

चौधरी ई वर सिंहः स्पीकर साहब, ऐजूके ान बोर्ड को भिवानी मे ि ाफ्ट करने का हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। कुरूक्षेत्र हरियाणा की सैन्ट्रल प्लेस है, वहां पर यूनिवर्सिटी है, रेलवे स्टे ान है और वह जी.टी. रोड़ पर भी है। इन सारी चीजो को देखते हुए वहां पर राजधानी बनाने पर विचार किया जा रहा है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन सारी चीजो को देखते हुए ऐजुके ान बोर्ड के दफ्तर को कुरूक्षेत्र ले जाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्षः मैं इस बारे मे कहना चहूंगा कि 1977 मे जब मैं ि ाक्षा मंत्री था तो चौधरी देवी लाल ने सलाह दी थी कि ऐजूके ान बोर्ड की बिल्डिंग पीपली मे बननी चाहिए।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ऐजूके ान बोर्ड को भिवानी मे ि ाफ्ट करने का फैसला हो चुका है, अब इसको चेंज करना सम्भव नही है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, कई बार क्वे चन आवर मे और डिबेट मे यह सुनने को मिलता है कि भिवानी से उठाकर फलां बिल्डिंग का सामान ले जाया जा रहा है। ठाकुर बीर सिंह और चौधरी भजन लाल इस बात को मानते हैं कि चाहे हौस्पिटल की बिल्डिंग का हो, चाहे कोई और बिल्डिंग का हो, कुछ भी सामान हो, भिवानी से उठकर जाता रहा है। सीपकर साहब, भिवानी के लोगो को फीलिंग को देखते हुए क्या चीफ मिनिसटर साहब यह अ योंरें ा देने की कृपा करेंगे कि ऐजुक ेान बोर्ड की बिल्डिंग भिवानी से नही ले जाई जायेगी ?

Mr. Speaker: The Hon'ble Chief Minister has already assured the House that the Eudcaiton Board will shift to Bhiwani.

श्री भले रामः स्पीकर साहब, पिछली बार चौधरी ई वर सिंह ऐजूके ान बोर्ड के चेयरमैन थे। हाई कोर्ट ने उस वक्त फैसला किया था कि इस बोर्ड का चेयरमैन ग्रैजुएट होना चाहिए लेकिन चौधरी ई वर मैट्रिकुलेट थे। क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेगें कि उन्होंने इसी वजह से इस बोर्ड की चेयरमैनि ाप से इस्तीफा दिया था ?

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नही है।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, अभी चीफ पार्लियामेटरी सैक्रेटरी साहिबा ने कहा था कि भिवानी मे काम बंद है और मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर काम चालू है। क्या मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर काम चालू है। क्या मुख्य मंत्री बताने की कुपा करेंगे कि, बोर्ड की बिल्डिंग की कंस्ट्रक ान का काम जो छत तक हुआ पड़ा है और अब बंद है इस काम को किस तारीख से भाुरू कर देंगे और बोर्ड को किस तारीख तक भिवानी मे ि ाफ्ट कर देंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मंत्री महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और ऐजूके ान बोर्ड की बहुत ज्यादा पब्लिक के साथ डीलिंग्ज है इसलिये उनको हरियाणा के मध्य मे ि ाफ्ट किया जा रहा है। क्या मुख्य मुत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के लोगो की हरियाणा सिविल सैक्रेटेरिएट से बहुत ज्यादा डीलिग्ज है क्या इसको भी कही सैंट्रल मे ले जाने का सरकार का वचिा है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर सहाब, मैंने यह नही कहा था कि सारे बिजली बोर्ड को हिसार ले जायेंगे। मैंने यह कहा था कि बिजली बोर्ड का कुद अं ा जिसके साथ हरियाणा की जनता की बहुत ज्यादा डे टू डे डीलिंग्ज है, उसको वहां पर ि ाफ्ट करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुमेर चंद भट्टः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पालिटीकल या ऐडमिनिस्ट्रटिव कौन से वजुहात थे जिनकी वजलह से पिछली सरकार द्वारा सब जगहो को छोड़ कर ऐजूके ान बोर्ड को भिवानी ले जाने का फैसला लिया गया था क्या आज ही सरकार उन सभी वजुहात से सहमत हे जिनकी वजह से ऐजुके ान बोर्ड को भिवानी मे ि ाफ्ट करने का फैसाला किया गया था ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं समझता हूं चूंकि सै ान समाप्त होने जा रहा है इसलिये मैंबर्ज साहेबाल ज्यादा उत्साहित हो रहे है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा डिस्पिलन रखे और हाउस मे भाांति बनाए रखे।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इस बात का फैसाल बड़े सोच विचार के बाद किया गया थाि क ऐजुके ान बोर्ड का दफ्तर भिवानी ि ाफ्ट किया जाये ओर यह फैसला आज का नही है, बहुत पहले का है। इसके लिये जमीन 1976 मे एक्वायर की गई थी और पैसा दे दिया गया था। तकरीबन इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इस बोर्ड को भिवानी ले जाने का फसला अटल है ओरइसमे कोई तबदीली करना सम्भव नही है।

Tanneries at Jind

***1514. Chaudhri Satvir Singh Malik:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whethe the Tanneries at Jind has run in frofit during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80 (upto 31st December, 1979); if so, the profit earned separately;

(b) if reply to part (a) be in the negative the loss suffered during the period mentioned in part (a) above together with the steps; if any, taken or proposal tobe taken ot make the said Tanneries a profitable venture;

(c) the categroywise total number of technical/non technical eployees working in the said Tanneries along with their of pay, separately; and

(d) the total number of employees out of those mentioned in part (c) above belonging to Scheduled Castes?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नही।

(ख) वर्श हानि (रूपये लाखो में)

1977—78	34.67
1978—79	42.52
1979—80	32.65

(31 दिसम्बर, 1979 तक)

राज्य सरकार ने हरियाणा टैनरीज की लाईसैंस क्षमता 2000 सकिन्ज प्रतिदिन से बढ़ाकर 5000 सकिन्ज प्रतिदिन करने के लिये भारत सरकर को अनुरोध किया हुआ है जिसकी स्वीकृति होने पर यह यूनिट वायेबल हो सकेगी। इसके अतिरिक्त भार लैदर कार्पोरे ान, जो भारत सरकार का उपक्रम है, को इस यूनिट की टैक्नो इकनोमिक वायेबिल्टी स्टडी सौंपी हुई है। उनकी रिपोर्ट भीघ्र प्राप्त होने की आ ाा है जिसके उपरांत वांछित आगामी कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार भी कम्पनी को वित्तीय सहायता देने के बारे विचार कर रही है।

(ग) तकनीकी गैर तकनीकी

74 45

एक सूची जिसमे तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियो की वर्गानुसार ब्रक अप तथा उनके वेतनमान दिये है, सदन के पटल पर रखी जाती है। (अनुबंध 'क')

(घ) तकनीकी गैर तकनीकी

24 5

अनुबंध ''क''

हरियाणा टैनरीज मे 28–2–1980 तक काम करने वाले कर्मचारियो की वर्गानुसार सूची।

क्र. संख्या	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान	पिछड़ी जाति की संख्या
1	2	3	4	5
तकनीकी स्टाफ				
1	जनरल मैनेजर	1	रू. 2000-100-3000	
2	वर्कस मैनेजर	1	रू. 1500-2000	
3	सहायक मैनेजर	2	रू. 400-1100	
4	सहायक फोरमैन	3	रू. 250-500	
5	मैकेनिकल फोरमैन	1	रू. 225-500	
6	म ीन ओपरेटर i) ग्रेड–ए	6	रू. 160-400	

	i) ग्रेड–बी i) ग्रेड–सी	1 4	रू. 110-225 रू. 90-140	
7	कलर सिक्सर	1	रू. 125-500	
8	वेलडर	1	रू. 200-400	
9	इलैक्ट्रि ियन कम मैकेनिक	1	रू. 200-400	
10	इलैकिट्रकल वाटर हैल्पर	2	रू. 200 रू. प्रति माह (फिक्सड)	
11	सैमी सकिल्ड वर्कर	35	रू. 200 रू. प्रति माह (फिक्सड)	
12	सैमी सकिल्ड वर्कर	9	रू. 185 प्रति माह	22
13	सलैक्टरज	2	रू. 160-400	22
14	पम्प आपरेटर	1	रू. 100-160	
15	वर्क मिस्त्री	1	रू. 100-160	

16	बोआयलर अटैंडेन्ट	1	रू. 160-400	
17	वायरमैन	1	रू. 90-140	
नान तकनीकी स्टाफ				
18	प्रबंधक निदे ान, आई.ए.एस.	1		
19	वित्तीय नियंत्रक	1	रू. 1500-2000	
20	मारकीटिंग मैनेजर	1	रू. 1100-1600	
21	सहायरक मारकीटिंग अधिकारी	1	रू. 225-500	
22	स्टोर प्रचेज अधिकारी	1	रू. 225-500	
23	सहायक स्टेर अधिकारी	1	रू. 225-500	
24	स्थापना सहायक	1	रू. 225-500	
25	सहायक लेखाकार	3	रू. 225-500	
26	स्टैनोग्राफरज	2	रू. 225-500	

27	क्लर्कस (i) अकाउंटस क्लर्क (ii) बिक्री क्लर्क iii) जनरल क्लर्क	 3 3 7	 रू. 110-225 रू. 110-225 रू. 110-225	
28	स्टोर कीपर	2	रू. 160-400	
29	ड्राईवरजर	2	रू. 130-200	1
30	सेवादार	7	रू. 75-95	1
31	कुक कम चौकीदार	1	रू. 110-225	
32	स्टोर अटैंडैंट	1	रू. 75-95	
33	स्वीपर	2	रू. 75-95	2
34	स्कीयोरिटी होलदार	1	रू. 125-250	
35	चौकीदारज	4	रू. 75-95	1
	जोड़:	119	जोडः	29

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः स्पीकर सहाब, जैसे कि जवाब के पार्ट 'बी' से पता चलता है कि यह कम्पनी लगातार तीन साल से घाटे मे चल रही है और अगर आप इसका अनैक चर 'क'

देखे तो उसमे बहुत सारे टैक्नीकल आदमी दिखाए गए है जो इसटैनरी मे लगे हुए है। जब इनको दो हजार स्किन की बजाए पांच हजार स्किन का लाइसैंस नही मिला है तो इतनी भारी संख्या मे आदमी क्यों लगाए हुए है ? इसलिये जो फालतु आदमी लगे हुए है क्या उनको कम करने पर विचार करेंगे ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इस टैनरी मे जितने आदमियों की आव यकता थी उतने ही रखे गये है। इस टैनरी मे कुल 119 आदमी कामकर रहे है। इसमे कोई दो राय नही है कि यह टैनरी घाटे मे जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वक्त इसकी क्षमता दो हजार स्किन की है और हमने इसकी क्षमता बढ़ाने के लिये भरत सरकार को रिकवैस्ट की हुई है लेकिन वह मानी नही। पिछले दिनों हाल ही मे भारत सरकार ने इंडस्टरी मिनिस्टर चालना साहब आए थे उनके साथ इस संबंध मे हमारा विचार विम र्ा हुआ था और उन्होंने हमे आ वासन दिया है कि इसकी क्षमता बढ़ाने की इजाजत जरूर दे देंगें हमे ज्यौं ही पांच हजार स्किन की इजाजत मिल जायेगी यह टैनरी प्रोफिट मे चलने लग जायेगी और जितने स्टाफ की जरूरत होगी उतना ही रखेंगे।

श्री मूल चंद मंगलाः अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इसकी कैपेसिटी दो हजार से पांच हजार करने जा रहे है। मैं पब्लिक अंडर टेकिंग्ज कमेटी का मैंबर रहा हूं और हमने उस टैनरी का निरीक्षण किया था। उसका घाटे मे जाने का कारण यह भी है कि उनको मार्किट रेट से 15 रूपये फी खाल ज्यादा देनी

पउ़ता है। इस वजह से उसमे लाखो रूपये का घाटा है। तो यह जो एकस्ट्रा पैसा देने पड़ता है उस पर नियंत्रण लगाने की कोि ा ा करेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चमड़े का कोई कन्ट्रोल नही है लेकिन पैसे के अभाव के कारण इसका काम ठीक तरीके से नही चल रहा है। सरकार ने अब फैसला किया है कि इस टैनरी को 25 लाख रूपये और दिया जाये, जिसे हम बहुत जल्द देने जा रहे है।

चौधरी पीर चंदः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि टैनरी मे घाटा इस वजह से भी है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कर्मचारी भी लगे हुए है जो इस काम से नफरत करने वाले है और उनकी इस काम मे कोई दिलचस्पी नही है ?

चौधरी भजन लालः इसमे जितनी हरिजनों की रिजर्वे ान होनी चाहिए उससे कम नही है बल्कि एक दो आदमी ज्यादा है । जैसे पार्ट 'डी' मे जवाब दिया गया है 119 आदमियों मे से 29 आदमी ि ाड्यूल्ड कास्टस के है। इनमे 24 टैक्नीकल है और 5 गैर टैक्नीकल है।

श्री लहरी सिंह मेहराः क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि इस टैनरी मे इसा वजह से तो घाटा नही है कि वहां सिर्फ छोटी स्किन्ज का परमिट है और वह हमें हरियाणा के बाहर से खरीदनी पड़ती है। अगर वहां पर बड़ी स्किन का परमिट

मिल जाये तो वह बड़ी स्किन हरियाणा मे मिल सकती है और उसका पूरा यूटिलाइजे ान भी हो सकता है। अगर इस वजह से घाटा है तो कया इसको दूर करने की कोि ा ा करेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी बताया कि 6'7 दिन पहले चानना साहब यहां आये थे। उनके साथ हमने डिटेल से डिस्क्स किया है और उन्होंने हमें वि वास दिलाया है कि वे पांच हजार स्किन की कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत दे देंगे। इससे ज्यादा पैसा भी खच्र होने वाला नही है क्योंकि साढ़े तीन हजार की कैपेसिटी की म ाीनरी तो वहां पहले ही लगी हुई है और केवल डेढ़ हजार की कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। जब पांच हजार की कैपेसिटी हो जायेगी तो मेरा ख्याल है स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा। पांच हजार की क्षमता होने के बाद इसकी एक तरह से अढ़ाई गुना क्षमता बढ़ जायेगी और यह यूनिट बिल्कुल वायएबल होगी।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इस तरह की कंसर्नज या कार्पोरे ांज है जिनमे घाटा है, इनमे चेयरमैन लगाए हुए है। अगर इनमे मैनेजिंग डायरैक्टर कम चेयरमैन कर दिये जाये, उससे कुछ न कुछ घाटा कम हो सकता है तो क्या इस बात पर विचार किया जायेगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन लगाने से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है मामूली सा अंतर पड़ता है। लेकिन जो पब्लिक का आदमी होता है उसको पब्लिक के सामने जवाब देना पड़ता है इसलिये हमने उनको सोच समझ कर लगाया है ताकि वे भी देखें कि इंडस्ट्रीज किस प्रकार से ठीक तरीके से चल सकती है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने फर्माया कि 1977–78 मे इस टैनरी मे 34.67 लाख का? 1978–79 मे 42.52 लाख का और 1979–80 मे दिसम्बर 1979 तक 32.65 लाख रूपये का घाटा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1977.78 मे और 1978.79 मे इस कंसर्न का चेयरमैन का काबलियत के कारण बढ़ा और उस चेयरमैन का नाम क्या था ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस कंसर्न के चेयरमैन उस समय चौधरी भले राम जी थे। इस घाटे के लिये मैं भले राम जी को दोश नही देता। इसलिये नही देता कि किसी यूनिट की जब तक क्षमता नही बढ़ाई जायेगी तब तक वह फायदे मे नही जा सकती, चाहे कोई भी चेयरमैन रहे। हां लाख दो लाख का फर्क पड़ सकता है भले राम जी की वजह से घाटा हुआ ऐसी बात नही है।

स्थागित तारांकित प्र न एंव उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I now take up postponed starred quesiton No. 1490 by Capt. Mange Ram जिसके लिये गवर्नमैंट ने दस दिन का टाईम मांगा था जो पूरा हो गया है।

Reservation of posts for Ex Servicemen

***1490. Capt. Mange Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the quota of posts reserved for ex servicemen in the matter of recruitment/promotion in various Government Depatments has been adhered to according to Government instructions; and

(b) if reply to para (a) above be in the negative, the names of the Departments where the Government instructions regarding reservation of posts referred to above have nt been complied with and the steps taken or proposed to be taken to ensure that these instructions are strictly complied with?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) और (ख) इस समस सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदो के लिये भूतपूर्व सैनिको के लिये कोटा 20 प्रति ात (श्रेणी III और श्रेणी IV के लिये) और 5 प्रति ात (श्रेणी I और श्रेणी II के लिये) आरक्षित हैं यह प्रति ातता अध्कितर अवसरों पर प्राप्त करना सम्भव नही हो सका है क्योंकि निर्धारित योग्यताएं रखने वाले भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध नही हुए

है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने मई, 1979 मे यह निर्णय लिया कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों और पुत्रियों को भी–जो विभिन्न पदों के लिये निर्धारित योग्यताओ, आयु आदि की सारी भार्ते पूरी करते हो–भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों के लिये गुणों के आधार पर विचारा जायेगा । यह हक केवल एक आश्रित बच्चे के लिये उपलब्ध होगा। आ ाा है कि इस ढील के फलस्वरूप भविश्य मे पहले से अच्छे परिणाम उपलब्ध होंगे।

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, अब क्वे चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित

प्र नों के लिखित उत्तर

The Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979

***1657. Shri Mook Chand Jain:** Will the Minister for Finance be plaesed to state—

(a) the on which the Haryana Taxation (On Certian Goods Carried by Road) Ordinance, 1979 was promulgated, and withdrawn;

(b) the total amount of income accrued to the State as as result of the promulgation of the Or4diance as referred to in part (a) above; and

(c) whether any representations were received againt the Ordinance after 26th may, 1979; if so, copies of the representations received after 26-5-79 be place on the Table of the House?

वित्त मंत्री (लाला बलवंत राय तायल):

(क) हरियाणा काराधान (कुछ वस्तुओ के सड़क मार्ग द्वारा वहन पर) अध्यादे I, 1979 दिनांक 21—4—79 से लगाया गया था औरी 21—7—79 को वापिस ले लिया गया था।

(ख) 5215052 रूपये।

(ग) जी हां, 26—5—79 के बाद 10 प्रत्यावेदन प्राप्त हुये थे जिनकी प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

Representations		
Details of the ten representations received after 26-5-79 against Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979.		
Sr. No.	No. and date of representation/letter	Source from which recied
1	Letter No. a/79/405 dated 30-5-79	Smalkha Industries Association Smalkha, Distt. Karnal.
2	Letter No. GTM/Sales Genl., dated 1-6-79	Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore.

3	Letter No. FIA/79/582 dated 5-6-79	Faridaba Industries Association Industries Area, Faridabad.
4	Letter No. 8106, dated 15-6-79	The Altas Cycle Industries, sonepat.
5	Letter No. MSL/ED, dated 22-6-79	Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore.
6	Letter No. FIA/79/661 dated 27-6-79	Faridabad Industries Association, Faridabad.
7	Letter No. FIN/56/5025 dated 11-7-79	Chairman, Haryana Affairs Committees, Punjab Haryana and Elhi Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.
8	Letter No. FIA/79/818, dated 25-7-79	Faridaba Industries Association, Faridabad.
9	Letter No. Nil, dated 3-8-79	Remington Rand Of India Ltd., Mathura Road, Faridabad.
10	Letter No. PK, dated 9-8-79	Hindustan Milk Food Manufactures Ltd., Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

Copy of Letter No. a/79/405 dated May 30, 1979 from Smalkha Industries Association, Samlkha, Distt. Karnal addressed to the Hobourable Finance Minister, Haryana, Chandigarh.

Sub. :- **Examption of Road Tax on Chaf Cutters.**

Sir,

With due regards we bring it to your kind knowlege that only from the last one week Haryana, Delhi sales tax barried has started charging 1% road tax even on Chaff Cutters.

We may submit that our product i.e. Chaff Cutter or toka is not a machine but an agricultural implement exdmpted from all sorts of central or state sale tax or any other duties.

We have to face a vest competition with Punjab which is the origin and biggest market of Chaff Cutters. So, yuour goodself is requested to please issue directives for necessary clarification to the check of posts.

Thanking you very much,

Sd/-

President,

Samalkha Indus. Association,

Copy to

(1) Excise and Taxtion Commissioner,

Haryana Chandigarh,

HINDUSTAN MACHINE TOOLS LTD.,

MACHINE TOOLS DIVISION,

PINJORE 134101

DISTT. AMBALA, INDIA

Date 1st June, 1979

Ref. GTM/Sales Genl.

The Secretary,

Government of Haryana,

Chandigarh.

Kind Attn: Mr. B.S. Ojha Hom Commissioner.

Dear Sir,

Sub: Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979.

Kindly refer to the discussions we had with you on 31st may, 1979 on the above subject. During our meeting we explained you that following:-

(i) We are manufacturers of sophisticated machine tools and agricutural tractors.

(ii) Our is a multi unit organisation with factories spead all over the country.

(iii) The terms of payment are uniform for goods from our all the units.

In view of the imposition of road tax by Haryana Government, in addition to the procedural difficulties since

the additional levy has to be borne by us, our competitivencess in the market has been adversely affected.

About 25% of our machine tools are exported, where to enable us to meet with the international comptition, we have to sell preactically without any profit margin.

We also explained to you the operational difficulties of payment of this levy. We have given fair during the month of May, 1979 and find that:-

(i) Handling of huge amount of cash is leading to obvious difficulties.

(ii) Although the despatches by Rail are exampt from this levy. We are still forced to pay this levy since the nearest development rail head for us happeins to be Chandigarh. As it was not practicable to develop the loading facilities at Kalka, we have during the cource of last 16 years developed facilites at Chandigarh Railway Station.

(iii) Since the export of goods does not attract any other inland tax, this leavy does not appear to be justified.

In view of the facts explained, we request yo to kindly consider the full withdrawal of this levy and pending the decision on this, we request you to permit us atleast the following:-

(i) Deduction of the levy at source and permission either fro pre payment or post payment.

(ii) Permission to operate all our rail traffic from Chandigarh Railway Station without attracting this levy.

(iii) Full withdrawal of this levy from all our export consignment and refund of the levy already paid on exports consignments.

Hopping for favouable consideration and thanking you.

Yours Faithfully,

for H.M.T. Ltd.

Sd/-

(G.N. Srivastava)

General Technical Manager.

Copy of letter No. FIA/79/582 dated 5th June, 1979 from Faridaba Industries Association, Bata Chowk, Industries Area, Faridabad-121001, addressed to Shri Mool Chand Jain, Hob'ble Finance Minister, Government of Haryana, Chandigarh.

Dear Sir,

We confirm having sent the following telegram:-

"Goods carried by Railway containers being taxed unde rthe Road Ordinance (.) These containers' goods moving under Railway receipts which are exempted under Ordinance

(.) Kindly instruct local officials not to tax Railway containers'goods"

As you are kindly aware, the Government of Haryan introduced an Ordinace under the name and style Haryana Taxation (on certain goods carried by roads) Ordinance, 1979. Under this Ordinance, certain goods that are coming in and going out by roads are being taxed as per the schedule appended with the Ordinance. The object of the Ordinance, if I am permitted to say so, is to tax the goods that are being cerried by road and there is an express provision in the Ordinace exempting the goods that are being carried by Railway or Airways.

As ou are kinly aware, the Northern Railway is operating containers service from Delhi, sicne the Central Railway has not introduced containes service at Faridabad. The Northern Railway usually sends the empty containers to Faridaba for taking the manufacturered goods int he containers for onward despatches to the various destinations spread thoughout the length and breadth of the country. In point of fact, the factories are getting cleared Railway Receipts Ex-Faridabad to various stations issued by the Northern Railway. The system is some what like out Agency system is being operated by the Railway by which the Railways use to give Railway tickets which is valid for movemnet by roads also. The local authority are taxing such containes' goods under the above Ordance which is a clear negation of the Ordianance. The Committee of the Association, therefore earnestly request you to kindly instruct the officials not to tax such containers'

goods moved by the Railways, as it is the property of the Railways.

While on the subject, some factories are exporting their goods to foreign countries and these goods are also covered under this Ordinance. You will being appreacitate that even under the Cental Excise law the goods that are being exported to foreign countries are exempted from the operation of the Centaral Excise Tariff. A similar provision should also be introduced in this Ordinance, as the goods that are being exported to foreign countries have to face a staff competition in the foreign marked.

A benign response is solicited.

Thanking you,

Yours faithfull,

Sd/-

(K.C. MAYOR)

President,

THE ATLAS CYCLE INDUSTIES LIMITED

Registered Office: Atlas Nagar, Atlas Road, Sonepat.

Post Box No. 20,

SONEPAT-131001

(Haryana)

INDIA.

India's Largest Producer of Quality Bicyles.

AUTO CYCLE DIVISION

Ref. No. 1806 15-6-1979

Excise and Taxation Commissioner,

Haryana, Chandigarh.

Dear Sir,

Sub:- Ordinance imposing tax on mopeds despatched by road outside Haryan.

We beg to invite your kind attention to the Ordinance No. 2 of 1979 dated 21-4-79 as subsequently amended by notification No. S.O.63/H.O.2/79/S.5/79 dated 26-5-79 and No. S.O. 64/H.O.2/79/S.3/79 dated 26-5-79* imposing fresh levy of goods tax on certain items going out of the State of Haryana. Under this Ordinance mopeds have been subjected to this tax @ Rs. 5/- per moped.

2. Obviously, this measure gives final shape to the following observation made by the Finance Minister, Haryana while presenting the budget estimates of the State for the year 1979-80:-

> "Haryana was facing another serious problem of tax evasion since long. Many industrialists, having their industries in Haryana have kept their head officers outside Haryana, especially in Delhi, Their factories produced goods in Haryana but their goods were not shown as sold here. These were and are transferred to Delhi and there as the rate of central sales tax is also much lower in Delhi. Haryana is thus deprived

of crores of rupees of central sales tax every year besides loss in its share of income tax. Besides repreated attempts these industrialists have failed to shift their head officers to Haryana".

3. In this connection, we wish to submit that our registered office is situated at sonepat and we do not have any saled depots anywhere outside the State. We do not make any stock transfers at all outside Haryana. All the sales effected by us attract either local sales tax or central sales tax which go to the coffers of Haryana State.

4. Our mopeds, therefore, suffer double taxation one in the form of central & local sales tax and again new goods tax. Obviously, this was not the intention of the State Government as is abundantly borne out by the above statement of Finance Minister, Haryana.

5. At the time of presenting Finance Bill, 1979 to the Parliament (now enacted Finance Act. 1979), Deputy Prime Minister and Finance Minister had, inter alia, stated:-

".....Mopeds which are used by comparatively less affluent people and consume less fuel, will bear a lower duty of 10 % as against existing rate of 13.1 %."

Thus keeping in view that mopeds were used by the lower middle class the Central Government has not only not increased excise duty on moped, but has reduced it by 3.1 %.

6. The recent steep increase in the steel prices and the rubber products like tyres and tubes has already dealt a

crippling below to the moped industry. Moped is used by relatively less affluent section of the society. Use of moped deserved encouragement by lowering taxes instead of making ghis item more expensive by imposing fresh levies.

7. It is just possible that some other manufacturers of vehicles included under item 19 of the Sechedule viz. motor cycles, scooters, mopeds, auto rickshaws withing the State of Haryana might be tranbsferring their goods to their head offices, sub offices or sale depots in other States. There may be justification in levying goods tax in such cases as also annuouced by the Finance Minister, Haryana. But we submit that in our case where we are aaying full central sales tax whenever our goods go out of the State of Haryana, leavying of goods tax is not equitable. We would request that t6he Ordinance may please be amended suitably to provide that in cased where in respect of itemes going out of the State of Haryana, Central sales tax has already been paid, no goods tax under this Ordinance will be leavied. Such a povision, while safeguarding against double taxation, will ensure that the loophole in taxation is suitably plugged in other cased where central sales tax has not been paid.

8. We in Sonepat ahve also to compete with moped industry in Ludhiana. Punjab Government has not levied any goods tax on such vehicles going out of the State of Punjab. We are, therefore, placed in a very unenvaible and uncompetitive position vis a is our competitiors in the negibhbouring States.

9. We, therefore, reqduest that the matter may please be given sympathetic consideration and that the

Ordinance may be suitable amended to ensure that either central sales tax is paid or goods tax is paid whenever the specified goods hleave the border of Haryana State, but not both.

Thanking you,

Yours faithfully,

for THE ATLAS CYCLE INDUSTRIES LTD.

Sd/-

Copy of letter No. MSL/ED dated 22nd June, 79 from HINDUSTRAN MACHINE TOOLS LTD. Machine Toolds Division, Pinjore, Distt. Ambala, addressed to the Excise & Taxation Commissioner, Government of Haryana, Sector-17, Chandigarh.

Dear Sir,

Sub:- Haryana Taxation (on certain goods carried by road) Ordinance, 1979.

This is to thank you for the countesies extended to the undersigned during his visit to your office on 18th June, 1979. During our discussions, we had explained to you the difficulties faced by HMT in view of the above tax imposed by the Haryana Govt.

2. We understand that Government is presently contemplating to exempt such goods from this tax which are

carried by road and on which Central Sales Tax has already been paid.

3. Export of goods does not attract any other inland tax like Central Excise Duty and Central Sales Tax. Goods exported by us are sealed by the Central Excise Department at our premises before despatch by road to various Indian ports for onward shipment for export. We request that such goods should also be exempted from road tax even thought no CST is paid on the same.

We request you to kindly consider the full withrawl on this leavy on both inland and export despatches and pending dicision on this, we request you to permit us at least for the following:

(i) Deducation of this levy at source and permission either for pre payment or post payment.

(ii) Permission to operate all our rail traffic from Chandigarh Railway Station without attracting this levy.

Yours faithfully,

for H.M.T. Ltd.,

Sd/-

(Chandra Parkash)

Manager Sales.

Copy of letter No. FIA/79/661 dated 27th June, 79 from FARIDABAD INDUSTRIES ASSOCIATION. Bata Chowk, Industrial Area, Faridabad-121001, addressed to Shri Sajjan Singh, Dy. the Excise & Taxation Commissioner, Government of Haryana, Chandigarh.

Sub:- Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979. levy of tax on Railway container goods thereunder.

Dear Sir,

Please refer to your letter No. 2012 dated 25th June, 1979 addressed to Shri Autar Singh, the former President of the Association. In this connection, we are sending enclosed a letter addressed to the Hon'ble Finance Minister, Haryana detailing the hardship that will ensure to the industries, in case the tax is imposed on the goods that are being carried by the Railways by road movement in their containers.

While on the subject, we with the inform you that the Local Excise & Taxation authorities are interpreting the Ordinance for imposing tax on the cuttingt tools namely Hacksaw Blades, Slitting Saws, Slotting cutters and Tool Bits etc. The above items are clearly exempted from the purview of the road tax Ordinance. But the locka Excise authorities are including these items under schedule No. therefor, request you to kindly issue suitable instructions to the local Excise staff not to tax to kindly issue suitable instructions to the local Excise staff not to tax cutting Tools such as Hacksaw Blades, Sliting Saws, Slatting cutters and Tool Bits etc. falling under traiff Item 51 A of the Central Excise.

It is in this regard, it may be stated that the Government by a Notification have regard, it may be stated that the Government by a Notification have removed certain items from the Schedule on 26the may. 1979. By the above Notification textiles have been removed from the schedule.

Some members who have paid the road tax till the removal of the item from the schedule are now approaching the Association for the refund of their money given by them as tax to the Govt. It is a genuine request and as you are aware, any bad law is bad from the inception. We, therefore, request you to kindly consider these cases sympathetically and issue favourable order for refunding the amount collected from such factories.

You beingn response is solicited.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/-

(G.C. NARNG)

Hony. General Secretary.

Encl: As stated

Copy of memo No. Fin/56/5026 dated 11th July, 1979 from Chairman, Haryana Affairs Committee, Punjab-Haryana and Delhi Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.

Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by

Road) Ordinance, 1979.

The Haryana Taxation (on certain goods carried by road) Ordinance, 1979. was promulgated on 21st April, 1979 to provide for the levy of a tax on certain goods, listed in the Ordinance carried by road while leaving the State of Haryana and for certain connected matters.

The idea originally to impose this tax was that stock transfer should be discouraged and revenue due to the State Government thus escaping should be plunged. However, the Ordinance has gone beyond this idea and covers certain specified goods, irrespective of the fact whether any stock transfers involved or not. The Ordiance as it stands will have numberous ill effects and disadvantages to industry in Haryana.

1. Economic Viability

This new tax, as envisaged, will affect the economic viablility of many industrial units and trade enterprise in the State, which would be neither in the interest of the State or that of the affected units.

Haryana is the lonely State which has put up such a barrier tax. It is a small State with limited consumption. Industry in Haryana has, therefore, necessarily to sell its products outside the State in competition with its counterpart in other States where there is no such lev. This will make Haryana industry's products uncompetitive thus affecting sales.

The State has a surplus production for various items enummerated in the schedule of the Ordinance. Being situated in proximity to Delhi sold mostly in these neighbouring States. The increase in cost of such items due to the levy of the above tax will thus affect all industry and distribution trade.

2. Ancillary Industry

It would be agreed that industry in Haryana is in a developing statge and has yet to come of age. In such a formative stage, it needs on the countrary, all the encouragement and incentives for growth and development. The character of industry in Haryana is mainly one of small scale acting as ancillary units to large/medium industries iocated outside the State, as Haryana inself has not very masny large industries to forster the culture of ancillarisation. As it is, the shortage of essential raw material and their current high prices are causing innumberable difficulties and problems to ancillary industry. The new levy will add to their problems and act as a major deterrent to further ancillary growth in the State.

3. Transport Business

This tax is chargeable at the barriers in the State. This will greatly effect transport business, for it is well known that these barriers act as great bottlenecks in the speedy movement of goods from state to State and cause immense damge to the efficiency of read vehcles. It is for this reason that discontinuance of octoi is being contemplated. Instead of helping in the direction of reducing delays and waiting time of

vehicles, the present levy, on the countrary, will multiply the problems of the business community.

4. Double Taxation

Ambiguity, in the definition of the term, "Goods" in the Ordinance has often led to double taxation. In certain case, some unfinished material has to be sent outside the State for further processing. After processing these materials are returned to the manufactures in the State for finishing or assembly purposed and then despatched out of the State. In each of these cased, when sent for processing/assembly or as finidhed goods, the tax is levied, leading to double taxation.

5. Anomalies

Moreover there are serval complications with regard to the working out of this Tax:-

(a) In case of heavy consignments, valuing lakhs of ruppees, the tax payable at the barriers will exceed Rs. 2500/-. As per Income Tax Act, industrial unit, concerned make any payment exceeding Rs. 2500/- in cash.

(b) The tax is payable at the inter state barriers and hence the industry concerned will have to give cash to the truck driver or depute their representatives to the barriers, for making the payment. In cases where numerous consignments are despatfhed daily, it is not possible to know as to when the trucks will reach the inter state

barriers. It is also not safe to give large sums of money to truck drivers.

(c) As no detailed drfinition of the term “Goods” in the schedule attached to the Ordinance has been given, it is difficult to classify as to what item is liable to tax. For example, no definition of machine and machine tools has been given. Moreover spares/machinery parts etc. are also being taxed at the barriers becouse normally transporters are illiterate and cannot give necessary clearification. In addition to this, this tax is payable on the invoice value of the goods which includes taxes, duties and other non taxable charges like forwarding inspection, incurance freigth, which is not justified and should be withdrawn, with immediate effect.

(d) Several Railway stations in Haryana are under equipped to handle the heavy goods, traffic emanating from the industrial towns.

As it is well known Faridabad Railway Station does not have enough booking facilities. Consequently units are constrained to send their goods to Delhi Railway Station for onward despatches. Deliveries of goods have to be made within a time bound schedule to customers both in the public and private sectors. Non availablilty of wagons at Faridabad Railway Station does not exempt the consignores from the imposition of liqudated damages and penalities in the event of delays in deliveries. Consequently the consignors have to pay the road tax while moving their goods from Haryana to Delhi

Railway Station. It will be appreaciated that such an exist of goods is being made mour out of a necessity than out of a voluntary wish. This is an additional financial burden and acts as a great disadvantage compared to various competitors in other States. In such a case road tax should be refunded on documentary evidence.

In view of the above problems and difficulties, I request you to kindly have the Ordinance reviewed in light of the original intention of the State Government of plugging loopholes and discouraging branch transfers of goods. I Trustthis would receive you sympathetic consideration.

With kind regards, Yours sincerly,

Sd/-

(Bishamber Das Kapur)

Dr. Mangal Sein,

Hob'ble Industries Minister,

Haryana, Chandigarh.

Copy of letter No. FIA/79/818 dated 25th July, 79 from Faridabad Industries Association, Bata Chowk, Industrial Area, Faridabad, addressed to the Excise & Taxation Commissioner, Government of Haryana, Chandigarh.

Sub:- Road Tax

Dear Sir,

As you are aware, the Government of Haryana promulagated an Ordinance under name and style Haryana Taxation (on certain goods carried by road) Ordinance, 1979 which is effective from 21st of April, 1979. The Ordinance contained a list of article in the Schedule for leavying such tax. It has specifically excluded from its purview the Electric Motors and tha Mono block pumping Sets whicha re primarily used for agricultural purpose. The local Excise authorities are levying 1% tax on the above items causing considerable difficulties to the small scale manufacturers.

The Committee of the Association, therefore, earnestly request you to kindly issue instructions to the locak staff not to levy 1 % tax on the Electric Motors and Mono block Pumping Sets used for Agricultural purpose.

A benign response is solicited.

Thanking you,

Yours faithfull,

Sd/-

(C.L. SAWHNEY)

Chairman,

Taxation Panel.

Copy of letter No. Nil dated 3rd August, 1979, from Remington Rand of India Limitted, Plot No. 3, Sector 6207

Mathura Road, Faridabad, addressed to Sh. Rajinder Singh, Excise & Taxation Commissioner, Chandigarh.

Subject:- The Haryana Taxation (on certain goods carried by road) Ordinance, 1979

Dear Sir,

Please refer to the above Ordinance dated 21st April, 1979. Our Company manufactures portable Typewriters, Safe Files and Kardveyers and transfers same to our Branches which are located all over India. As per schedule attached to Section 4 our items are not covered under the aforesaid Ordinance but the Sales Tax barrier persons are charging 1 % of the value of our products also. We had discussed the matter with the Excise and taxation Officer, Faridabad, who has also advised us that our goods are not covered under this Ordinance but is not giving us in writing. He has asked us to forward our request to your goodself. Hence this request.

We would like to request you to please advise the authorities that our products are not covered under this Ordinance. We will be very tankful to you if an early action is taken.

Thanking you,

Yours Faithfully,

for Remington Rand of India Limited.

Sd/-

(S.K. Maggu)

Plant Accountant,

Faridabad.

Hindustan Milk Food Manufacturers Ltd.

P.O. Box 407, New Delhi, India Himalaya, House, 5th Floor,

23-Kasturba Gandhi Marg,

New Delhi-110001,

August 9, 1979.

KCD: PK

The District Excise and Taxation Officer,

Plot No. 5, Sector 6,

Faridabad.

Re: Application under Rule 12 for refund of tax paid from April 21, 1979 till May 26, 1979, under Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordanance, 1979.

Dear Sir,

Our company is engaged in the maufacture and sale of Milk Food and dairy products popularly known in the

market as 'Horlicks', 'Boost' etc. These products are manufactured at our works located at Nabha (Punjab) and Rajahmundry (Andra pradesh) and the manufactured products in powder from are put in steel drums and transported to our packing stations located inter alia at Faridabad where the products are packed into unit containers in bottles for marketing. The products are then distributed on consignment basis to ano through our dealers all over India. The products packed at Faridabad are manufactured at Nabha (Punjab).

As our company brings its products into Haryana only for purposes of packing, such activity does not fall withing the mischief sought to be prevented by the above Ordinance, namely manufacture of goods withing Haryana but sales outside Haryana to avoid Haryana Sales Tax.

In light of the above we made a representation to the Government of Haryana and also has personal interview with the Minister Finance pursuant to which by Notification No. S.O. 64/H.O.2/79/S.3/79, dated the 26th May, 1979, the Governor of Haryana was pleased to amed the Schedule to the Ordinande by inter alia deleting entry No. 11 which included Milk Powder and other Milk Products.

We had earlier been advised that the said Ordinance was invalid and unconstitutional as being beyond the ligislative competence of the State legislature and beyond the constitutional powers of the Governor of Haryana but we preferred to await executive decision. In any event so far as our products are concerned, the matter has now been placed beyond controversy by the said Notification date 26th May, 1979, deleting entry 11 of the Schedule to the Ordinance. As

such we are now entitled to a refund to the tax paid by us from April 21, 1979 till May 26, 1979 as per annexure "A" attached.

Kindly sanction the refund due to us and issue a refund voucher in Form STR 34 in our favour as per Rule 12 of the Haryana Taxation (on certain goods by road) Rules, 1979.

We a wait to receive the refund voucher at an early dated.

Yours faithfully,

for HMM Limited.

Sd/-

Authorised Signatory.

CC. The Commissioner,

Excise & Taxation Department,

Haryana, Sector-7, Chandigarh.

<table>
<tr><th colspan="4">Annexure 'A'</th></tr>
<tr><td colspan="4">A. Details of Haryana Goods Tax @ 1% paid on bulk Horlicks, Elaichi Horlicks and Boost brought in Haryana during the period 21-4-79 to 26-5-79</td></tr>
<tr><td colspan="2">Goods Tax Receipt</td><td>Amount</td><td>Remarks</td></tr>
<tr><td>Number</td><td>Date</td><td>Rs.</td><td></td></tr>
</table>

16710/24	7-5-79	524.00	
29704/96	21-5-79	532.00	
29704/95	21-5-79	524.00	
29709/40	10-5-79	612.00	
7157/33	16-5-79	612.00	
24043/15	6-5-79	594.00	
16710/24	7-5-79	594.00	
24674/96	10-5-79	594.00	
14537/2	11-5-79	594.00	
24043/95	10-5-79	594.00	
14537/1	11-5-79	594.00	
14537/50	13-5-79	594.00	
24081/45	13-5-79	594.00	
23823/34	15-5-79	594.00	
25127/45	17-5-79	594.00	
29492/71	18-5-79	594.00	
29492/72	18-5-79	594.00	
29325/28	19-5-79	594.00	
	Total A	10526.00	

B. Details of Haryana Goods Tax @ 1% paid on bulk Horlicks, Elaichi Horlicks and Boost brought in Haryana during the period 21-4-79 to 26-5-79

Goods Tax Receipt		Amount paid	Remarks
Number	Date	Rs.	
7314/09	3-5-79	670.00	
31458/79	3-5-79	1150.00	
30834/16	3-5-79	1150.00	
30879/5	3-5-79	1150.00	
30879/35	3-5-79	670.00	
30702/67	4-5-79	1150.00	
23410/24	5-5-79	700.00	
17158	8-5-79	1150.00	
17163/47	8-5-79	1265.00	
2311/37	9-5-79	1265.00	
17317/57	9-5-79	1265.00	
17317/58	9-5-79	1265.00	
24257/50	10-5-79	690.00	
24429/37	10-5-79	230.00	

31410/97	12-5-79	387.00	
25109/35	”	1265.00	
24354/78	15-5-79	505.00	
24539/87	15-5-79	650.00	
24638/42	17-5-79	1265.00	
24638/72	17-5-79	304.00	
2406/31	17-5-79	1265.00	
24638/95	17-5-79	485.00	
24596/76	19-5-79	1265.00	
8884/18	19-5-79	172.00	
24524/78	25-5-79	1315.00	
24056/90	29-5-79	709.00	
15808/44	21-5-79	501.00	
15808/50	21-5-79	199.00	
22016/02	21-5-79	345.00	
25148/38	22-5-79	115.00	
24169/103	22-5-79	57.00	
24169/104	22-5-79	57.00	
24169/105	”	204.00	

24538/38	1-5-79	250.00	
24638/72	17-5-79	402.00	
8884/18	19-5-79	250.00	
15808/44	21-5-79	750.00	
15808/46	”	562.00	
15808/50	”	250.00	
25148/38	22-5-79	250.00	
24169/103	”	188.00	
24169/104	”	63.00	
16633/16	29-5-79	268.00	
24353/98	26-5-79	63.00	
24538/38	1-5-79	1018.00	
37	1-5-79	1422.00	
31416/41	2-5-79	1282.00	
7439/22	4-5-79	1373.00	
30702/68	4-5-79	1283.00	
16721/38	5-5-79	798.00	
1672/78	5-5-79	1283.00	
24644/95	7-5-79	1283.00	

24631/25	7-5-79	781.00	
23122/20	7-5-79	1298.00	
17163/2	8-5-79	1283.00	
17158/98	9-5-79	1283.00	
24666/91	9-5-79	1283.00	
24257/69	10-5-79	11127.00	
7199/86	”	1282.00	
24429/37	”	1035.00	
12870/69	11-5-79	781.00	
24025/13	11-5-79	1368.00	
31410/97	12-5-79	992.00	
24350/70	13-5-79	1283.00	
15666/13	13-5-79	1336.00	
17315/51	14-5-79	909.00	
”	”	427.00	
15412/13	14-5-79	1283.00	
15412/12	14-5-79	1283.00	
24354/78	15-5-79	177.00	
24638/95	18-5-79	631.00	

24547/10	18-5-79	1283.00	
8884/18	18-5-79	552.00	
24056/74	20-5-79	717.00	
24056/90	29-5-79	391.00	
24056/91	20-5-79	124.00	
15808/46	21-5-79	744.00	
15808/50	21-5-79	274.00	
22016/02	21-5-79	667.00	
25148/38	22-5-79	513.00	
24169/103	”	691.00	
24169/104	”	62.00	
24147/87	24-5-79	1290.00	
24087/15	24-5-79	860.00	
”	”	148.00	
24087/85	25-5-79	1283.00	
16633/16	25-5-79	521.00	
17464/83	26-5-79	684.00	
24353/98	”	1250.00	
17160/47	”	781.00	

	Total B	70635.00	
	Total A+B	Rs. 81161.00	

Sd/-

for HMM Limited.

Authorized Signatory.

Employment to the Unemployed Graduates

***1489. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Public Works (Public Health) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide employment to the un employed graduated in the State; if so, the details therefore?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): ि ाक्षित बेरोजगारो (मैट्रिक पास तथा इससे अधिक) को रोजगार प्रदान करने के उद्दे य से सरकार ने कई रोजगार सकीम्ज चलाई है। ये स्कीम्ज मुख्यतः कृशि सेवा केन्द्र स्थापित करना, कृशि सेवा विस्तार कार्यक्रम का प्रसार, ि ाक्षित युवक/युवतियों को लधु डेरीज की स्थापना पर स्वतः रोजगार देना, ग्रामीण औद्योगिकरण स्कीम, ि ाक्षित युवकों (जिसमे तकनीकी ि ाक्षा प्राप्त भी भाामिल है) को स्वतः रोजगार ईकाईयां स्थापित करने के लिये सीड कैपीटल/मार्जिन मनी को सहायता प्रदान करना तथा

प्रौढ़ ि ाक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। इन स्कीम्ज के अधीन बेरोजगार स्नातक भी रोजगार प्राप्त कर सकते है।

Construction of Bridge over Yamuna River

***1631. Shri Fateh Chand Vij, Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether the Govt. is aware of the fact that the bridge on Yamuna River linking Panipat with Uttar Pardesh has been rendered unfit for traffic for the last one a and a half years due to damage caused to it by floods;

(b) whether the Govt. has made any correspondence with the Uttar Pardesh Govt. for its repairs; if so the details thereof; and

(c) wheter it is also a fact that the Govt. has written to the Uttar pradesh Govt. that the Haryana Govt. is prepared to get the bridge repaired if they are not willing to do so and if so, the details of the reply so far received from the Govt. of Uttar Pradesh?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(ए) हां, जी।

(बी) हां, जी। इस पुल को क्षति के कारण जनता की अति कठिनाई को ध्यान मे रखते हुए, हरियाणा सरकार ने 17.3.79

को सचिव, उत्तर प्रदे ा सरकार, लोक निर्माण विभाग को इस पुल की मुरम्मत भीघ्र कराने हेतु एक पत्र लिखा।

(सी) नही, जी।

New Water Works on Jhajjar Road Rohtak

***1599. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether a new water works is being constructed on Jhajjar road in Rohtak; if so, the capacity thereof;

(b) the estimated expenditure to be incurred on the above said water works together with the amount sent so far;

(c) the time by which it is likely to be completed; and

(d) the extent to which the capacity of water distribution wil be increasedafter the completion of the said water works?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) हां, जलघर की क्षमता निम्नलिखित है:–	
चरण–I	10 लाख गैलन प्रतिदिन
चरण–II	12 लाख गैलन प्रतिदिन
(ख) अनुमानित रा ि ा निम्नलिखित है:–	
चरण–I	84.91 लाख रूपये

चरण–II	95.09 लाख रूपये
कुल जोड़	95.09 लाख रूपये

केवल पहले चरण का कार्य हो रहा है। फरवरी, 1980 तक 60.83 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

(ग) पहले चरण के कार्य दि ाओं मे धन रा ि ा जो नगरपालिका रोहतक द्वारा मार्च, 1981 तक जमा करवाई जानी है, के उपलब्ध होने पर पूरा होने की आ ा की जा सकती है। दूसरे चरण के बारे मे कोई नि ि चत समय नही बताया जा सकता क्योंकि यह धन रा ि ा उपलब्ध होने पर निर्भर है।

(घ) पहले चरण का काय्र समाप्त होने पर पानी देने की क्षमता 10 लाख गैलन प्रतिदिन बढ़ जायेगी तथा दूसरे चरण का पूर्ण काय्र समाप्त होने पर पानी की क्षमता 22 लाख गैलन प्रतिदिन बढ़ जायेगी।

Neurology/Neuro-surgery Departement in the

Govt. Medical College, Rohtak

***11549. Ch. Sant Kanwar:** Will the Ministerbe pleased to state—

(d) whether Neurology or Neuro Surgery Department exists in the Medical College, Rohtak at present;

(e) if so, the details of the staff posted therein; and

(f) if not. whether there is any proposal under consideration to open Neurology or Neuro Surgery Departement with adequate staff there?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) (i) न्यूरोलौजी का कोई अलग विभाग नही है। परन्तु इसका एक अनुभाग मैडिसिन विभाग मे ही एक प्रौफैसर, जिसने इस विशय मे एडवांसड ट्रेनिंग ली हुई है, के अधीन चल रहा है।

(ii) जी नही। न्यूरो सर्जरी विभाग खोलने के लिये पद स्वीकृत है और स्थान भी उपलब्ध हे परन्तु उपयुक्त टीचिंग स्टाफ न मिलने के कारण इस विभाग ने कार्य करना अभी आरम्भ नही किया है।

(ख) जी नही।

(ग) उपयुक्त स्टाफ सहित न्यूरो सर्जरी विभाग खोलने के बारे प्रस्ताव विधाराधीन है।

Extension of Rara Minor

***1635. Sh. Jai Narain Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under considreration of the Govt. to extend Nara Minor to Village Mirchpur in Barwala constituency, if so, the steps, if any, taken for the extension thereof?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): नही। नाडा माईनर को गांव मिरचपुर तक बढ़ाने की मांग थी जिसको विचार उपरांत अस्वीकार कर दिया गया।

Remodelling of Ottoo Bridge

***1527. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under considreration of the Govt. to remodel the Ottoo Bridge of District Sirsa; if so, the time by which it is likely to be remodelled?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): हां। ओटू पुल को रिमौडल करने का प्रस्ताव है, जिसका कार्य धन रा ि ा की उपलब्धि होने पर जून, 1981 तक पूर्ण होनी की सम्भावना है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

New Water Works on Jhajjar Road Rohtak

356. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the district wise total number of residential hours and shops together with the names of place where constructed during the period from 1966-67 to 1979-80 (to date) in the State by the Housing Board, together with

the criteria adopted for the allotment thereof, separately; and

(b) the dstrict wise total number of residential houses and shops togetherwith the names of places where they are likely to be constructed during the years 1980-81 and 1981-82 together with the criteria to be adopted for the allotment thereof, separately?

विकास मंत्री (राव राम नारायण):

(ए) और (बी) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूचना

(ए) आवास बोर्ड, हरियाणा अगस्त, 1971 मे स्थापित किया गया था। अतः 1966–67 से 1971–72 की अवधि के दौरान किसी भी रिहाय ी मकान और दूकानों का निर्माण नही किया गया।

राज्य मे 1972–73 से 1979–80 की अवधि के दौरान आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए (I) रिहाय ी मकानो, और (II) दुकानों की जिलावार कुल संख्या तथा जहां वे बनाए गए उन स्थानों का नाम इस प्रकार है:–

वर्श	जिले का नाम	स्थान	श्रेणीवार निर्मित मकानों की संख्या

			एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	इ. डब्ल्यू. एस.	जोड़
1972–73	फरीदाबाद	सैक्टर–7, फरीदाबाद	–	–	500	500
			–	–	500	500
1973–74	फरीदाबाद	सैक्टर–22, फरीदाबाद	164	252	468	884
	करनाल	पानीपत फेज I और II	77	32	109	218
	अम्बाला	यमुनानगर	25	6	117	148
			266	290	694	1250
1974–75	सोनीपत	सोनीपत–I	78	16	129	223
	अम्बाला	अम्बाला	48	44	119	211
			126	60	248	434
1975–76	अम्बाला	पंचकूला	51	84	147	281

	करनाल	करनाल	132	64	244	440
			183	148	391	722
1976–77	गुड़गांव	गुड़गांव	74	49	61	184
	जींद	जींद फेज–I	22	26	60	108
	सोनीपत	राई स्पोर्टस डिपार्टमैंट	16	—	—	16
	कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र	36	39	11	86
			148	144	132	394
1977–78	फरीदाबाद	सैक्टर–28, फरीदाबाद	169	—	—	169
	रोहतक	रोहतक	63	152	102	317
	करनाल	वीवर्ज कालोनी पानीपत	—	—	329	329
	फरीदाबाद	सैक्टर–23, फरीदाबाद	82	—	742	824

	सोनीपत	राई स्पार्टस स्कूल	—	49	—	49
	जींद	जींद, फेज—II	34	84	56	174
			384	285	1229	1862
1978—79	कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र फेज—II	—	116	68	184
	कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र फेज—III	36	67	56	159
	फरीदाबाद	सैक्टर—28, फरीदाबाद	98	—	—	98
	भिवानी	भिवानी	102	156	126	384
	सोनीपत	सोनीपत फेज—II	35	64	80	179
	करनाल	मधुबन	32	400	148	580
	फरीदाबाद	सैक्टर—23, फरीदाबाद	—	247	—	247

			303	1050	478	1831
1979–80	हिसार	हिसार	14	30	32	76
	अम्बाला	पंचकूला	235	331	311	877
	फरीदाबाद	फरीदाबाद	304	305	415	1024
	करनाल	करनाल	62	184	209	455
	सिरसा	सिरसा	22	112	2099	433
			637	962	1266	2865
		कुल जोड़	2011	2909	8938	9858

मकानो की अलाटमैंट ''पहले आओ पहले पाओ'' नीति के आधार पर की जाती है और आवास बोर्ड, हरियाणा (हरियाणा प्रबंध तथा टैनिमैंट की बिक्री) विनियमावली, 1972 के विनियम 7 के अनुसार निम्नलिखित क्रम से नियमित की जाती है:–

(i) उन के लिये 7½ प्रति ात जो पंजीकरण की रा ि ा जमा कराते समय 25 प्रति ात अथवा इस से अधिक रा ि ा जमा करवाये।

(ii) 7½ प्रति ात राज्य सरकार तथा आवास बोर्ड के कर्मचारियों के लिये।,

(iii) 20 प्रति ात अनुसूचित जातियों के लिये (इस मे 1.5 प्रति ात विकलांग/नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये कोटा भी भाामिल है।)

(iv) 10 प्रति ात सेवारस सैनिक कर्मचारी वर्ग के लिये जिस मे युद्ध मे मारे गये सैनिको की विधवाएं, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक आदि भी भाामिल है।

(v) 5 प्रति ात पिछड़े वर्गों के लिये।

उपर्युक्त वर्ग (i) से (v) मे उल्लिखित अधिमान्य आवेदकों को अलाटमैंट करने के प चात् भोश मकान सामान्य वर्ग मे आने वाले आवेदकों को दिये जाते है।

(II) 1972–73 से 1979–80 तक की अवधि के दौरान राज्य मे बनाई गई दुकानों की जिलावार कुल संख्या नीचे दी जाती है:–

वर्श	जिले का स्थान		दुकानो की
	नाम		कुल संख्या
1	2	3	4
1972–73 और 1973–74	–	–	–
1974–75	अम्बाला	यमुनानगर	12

	करनाल	पानीपत फेज–I	14
			26
1975–76	सोनीपत	सोनीपत	12
	अम्बाला	पंचकूला	13
	करनाल	करनाल	19
	फरीदाबाद	सैक्टर– 22, फरीदाबाद	18
			62
1976–77	फरीदाबाद	सैक्टर– 22, फरीदाबाद	38
	करनाल	पानीपत, फेज–II	14
			52
1977–78	जींद	जींद	15
	करनाल	वीवर्ज कालोनी पानीपत	8
			23

1978–79	रोहतक	रोहतक	10
			10
1979–80	फरीदाबाद	सैक्टर– 23, फरीदाबाद	38
	भिवानी	भिवानी	12
			50
	कुल जोड़		223

बोर्ड द्वारा बनाई गई दुकानों की बिक्री आम नीलामी से की गई है।

(बी) (i) बनाये जाने वाले मकानो की लगभग संख्या तथा इस के साथ जिलों तथाा स्थानो के नाम, जहां बोर्ड द्वारा वर्श 1980–81 और 1981–82 के दौरान मकान बनाये जाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार है:–

वर्श	जिले का नाम	स्थान	श्रेणीवार निर्मित मकानों की संख्या				
			एम. आई.	एल. आई.	इ. डब्ल्यू.	एच. आई.	जोड़

			जी.	जी.	एस.	जी.	
1980—81	अम्बाला	पंचकूला	250	162	—	29	441
	फरीदाबाद	फरीदाबाद	5	462	906	—	1373
	फरीदाबाद	फरीदाबाद	53	114	121	—	228
			308	738	1027	29	2102
1981—82	गुड़गांव	गुड़गांव	95	208	106	—	409
	करनाल	पानीपत	195	442	543	—	1280
	फरीदाबाद	सैक्टर—29, फरीदाबाद	150	50	—	—	200
	सोनीपत	सोनीपत	106	151	122	—	379
	कुरूक्षेत्र	चीका	—	165	—	—	165
	जींद	जींद	70	—	—	—	70
			13	48	94	—	155
			729	1064	865	—	2658
			1037	1802	1892	29	4760

मुकम्मल होने पर इन मकानों की अलाटमैंट आवास बोर्ड हरियाणा, (अलाटमैंट, प्रबंध और टैनीमैंट की बिक्री)

विनियमवली, 1972 के विनियम संख्या 7 मे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार की जायेगी।

(ii) 1980–81 और 1981–82 मे आवास बोर्ड द्वारा चीका (कुरूक्षेत्र) के सिवाए किसी अन्य स्थान पर दुकानो का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नही है। चीका मे कितनी दुकानें बनाई जायेंगी इस संबंध मे भी अभी अंतिम निर्णय किया जाना है।

Allotment of plots for resiential purposed by HUDA

357. Chudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) the district wise number of plots auctioned/allotted for commeercial purposed together with the names of places where auctioned/allotted by the HUDA during the period from 1966-67 to 1979-80 (to date) togetherwith the criteria adopted for allowtment/auction thereof, seperately; and

(b) the district wise number of plots as referred to in part (a) above which are likely to be allowtted/auctioned during the year 1980-81 and 1981-82, separately?

स्थनिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): इस सुचना के एकत्रित करने मे जितना सम लगेगा और प्रयास करना पड़ेगा, उससे जनहित की दृश्टि मे कोई लाभ नही होगा।

Ban on the export of cows and buffaloes

359. Chudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state—

(c) whether the Govt. maintain a record about the figures of cows and buffaloes; if so, the total number of cows and buffaloes in the State as on 31st March, 1977 and 28-2-1980, separately;

(d) the total number of cows and buffaloes exported to other States during the period from 1966-67 to 1976-77 and 1977-78 to 1979-80 (to date) separately; and

(e) whether any ban has been imposed on expert of cows and buffaloes from State; if so, since when?

जल तथा डेयरी विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा):

(क) वर्श 1977 की प ा गणना के अनुसार 15—4—77 को राज्य मे गायों तथा भैंसो की संख्या निम्न प्रकार थीः—

गाय 24.4 लाख

भैंसें 29.4 लाख

28—2—80 को राज्य मे गायों औ भैसों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार हैः—

गाय 24.4 लाख

भैंसें 32.4 लाख

(ख) वर्श 1966–67 से 1976–77 तक राज्य से निम्नलिखित संख्या मे गायें तथा भैंसें निर्यात की गईः–

गाय 5.07 लाख

भैंसें 7.83 लाख

वर्श 1977–78 से 1979–80 (31–1–1980 तक) राज्य से निम्नलिखित संख्या मे गायें तथा भैंसें निर्यात की गईः–

गाय 1.09 लाख

भैंसें 1.53 लाख

(ग) राज्य सरकार ने एक अध्यादे ा दिनांक 26–11–79 द्वारा गोवध करने के लिये राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस अध्यादे ा को बदलने के लिये एक विधेयक विधान सभा मे पे ा किया गया है।

नेमिंग आफ मैंबर

डॉ. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि चौधरीवास मे पिछले दिनों एक कत्ल हुआ था, उस संबंध मे जांच करने के लिये इस हाउस के मैंबरों की एक कमेटी बनाई गई थी। (ाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Doctor Sahib, I have not received any notice for this. (Interruptions)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो हाउदस की एक कमेटी बनाई गई थी (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अगर जीरो आवर मे कोई प्वायंट रेज करना चाहे तो पहले मुझे उसका नोटिस दे। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग मे स्टेटमैंट दिया था और वह स्टेटमैंट जो है कंटैम्पट आफ दी हाउस हो जाता है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी क्या आपने इसके लिये कोई नेटिस दिया है । (ाोर)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मैं उस का नोटिस अब दे रहा हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी आप यह मेरे को लिखित रूप मे दीजिए। Please take your seat.

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः जो कुछ मेरी इजाजत के बगैर बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाये (ाोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं आपसे एक रिकवैस्ट करूंगा कि यह बात रिकार्ड न की जाये। (ाोर एवं विघ्न) मैंने कोई भी स्टेटमैंअ नही दिया था (ाोर एंव विघ्न)

श्री अध्यक्षः वह मैं पहले ही कह चुका हूं कि रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी, आप मुझे लिखित रूप मे दीजिए। (ाोर) Please take your seat.

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(ाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Chaudhri Ganga Ram ji I would request you to please sit down. (Interruptions)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप बैठ जाये। मुख्य मंत्री जी ने यह डिनाई कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमैंट दिया है । मैंने पहले ही कर दिया है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई बात रिकार्ड न की जाये। इसलिये आप हाउस का समय जाया न करे and nothing will be recorded. (ाोर)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः जो चीज प्रैस मे रिपोर्ट होती है उसका हाउस से कोई संबंध नही है। आप लिख करके दे दे। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं कि आप बैठ जाइये otherwise with great reductance I will have the name you.

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(ाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: I name Ch. Ganga Ram. He may please withdraw from the House. (Interruptions)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(ाोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Remove him.

(इस समय सार्जेंट एट आर्मज चौधरी गंगा राम जी के पास गए तथा उन्हें सदन से बाहर ले गए)

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

राज्यपाल के अभिभाशण तथा बजट की आम चर्चा पर अपोजी ान तथा ट्रेजरी बैंचिज को दिये गये टाइम संबंधी

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान अब मैंने एक अनाउंसमैंट करनी है।

कल बजट पर जनरल डिस्क ान का आखिरी दिन खत्म हुआ। जब से मैंने इस आगस्ट चेयर को आकुपाइ किया है तब से मेरी पालिसी और कोि ा ा सदा यही रही है कि जम्हूरियत भी रहा हूं। यह मेरी बात इससे जाहिर भी होती है कि गवर्नर एड्रैस पर, हालांकि हाउस की कम्पोजी ान आप सब लोग जानते है कि 48 मैंबर साहेबान ट्रैजरी बैन्चिज के है और 40 मैंबर साहेबान अपोजी ान की तरफ बैठे है। अपोजी ान के मैंबर साहेबान को बोलने के लिये मैंने 250 मिनट का समय दिया और ट्रैजरी बैंचिज को बोलने के लिये केवल 243 मिनट का समय

दिया। यही बात जनरल डिस्क ान आन दि बजट से और भी ज्यादा मैनीफैस्ट होती है, जिससे क्लियर नजर आता है कि जनरल डिस्क ान आन दी बजट के ऊपर अपोजी ान मैंबर साहेबान को 388 मिनट बोलने के लिये समय दिया गया जब कि ट्रैजरी बैन्चिज को केवल 295 मिनट का समय दिया गया। इसके अलावा मैंबर साहेबान, मै अपनी तरफ से यह समझता हूं कि हरियाणा विधान सभा का यह एक बड़ा क्रु ियल सै ान था और इस सै ान के दौरान एक बड़े मु कल काम को निपटाने मे, पूरा करने मे जो आप सब साहेबान ने, और वि ोश तौर पर लीडर आफ दि अपोजी ान, बाबू मूल चंद जैन जी, और लीडर आफ दि जनता लैजिसलेचर पार्टी, डॉ. मंगल सैन जी ने, मुझे कदम कदम पर सहयोग दिया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथर ही जो ट्रेजरी बैन्चिज की तरफ से मिनिस्टर साहेबान ने और दूसरे मैंबर साहेबान ने मेरा सहयोग किया है उसके लिये उनका भी मैं बहुत आभारी हूं लेकिन मैं वि ोश तौर पर लीडर आफ दि अपोजी ान, बाबू मूल चंद जी जैन, और डॉ. मंगल सैन जी को एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया है। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि जो 4–5 दिन का सै ान बाकी रहता है उस दौरान भी मेरे उनका इसी किस्म का सहयोग मिलता रहेगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपने इनका भुक्रिया अदा तो दिया।

आपने कहा कि इन्होंने जितना सहयोग पीछे दिया वैसा ही आगे देंगे इससे तो इनका हौंसला और भी बढ़ जायेगा।

डॉ. मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अगर कोई गुस्ताखी की है तो आपने उसको दरगुजर किया है। आपने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है इसके लिये हम आपके आभारी है।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, *

* * * * (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाये। (ाोर)

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारि ा है कि चौधरी गंगा राम जी वापिस बुला लें। हम उनको समझा देंगे। (ाोर)

आवाजेंः स्पीकर साहब, चौधरी गंगा राम जी को वापिस बुला लिया जाये।

Mr. Speaker: You give me an assurance that the would not repeat it. डॉ. मंगल सैन जी अगर ए ाोरेंस देते है तो चौधरी गंगा राम जी को हाउस मे वापिस बुला लिया जाये।

Dr. Mangal Sein: Sir, I will try my best to presuade Ch. Ganga Ram to maintain decorum and discipline in the House.

श्री अध्यक्षः ठीक है, चौधरी गंगा राम जी को हाउस मे वापिस बुला लिया जाये।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, कल मैंने एक प्वायंट पर आपकी रूलिंग मांगी थी।

श्री अध्यक्षः मैंने रूलिंग दे दी है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, हाउस की इन्फर्मे ान के लिये अगर आप हाउस मे पढ़ कर सुना दे तों ठीक रहेगा। आप हाउस को बता दें कि क्या रूलिंग दी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मेरी रूलिंग भाायद आपके पास पहुंच गई है। Every ruling need not be announced in the House. You have been informed about it. मेरे पास आपके सिग्नेचर है। अब आप यह प्रैंस वालो को दे सकते है।

वर्श 1980–81 की बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब वर्श 180–81 के बजट की डिमांउज फार ग्रांटस पर विचार होगा। पहली प्रैक्टिस के अनुसार हाउस का समय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गई डिमांउज फार ग्रांटस एक साथ पढ़ी गई और पे ा की गई समझी जायेंगी। आनरेबल मैंबर किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते है,

लेकिन बोलते समय कृपया डिमांड का नंबर बता दे। 1 बजे डिमांडज पुट की जायेगी।

That a sum not exceeding Rs. 3691510 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 65977430 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 2-Genral Administration.

That a sum not exceeding Rs. 181237335 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 42483700 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 25221360 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 67016185 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 41120600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 202571500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 577456210 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 353166140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 16500330 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 150740020 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 56121610 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabitlitation.

मेरे पास श्री मूल चंद जैन की तरफ से कुछ कट मो ांज आए है, चूंकि आनरेबल मैंबर हाउस प्रैजैंट नही है, इसलिये वे मूव की गई नही समझी जायेगी।

श्रीमती डॉ. कमला वर्मा (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं डिमांड नं.5 पर अपने विचार रखना चाहती हूं। यह डिमांड एक्साईज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट से ताल्लुक रखती है। मैं एक्साईज एंड टैक्से ान तथा वित्त मंत्री के नोटिस मे लाना चाहती हूं कि यमुनानगर मे टिम्बर और टिम्बर मैनुफैक्चरिंग का लार्ज स्केल पर काम होता है। वह सारे एि ाया मे एम्युनी ान केसिज और दूसरे कई प्रकार के पैकेस केसिज बनाने के लिये सुप्रसिद्ध है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने देसी घी पर वैसे बिक्री टैक्स माफ कर दिया है, इसी तरह टिम्बर और टिम्बर मैंनुफैक्रिंग पर भी टैक्स खत्म किया जाना चाहिए था। पहले एक बार इस टैक्स को खत्म करने का आ वासन भी दिया गया था

लेकिन उस पर अभी तक डिपार्टमैंट की तरफ से इमल नही हुआ है।

(इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य भी कन्हैया लाल पोसवाल पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, यमुनानगर की ट्रेड्ज को बड़ा धक्का लग रहा है, 60 प्रति ात प्रोडक ान कम हो गई है। मैंने एक साल के लिये बिक्री टैक्स माफ करवाया था लेकिन सरकार ने पोलिटिकल डिसीजन लेकर इसको दोबारा लागू कर दिया है। चेयरमैन साहब, आप नेबरिंग स्टेट्स की स्थिति देखे। पंजाब मे टिम्बर और टिम्बर मैनुफैक्चरिंग पर 2 प्रति ात टैक्स है लेकिन यू.पी., हिमाचल प्रदे ा और जम्मू एंड का मीर मे कोई टैक्स नही है। हरियाणा मे 60 परसैंट प्रोडक ान कम होने से ट्रांसपोर्ट को हानि हो रही है और सारी लेबर निरा ा होकर बैठी हुई है। चेयरमैन साहब, 30–40 परसैंट ट्रेडज दूसरे प्रांतों मे हरियाणा मे 4 प्रति ात टैक्स होने के कारण ये ट्रैड्ज दूसरे प्रांतों जम्मू का मीर, यू.पी. हिमाचल प्रदे ा वगैरह मे जा रही है इसलिये मेरी प्रार्थना हे कि दूसरी स्टेटों के साथ टैक्स की यूनिफार्मिटी रखे ताकि लोग दूसरे प्रांतों मे ट्रड्ज न ले जाये। जब तक टैक्स की युनिफार्मिटी नही होगी, हरियाणा मे रैवेन्यू को धक्का लगता रहेगा, व्यापरियों को धक्का लगता रहेगा और लेबर को निरा ाा का मुंह देखना पड़ेगा।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिपांड नं.9 पर, जो कि एजुके ान के बारे मे है, अपने विचार रखना चाहती हूं मैं यह मानकर चलती हूं कि सरकार ने ि ाक्षा के प्रसार के लिये कुछ काम करने का प्रयास किया, लेकिन इस बात से इंकार नही करती कि ि ाक्षा विभाग के अंदर मूलभूत समस्यायें है जिसके कारण ि ाक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। चेयरमैन साहब, मैंने एक प्र ान भी किया था जो साईंस और सामाजिक अध्यापकों के बारे मे था। मैंने पूछा था कि साईंस टीचर की जगह पर सामाजिक और एस.एस. टीचर्ज क्यों लगाये जाते है। चेयरमैन साहब, हमारे यहां एक एग्जामीने ान होता है जिसको 'साईंस रिसर्ज टेलेंट एग्जामीने ान' कहते है। इस एग्जामीने ान मे हरियाणा प्रान्त और दूसरे प्रान्तों के बच्चे, जिन्होंने 10वीं 11वीं पास की होती है, अपीयर होते है। मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि जब से यह परीक्षा भाुरू हुई है, हरियाणा प्रांत के केवल 7 बच्चे ही आ पाये है क्योंकि यहां पर साईंस का स्तर बहुत नीचा है जिसके कारण हरियाणा के बच्चों को अपना टेलेंट दिखाने का मौका नही मिलता। चेयरमैन साहब, दूसरे प्रांतों मे 10+2 का सिस्टम लागू है, लेकिन हरियाणा मे अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया कि हरियाणा मे हायर सैकैंडरी सिस्टम चलेगा या 10+2 सिस्टम लागू होगा। कुरूक्षेत्र मे रीजनल टैक्नीकल कालेज है जिसमे 125 बच्चे बाहर से आते है, अन्य 125 हरियाणा के लिये जाते है। अन्य प्रांतों के बच्चे 4 वर्श का कोर्स चाहते है जबकि हरियाणा के विद्यार्थी 5 वर्श का चाहते है। मैं सरकार से जानना

चाहती हूं कि ि ाक्षा विभाग ने समानता लाने के लिये जब तक निर्णय क्यों नही लिया ? दूसरे प्रांतों के साथ समानता लाले के लिये सरकार को निर्णय लेना चाहिए ताकि आने वाले बच्चो को असुविधा न हो। चेयरमैन साहब, इसके अतिरिक्त ि ाक्ष विभाग के अंदर कोई तालमेल नही है। 8वीं कक्षा तक की किताबें डिपार्टमैंट छपवाता है और आठवीं के आगे की किताबे बोर्ड छापता है। इन दोनाो संस्थाओं मे आपस मे कोई तालमेल नही है। कोर्सिज की कन्टिन्यूटी साथ साथ नही चलती। एक्सपर्टस को एक रूफ के नीचे बैठकर आपस मे तालमेल करके, बच्चो के कैरियर को ध्यान मे रख कर पुस्तक पाठयक्रम रखने चाहिए ताकि कोर्सिज मे कंटन्यूटी रहे। मैं मुख्य मंत्री महोदय से और चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिबा से कहना चाहती हूं कि पाठयक्रम मे कंटिन्यूटी के लिये एक्सपर्टस को एक रूफ के नीचे बैठकर डिसीजन लेना चाहिए ताकि हमारे प्रान्त के बच्चों का भविश्य उज्जवल हो सके और वे कम्पीटी ान मे दूसरे प्रांतो के बच्चो के मुकाबले मे बैठ सके। इसके अतिरिक्त एक न्युनता यह है कि कई बार किताबें अधिक छप जाती है और इन दि मीन टाईम कोर्सिज बदल जाते है। इन पुराने पाठयक्रम की किताबों को कुछ स्कूलो मे लगा दिया जाता है। चेयरमैन साहब, मुझे यह कहने से इंकार नही है कि अभी भी कुछ स्कलों मे पुराने कार्सिज की पुस्तके लगी हुई है और कुछ स्कूलों मे नये कोर्सिज की पुस्तके लगी हुई है। यह दो भांति का सिस्टम नही होना चाहिए, इससे बच्चो के कैरियर पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस वर्श प्रिंटिंग एंउ स्टे ानरी डिपार्टमेंट के

द्वारा जितनी किताबे छापी गई है उन मे कुल चार हजार गल्तियां पाई गई है। अगर किताबों मे प्रिंटिंग ही गलत हो तो बच्चे क्या समझेंगे, कैसे उनका भविश्य बनेगा ? चेयरमैन साहब, एजुके ान के बारे मे एक बात और कहना चाहती हूं। हरियाणा मे प्राईवेट टीचर्ज की सिक्येरिटी आफ सर्विस के लिये एक एक्ट बना हुआ है। लेकिन आध्यापकों के कुद ग्रिवैंसिज और भी है। प्राईवेट मैनेजमैंट उनको पे कुछ देती है ाऔर लिखवाया कुछ जाता है। सारे हिन्दुस्तान के अंदर केवल 7 प्रांत ऐसे है जिनमे अध्यपको को वेतन ट्रैजरी के द्वारा मिलता है। हरियाणा सरकार को भी यह सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि हरियाणा मे प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज के साथ अन्याय न हो। ट्रैजरी के द्वारा वेतन देने से, जो अध्यपक इस एक्ट के नीचे आते है उनको लाभ होगां इसके अतिरिक्त प्राईवेट स्कूलों को कुछ ग्रांट दी जाती है लेकिन प्राईवेट मैंनेजमैंट ग्रांट प्रयोग करने मे बड़ी घपलेबाजी करती है। यह फण्ड स्कूल के अध्यपको और बच्चो के लिये होता है और अगर कोई मैंनेजमैंट इसको यूज करने मे घपलेबाजी करती है तो सरकार उस स्कूल को ग्रांअ बंद कर देती है। इसलिये सरकार को चाहिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाये ताकि वह चैंकिंग करे, और देखे कि जो ग्रांट सरकार देती है, वह गलत ढंग से इस्तेमाल तो नही हो रही। ग्रांट को ठीक तरह से प्रयोग करवाना चाहिए लेकिन ग्रांट बंद करके बच्चों और अध्यापकों को दण्ड नही देना चाहिए। इसके अलावा हरिजनों के बारे मे भी बातें कही जाती है। लेकिन एक बात मैं सरकार के नोटिस मे लाना

चाहती हूं । हरिजन विद्याथ्रियों की वैसे तो आठवीं और दसवीं आदि की परीक्षा देने के लिये जो ऐडमि ान फीस होती है वह माफ होती है लेकिन मुख्याध्यापक उनसे पहले ले लेते है, बाद मे युनिवर्सिटी से लिखा पढ़ी करके उसे वापिस करते है। परीक्षा के बाद कई बार छात्र इधर उधर चले जाते है और उन्हें उनका पैसा भी वापस नही मिलता। अगर सरकार इस बात को ध्यान मे रख कर प्रारम्भ मे ही ऐसा सरकुलर निकाल दे कि हरिजन बच्चो से फीस न ली जाये तो उनके माता पिताओं को ज्यादा राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, हमारा हरियाणा प्रांत कृशि प्रधान माना जाता है। पहले छठी कक्षा से कृशि का विशय हुआ करता था। उस विशय के तहत बच्चे कृशि के बारे मे काफी कुछ सीखते थे और परिणास्वरूप बाद मे गांव मे रह कर वे अपने आपको कृशि के काम मे लगा लिया करते थे। लेकिन अब छठी कक्षा मे कृशि और ड्राईंग के विशय को हटा दिया गया है। मेरी प्रार्थना यह है कि इस विशय मे दोबारा स्कूलों मे भाुरू किया जाये।

सभापति महोदय, एक पटेल कमेटी बनी थी जिसके युजफूल प्रोडक्टिव वर्कस के बारे मे थोड़ा पाठयक्रम बना कर अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमे ि ाक्षा कार्यक्रम के साथ श्रमनिश्ठा की एक योजना थी जिसके तहत बच्चो को पढ़ाई के साथ साथ श्रम के महत्व के बारे मे भी बताय जाता था। उसके आंतरिक अंक हुआ करते थे। जब कोई अध्यापक किसी बच्चे को आंतरिक अंक

नही देता था तो उसका रिजल्ट रोक दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है वह कोर्स अब स्कूलों मे नही है । बच्चों को उसके बारे पढ़ाया नही जाता परन्तु बच्चों के साथ धोखा किया जाता है और झूठ सिखाया जाता है।

इसके अलावा, चेयरमैन साहब, हमारे यहां एक नैतिक ि ाक्षा समिति बनी थी। आप जानते है कि मानव का निर्माण अपनी संस्कृति और उसके आचरण पर आधारित है। आप यह भी जानते है कि बच्चे राश्ट्र की नींव है। जैसी ि ाक्षा उनको दी जायेगी वैसे ही नागरिक वे आगे जाकर बनेंगे। अगर हम अपनी संस्कृति की ि ाक्षा उन्हें देंगे तो वे आगे चल कर अच्छे नागरिक बनंगे, अच्छे अध्यापक बनेंगे, अच्छे डाक्टर बनेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे सरकारी कर्मचारी बनंगे और अच्छे राजनीतिज्ञ बनेंगे। वे सोंचेंगे कि मेरा चरित्र अच्छा हो, मैं किसी सिद्धांत के लिये राजनीति मे आया हूं, मैं किसी सिद्धांत के लिये अध्यापक कार्य मे आया हूं, मैडिकल प्रोफै ान मे आया हूं या सरकार नौकरी मे आया हूं। सिद्धांत के नाते ही यह जनसेवा कर सकता है। चेयरमैन साहब, उस नैतिक ि ाक्षा समिति की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मेरी यह प्रार्थना है कि उसे जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि हरियाणा के बच्चे अच्छे नागरिक बन सके।

सभापति महोदय, मैं एक और विचार सदन के सामने रखना चाहती हूं। प्राईमरी ि ाक्षा बड़ी आव यक है क्योंकि इसी मे बच्चे की ि ाक्षा की नींव रखी जाती है लेकिन यह कहते हुए

बड़ा दुख होता है कि गांव मे एक अध्यापक को दो तीन क्लासिज को पढ़ाना पड़ता है। चेयरमैन साहब, पंजाब मे प्राईमरी ि ाक्षा के लिये अलग डायरैक्टर बना हुआ है। प्राईमरी ि ाक्षा सुदृढं हो और बच्चों को अच्छी ि ाक्षा मिले इसके लिये जरूरी है कि पंजाब की तरह यहां भी अलग डायरैक्टोरेट बनाया जाये। उम्मीद है हमारी सरकार ऐसा करने की पूरी कोि ा ा करेगी।

इसके साथ ही मुझे एक बात और कहनी है। सभापति महोदय, अडल्ड ऐजुके ान सैंटर्ज बनाए गए थे। जनता सरकार के समय मे इन सैंटर्ज मे कई घपले पकड़े गये थे और कुछ डी.ई. ओज. सस्पैंड भी किये गये थ लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जांच किये बिना ही उनमे के कुछेक को रीइनस्टेट कर दिया गया है। सरकार कृपया इस तरफ भी ध्यान दे। मैं ि ाक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि जो सुझाव मैंने दिये है यदि सरकार उन पर अमल करेगी तो ि ाक्षा का स्तर ऊंचा होगा और हरियाणा के बच्चे काफी उन्नति कर सकेंगे।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांउ नं.10 के बारे मे कुछ निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, आप जानते है कि किसी भी राश्ट्र के उत्थान के लिये ि ाखा के बाद स्वास्थ्य का बड़ा महत्व होता हैं कार्य निश्ठा स्वास्थ्य के माध्यम से ही बढ़ सकती है। अगर स्वास्थ्य ही ठीक न हो तो इंसान न तो मेहनत कर सकता है, न हल चला सकता है, न स्कूल मे ठीक से पढ़ व पढ़ा सकता है, न उत्पादन कार्य कर सकता है, कहने का मतलब यह

कि वह कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नही कर सकतां विदे ाो मे स्वास्थ्य के लिये सबसे जयादा बजट रखा जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब कभी बजट मे कटौती लगती है तो स्वास्थ्य के बजट पर लगा करती है। स्वास्थ्य बजट वर्श 1979–80 मे कंस्ट्रक ान के लिये 2.8 करोड़ रूपये का था और मुख्य मंत्री जी ने जितने हस्पतालो के नींव पत्थर रखे हे, उसका एस्टीमेट 17 करोड़ रूपये का बनता है जबकि इस बार भी 1980–81 मे केवल 2.28 करोड़ रूपया कंस्ट्रक ान कार्य के लिये रखा गया है। इसका प्रभाव चिकित्सा के अन्य पदो पर पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं तो इस राय की हूं कि गांव गांव मे चिकित्सा सुविधाएं पहुंचनी चाहिएं 80 फीसदी जनता जो हमारी गांवो मे रहती है, उनको चिकित्सा सुविधायें मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजट के अंदर इस काम के लिये जितना प्रोविजन किया जाता है, उससे गांव और भाहरो के अंदर जितनी चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए वे नही दे पाते। सभापति महोदय, यही नही आज डाक्टर्ज के साथ भी भेद भाव बरता जाता है। 24 घंटे की ड्यूटी डाक्टर की हुआ करती है। अगर वह कभी औफ टाईम मे पिक्चर जाता है तो बताकर जाता है ताकि अगर कोई अमरजैंसी पड़ जाये तो उसे बुला लिया जाये। फिर उनके साथ भेदभाव क्यों ? सभापति महोदय, बेसिक क्वालिफिके ान के बाद ग्यारह साल और पढ़ने के बाद एक व्यक्ति अच्छा डाक्टर बनता है। जब उसे वेतन पूरा नही मिलता तो उसके मन के अंदर एक विद्रोह सा पैदा होता है। डाक्टर्ज के साथ सिलैक ान ग्रेउ हुआ करते थे लेकिन पे

कमी ान ने उनको काट दिया है। साथ ही उनका एन.पी.ए. भी बंद कर दिया है। इसका परिणाम क्या होगा ? कोई भी अच्छा डाक्टर सरकानी नौकरी मे नही आयेगा और लोगो को अच्छी डाक्टरी सेवा नही मिल पायेगी। मैं मानती हूं कि एच.सी.एस. आफिसर्ज को वेतन बहुत मिलना चाहिए। उनके काम की दृश्टि से उन्हे सम्मान भी मिलना चाहिए लेकिन पिछले दो तीन वर्शो मे दो बार उनके पे स्केल रिवाइज हो गये जबकि डाक्टर्ज ने नही हुए। उनको तो अब तो अब जो वेतन मिलता है पे कमी ान की रिकमैंडे ांज के अनुसार उससे भी कम वेतल नए स्केल्ज से मिलेगा। तो मेरी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह रिक्वैस्ट है कि डाक्टर्ज के साथ किसी प्रकार का अन्याय न किया जाये क्योंकि अगर हरियाणा प्रांत के अंदर चिकित्सा करने वाले चिकित्सक ही विद्रोही हो जायेंगे तो यहां लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और प्रांत की आर्थिक समृद्धि नही हो सकेगी।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नं. 11 पर बोलना चाहती हूं। अर्बन डिवैल्पमैंट को बड़ी बड़ी बाते होती है लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर सुधार मंडल के द्वारा जो योजानाएं चालू की गई थी वे आज भी पूरी नही हो पाई है। आप उन लोगो से पूछिए जो हजारो रूपये दे चुके है लेकिन आज तक उनको मकान नही मिले। कुछ को अगर मिले हुए है तो बना हुआ मकान कहीं से लीक कर रहा है और उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नही है। यमुनानगर मे मकान लेने के लिये हाउसिंग बोर्ड के

पास लोगो ने पैसे जमा कराए है लेकिन अभी तक जमीन ऐक्वायर नही की गई है मकान बनाकर देना तो दूर रहा । सभापति महोदय, जो गरीब आदमी अपनी तनख्वाह, व आमदनी आदि से स्वयं मकान नही बनासकता वह लोन आदि के लिये सरकार की तरफ देखता है लेकिन आज जब वह बजट के आंकड़ों की तरफ देखेगा तो सोचे गा कि इस सरकार के राज्य मे गरीब के लिये कोई स्थान नही है।

डिमांड नं. 12 के अंदर लेबर एंड ऐम्पलायमैंट की बात आती है। सभापति महोदय, सैल्फ ऐम्पलायमैंट स्कीम के तहत कुछ म्युनिसिपैलेटीज ने दुकाने बना कर दी थी। (विघ्न) इस तरह की दुकाने पानीपत,यमुनानगर और कई दूसरे स्थानो पर भी बनाई गई थी। नियम यह थास कि कोई भी आई.टी.आई. ट्रेंड, टैक्निीकल अनऐम्पलायड, यूथ जब चाहेगा तब ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज के माध्यम से उसे दुकान अलाट कर दी जायेगी। युमुनानगर मे इस तरह से 15 दुकाने दी गई । ऐडमिनिस्ट्रेटर ने 150 रूपये (125 रूपये कास्ट और 25 रूपये मुरम्मत आदि के लिये) तक किराया तय किया था लेकिन बाद मे किराया 300 रूपये कर दिया जबकि उसके साथ बनी हुई दुकानो का किराया 100 या 110 रूपये है। मैंने बीस बार लिख कर दिया कि उनका रिाया कम होना चाहिए लेकिन वह आज तक कम नही किया गया। आज उन गरीबो को बिजली नही मिल रही है, रा मैटीरियल नही मिल रहा है। चेयरमैन साहब, आप ही बताएं कि वे बैंको का कर्जा कैसे अदा करेंगे। मेरी

सरकार से प्राथ्रना है कि यह बेरोजगार यूथ को विद्राह की ओर अग्रसर न करे बल्कि उनको दुकानो का किराया कम करके, उनको मदद करके उन्हे भी सुख की सांस लेने दी जाये।

सभापति महोदय, कौन नही जानता कि यमुनानगर मे बिजली की कटौती बहुत ज्यादा है ? इसके बावजूद भी खाद्य एवं पूर्ति मंत्री जी ने कहा कि वहां डीजल पांच प्रति ात दिया जाता है। उन्होंने यह भ कहा कि वहां केवल 11 जैनरेटर्ज है।

मैं हाउस मे बताना चाहती हूं कि वहां सारे सब डिवीजन मे 2 हजार स्माल स्केल यूनिटस काम कर रहे है और केवल यमुनानगर मे 19 जनरेटिंस सैटस है, साढ़े चार सौ इंजन है लेकिन ये सारे के सारे स्टैंडस्टिल हैं उनको न डीजल मिलता है और न ही बिजली मिलती है। जब इन यूनिटस मे लेबर काम करने के लिये जाती है तो यूनिटस वाले कह देते है कि बिजली नही है इसलिये आज काम नही करना। उन यूनिटस को 15 दिन के अंदर केवल 60 घंटे बिजली मिली है। आप इस बिजली से अंदाजा लगाये कि यमुनानगर मे इंडस्ट्री की क्या हालत होगी ?

सभापति महोदय, मैं रोड्ज के बारे मे भी अर्ज करना चाहती हूं। एप्रोच रोडजतो गांवों को देने का सरकार का संकल्प ठीक है लेकिन गांवो के अंदर जो हरिजन बस्तियां है जिन्हें हरिजन माजरी आदि कहते है ये आमतौर पर इनटीरियर मे होती है। बरसात के दिनों मे वे लोग बिल्कुल नही निकल सकते है।

मेरे अपने हल्के मे भी हरिजन माजरी है उनकी भी यही पोजी ान है। जैसे गदोली माजरी, करेड़ा माजरी, इनके अंदर जल्द से जल्द लिंग रोडज बनायी जायें ताकि उन गरीबो को सुविधा हो सके।

इसी प्रकार से टापू कमालपुर है। वह गांव ऊंची जगह पर बसा हुआ है। उनके खेत सड़क से बहुत दूर पड़ते है। सड़क सारी डूब जाती है। महिलायें भाोच भी नही जा सकती है इसलिये ऐसे गांवो को एप्रोच रोडज से जरूर मिलाया जाना चाहिए। एक गांव नागल है जिसका स्कूल भाादीपुर रोड पर है। उस गांव का स्कूल तो सड़क पर है पर गांव वहां से कुछ दूर है। पिछले साल फल्ड मे स्कूल के आस पास इतना पानी आ गया कि एक चौकीदार भी डूब कर मर गया था। बच्चो के कश्ट का तो क्या कहा जाये वहां पर अध्यापक जाता हे, सड़के पर हाजरी लगा कर बच्चो को वापिस घर भेज देता है। ऐसी रोड़ज को प्रायरिटी बेसिज पर बनाया जाना चाहिए। ऐसी सड़कों मे नियम का खास ख्याल नही रखना चाहिएं मेरे हल्के मे पंचपूर गांव है। जब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर थे उनके नोटिस मे भी मैं यह बात लायी थी कि जो वहां पर आगमेंटे ान कैलान बनायी गई है उससे उनके खेत कट कर नहर के पार पड़ते है जिसके कारण उनको काफी दिक्कत होती है। इसलिये वहां पर एक फूट ब्रिज बनाया जाना चाहिए। पिछली सरकार ने इस पुल की योजना को स्वीकार भी किया था पर अभी तक कुछ भी हुआ नहीं कुरूक्षेत्र जिले के रादौर गांव के पास अलहार गांव मे कुछ

कुंड बने हुए है। बरसात के दिनों मे उनके आधा आदमी डूब जाता है। वहां पर सेम का पानी भरा रहता है इसलिये वहां पर भी पुल बनाने की योजना स्वीकृत भी, परन्तु जनहित के इस कार्य को प्रारम्भ नही किया गया।

इसके बाद मैं ला एन्ड आर्डर की डिमांउ नं. तीन पर भी अर्ज करना चाहती हूं। बहुत से साथियों ने हाउस मे कई घटनाओं की चर्चा की है। बहुत सारी बाते तो आ गई है लेकिन फिर भी मैं अर्ज करना चाहती हूं कि अगर ला एंड आर्डर की यही पोजी ान रही तो भारीफ आदमी के लिये रहना मु कल हो जायेगा। मुझे अभी चार पांच दिन पहले एक डैपुटे ान मिला। उसने बताया कि कालांवाली मंडी का चालीस वर्श का एक बृज लाल नाम का व्यक्ति गुम है, अब पता नही वह मिला है या नही। पहले उसको धमकियां भरे पत्र भी आते रहे है। इसी प्रकार से पिछले साल एक तीन साल के बच्चे को उठाया गया और मार दिया था। उसी प्रकार से उसकी भी ऐसी स्थिति न हो जाये।

सरदार सुखदेव सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्या को सच्चाई मालूम कर लेनी चाहिए। वह आदमी जिन्दा है। ये बोल * * * रही है।

श्री सभापतिः झूठ भाब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

श्रीमती डॉ. कमला वर्माः मुझे नही पता कि मिला है या नही। अगर मिल गया है तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे को एक डैपुटे ान मिला था उसने यह बताया था कि वह गायब है।

सरदार सुखदेव सिंहः यह गलत कह रही है।

श्रीमती डॉ. कमला वर्माः मेरे को तो डैपुटे ान मिला था। सरकार ने छानबीन कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नही मिला है तो कोि ा ा कर ले।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमेन साहब, जब वह तीन साल का बच्चा मारा गया था उस समय पर चौधरी देवी लाल चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और चौधरी वीरेन्द्र सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब एक हफ्ते पहले एक आदमी गुम हुआ था लेकिन दो दिन के बाद अपने आप वापिस आ गया था। (विघ्न)

श्रीमती डॉ. कमला वर्माः चेयरमैन साहब, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे है उनके बारे मे तो कहने का मेरा अधिकार है, कोई भी सरकार हो उसका यह कर्तव्य बनता है कि उनकी सुरक्षा करे। जिन हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, गोहाना मे जो लड़की का कत्ल हुआ है, हांसी मे जो घटनाएं हुई है या जो भी कोई डाकाजनी की या अन्य घटनायें हुई है, उनका प्रबंध करना तो सरकार की जिम्मेदारी है।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

श्री बलदेव तायल द्वारा

श्री बलदेव तायलः आन ए प्वायंट आफ परसनल एक्सप्लेने ान सर। कल सी.एम. साहब ने मेरे मे कुछ कहा था उस विशय पर बोलना चाहता हूं। मैं डिमांडज पर इस समय बोलना नही चाहता।

श्री सभापतिः मैं रिकार्ड से चैक करवा लेता हूं। आपको टाईम दे दूंगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, बलदेव तायल जी को आप समय दे दें लेकिन बाद मे मुझे भी थोड़ा सा टाईम दें।

श्री बलदेव तायलः चेयरमैन साहब, मुख्य मंत्री जी की सत्यप्रियता तो सारे हरियाणा मे म ाहूर है। इस बारे मे मुझे कुछ नही कहना है। जहां तक डिफैक ान का संबंध है इस बारे मे मेरे पितामह के और मेरे विचारों मे भिन्नता रही है। वैसे हम दोनो ही 19 महीने जेल मे इकट्ठे रहे है। इसमे कोई दो राय नही है कि उस वक्त भी वे मेरे पितामह थे और आज भी है लेकिन मैं इस गरिमामय सदन मे एक बात कहना चाहता हूं कि जब से मैंने जनता पार्टी जायन की है, मेरा पार्टी छोड़ने का कभी इरादा नही बना, न ही पार्टी छोड़ी और न ही पार्टी छोड़ने का इरादा रखता हूं। Chairmain Sir, I must say one thing—

"The birds abadon the tree when there are not ruits,

Swans abandon the direct lake,

Women abandon men, who are no longer rich;

Ministres abandon their rules, when

they are not more in power;

Bees abandon the stale flower;

Animals abandon the burnt forest;

People try to please for some selfish objectives;

who rules over whom", Chanakya says.

चौधरी भजन लालः चेयरमैन साहब, मुझे भी एक मिनट दे दे। अभी बलदेव तायल जी ने फरमाया कि न मेरा पार्टी छोड़ने का इरादा है और नही मेरा कभी इरादा हुआ थां जोक बात मैंने कही थी वह यह थी कि जब चौधरी रिजक राम पार्टी छोड़ कर जा रहे थे, वे मेरे पास हिसार मे आये कि मैं इस्तिफा देना चाहता हूं और ये पार्टी छोड़ना चाहते थे मुझे आप जाने दे। ये उस वक्त पार्टी छोड़ने को तैयार थे। यह हकीकत है उनकी पार्टी छोड़ने की।

Shri Baldev Tayal: No, I had never said that, I had never expressed a desire to leave the party (Insterruptions) Mr. Chairman, Sir, I must say one thing. Both Dr. Mangal Sein and Shri Balwant Rai Tayal are the witness. They requested Ch. Bhajan Lal not to accept my resignation when I resigned not once but twice and requested to be relieved as Deputy Chairman. Shri Balwant Rai Tayal is very much present here.

He should state the balwant Rai Tayal is very much present here. He should state the true facts about the meetig held in the P.W.D. Rest House, Hissar, if he has any guts.

Mr. Chairman: You personal explanation has come.

वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री भाम ोर सिंह (नरवाना): चेयरमैन साहब, बजट की जनरल डिस्क ान पर काफी अच्छे सुझाव सरकार के सामने आये है। (भाोर) मैं अपने हल्के के बारे मे 2–4 बाते अर्ज करना चाहता हूं। कल मैं नही कह सका था इसलिये मैं अब बोलना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नं. 8, 9, 10 तथा 11 पर संक्षेप मे बोलना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, नरवाना एक छोटा सा टाऊन है। वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम 10–12 साल पहले 10–12 लाख रूपये लगा कर बनाई गई थी। उस स्कीम का जो स्टोरेज टैंक है, वह नीचे बैठ गया है उसके कारण जो पानी सप्लाई होता है, वह काफी गंदा पानी आना भाुरू हो गया हैं चौधरी देवी लाल जी की सरकार के टाईम मे इस बारे मे मैंने एक काल अटैं ान मो ान भी दी थी और उस बजट पर बोलते हुए भी मैंने बार बार यह कहा था कि इस वाटर सप्लाई स्कीम को टेक ओवर किया जाये। 30 हजार के करीब आबादी का यक कस्बा है। मैंने इसी हाउस मे, जब सरदार लक्षमन सिंह मिनिस्टर होते थे, उस समय यह जिक्र

किया था। गवर्नमैंट की तरफ से यह अ यारेंस आई थी कि नरवाना वाटर सप्लाई स्कीम को म्युनिस्पिल कमेटी से लेकर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट टेक ओवर इसलिये करना था क्योंकि वहां की म्यूनिसिपल कमेटी के पास टैक्निकल नो हाऊ नही है। इस फैसले को हुए आज करीब दो साल हो गये हैं लेकिन आज तक उस स्कीम पर कुछ भी कार्यवाही नही की गई है। इसलिये मैं सरकार का इस बोर ध्यान दिलाना चहाता हूं कि यह जो तीस हजार का कस्बा है इस मे गन्दा पानी जाने से बिमारी फैल सकती हैं इसलिये जल्दी से जल्दी उसकी रिपेयर कराई जाये। चेयरमैन साहब, मेरे इलाके मे जो देहात है उनमे पीने के पानी की बहुत दिक्कत हैं पिछली सरकार ने इस बात को माना था कि नरवाना सब डिवीजन मे 80 फीसदी ऐसे गोंव हे जहां पर खारा पानी है उस वक्त श्री बीरेनद्र सिंह से मुझे एक पत्र भी आयाथा कि हम नरवाना की स्कीम को वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहज लेने जा रहे है। मेरी सारी कांस्टीच्यूएंसी का सर्वे भी करवाया गया लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनीतिक कारणो से, बाद मे उसको नही लिया गया। और किसी अन्य कान्स्टीच्यूएंसी को बर्ल्ड बैंक स्कीम के तहत ले लिया गया। में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 सालो मे मेरी कांस्टीच्यूएंसी मे कोई वाटर सप्लाई स्कीम नही दी गई। इसलिये मेरी कांस्टीच्यूएंसी मे जल्दी जल्दी वाटर सप्लाई स्कीम दी जाये ताकि वहां के गांवों के लोगों को अच्छा पानी मिल सके। जिन गांवों के लोगों ने अपना भोयर भी जमा किया हुआ है और वहां पानी भी

खराब है उसको जल्दी से जल्द भुरू किया जायें अब राठी साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि पिछले तीन सालो मे जो कमी रह गई हे उस कमी को पूरा कर दिया जायेगा।

चेयरमैन साहब, नरवाना म्यूनिसिपल कमेटी की भी बड़ी खराब हालत है। जैसे कि मैंने बताया है कि नरवाना एक छोटा सा कस्ब है। उसमे बहुत से हरिजन बस्तियां भी है। उनमे किसानों की भी बस्तियां है और कुछ अन्य लोगों की भी बस्तियां है। उन बस्तियों के अंदर न कोई लाईट का प्रबंध है और न ही कोई नाला आदि का प्रबंध है। नरवाना कस्बे की हालत एक बदतर गांव से भी बुरी है। इसलिये उस कस्बे की गलियों को पक्का किया जाये और लाईट आदि का प्रबंध किया जाये। मैं सरकार से यह भी दर्खास्त करना चाहूंगा कि नरवाना म्यूनिसिपल कमेटी के पास कोई आमदनी के साधन नही है। इसलिये सरकार नरवाना कमेटी को कोई स्पे ाल ग्रांट दे कर वहां पर लोगों की सुविधाओं के लिये काम कराये। पिछले आम चुनावों के दिनों मे मुख्य मंत्री जी ने एक लाख या दो लाख रूपये देने का एलान भी किया था। मैं चाहता हूं कि कम से कम 5–7 लाख रूपये उस म्यूनिसिपल कमेटी को दिये जाये ताकि वहां की बस्तियां को न्यूनतम सुविधाएं दी जा सके।

चेयरमैन साहब, नरवाना के बस स्टैण्ड की भी बहुत खराब हालत है। यह बस स्टैण्ड म्युनिसिपल कमेटी का बनाया हुआ है। वर्शा के दिनों मे वहां पर 4–5 फुट पानी खड़ा हो जाता

है। इस बस स्टैण्ड से 300 बसें रोजाना गुजरती है। मैं सरकार से अ यारेंस चाहूंगा कि वहां पर नया बस स्टैण्ड जल्द से जल्द बनाया जाये। मंत्री महोदय मेरे दोस्त भी है लेकिन उन्होंने जो बस स्टैंडज की लिस्ट दी है उस मे अब भी नरवाना बस स्टैण्ड का नाम नही है। मुझे मंत्री जी से उम्मीद है कि उसको ये प्रायरिटी बेसिज पर बनाये जाने पर ध्यान देंगे।

चेयरमैन साहब, एक बात और कहना चाहता हूं कि कल मैंने एम्पलायमैंट के बारे मे सुझाव दिया था, उसमे एक बात और ऐड करना चहता हूं। हरियाणा मे हजारो पढ़े लिखे नौजवान गांवो मे रहते है। जब हरियाणा के अंदर कोई जगह निकलती है तो उनको पता लग जाता है लेकिन जब कोई सैंट्रल या रेलवे मे कोई जगह निकलती है तो उनको पता नही लगता। इसलिये मेरी हरियाणा सरकार से गुजारि ा है कि गांवो और कस्बों के जो नौजवान है उनके लिये ऐसे गाईडैंस ब्योरो का प्रबंध किया जाये जो उनको इस बात के लिये गाईड कर सके कि कहां एग्जाम देना है, कहां पर वेकेंसी है ताकि वे उसके लिये एप्लाई कर सकें और तैयारी कर सकें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात के लिये जरूर कदम उठाये क्योंकि ऐसा करने से गरीबो के बच्चे ज्यादा से ज्यादा नौकरी पा सकेंगे।

चेयरमैन साहब, इसके साथ ही आखिर मे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । डिमांड नं. 1 विधान सभा के बारे मे है, चेयरमैन साहब, आपको खुद को भी पता हे कि एम.एल.एज.

फ्लैट्स मे फर्नीचर के बारे मे अढ़ाई तीन साल पहले सरकार ने यह कहा था कि हम इसके लिये कुछ पैसा देंगे। अब जो वहां पर फर्नीचर है वह 10–15 या 20 साल पहले का खरीदा हुआ है जोकि बिल्कुल टूट चुका है.....

श्री सभापतिः 25 साल पुराना है।

श्री भाम ोर सिंहः जी हां, 25 साल पुराना फर्नीचर है जोकि बिल्कुल टूट चुका है किसी भी फ्लैट मे फर्नीचर की कोई भी आईटम पूरी नही है और बड़ा पुराना फर्नीचर है। करीब दो तीन साल पहले सरकार ने यह कहा था कि हम इसके लिये कुछ पैसा अलाट करने वाले है। आज उस बात को भी तीन साल हो गये है और फर्नीचर की इतनी खराब हालत हो गयी है कि उस फर्नीचर से काम चलना बहुत मु कल हो गया है। कोई अपने घर से फर्नीचर ले आये तो बे ाक ले आये, वरना जो फर्नीचर मिला हुआ है, वह तो इस्तेमाल नही हो सकता। हम फ्लैटस का भी किराया देते है और फर्नीचर का भी किराया देते है। किराया जरूर कम है। किराया बे ाक और ज्यादा ले ले लेकिन एम.एल.एज. फ्लैटस को प्रौपर्ली फर्नि ा करने के लिये पूरा रूपया रखे। आखिर मे मैं ला एण्ड आर्डर के बारे मे एक बात और कहना चाहता हूं । हमारी जो पुलिस की म ानरी है वह टाप हैवी है। बहुत से डी.आई.जी. बनाए गए है और इसके अलावा दूसरे काफी अफसर और कर्मचारी भी है। चेयरमैन साहब, यह कहना कि हरियाणा मे ला एण्ड आर्डर सब अच्छा है, सब ठीक है, ऐसी बात

बिल्कुल नही है। इसमे अभी काफी इम्पूवमैंट करने की जरूरत है। इसके लिये मैं समझता हूं कि मेजर कारण अभी तक पूरी तरह से ठीक नही हुआ है। यह कारण है कि हरियाणा की पुलिस की जो टाप हीरारकी है, उसके अंदर पार्टीबाजी है, वह आपस मे लड़ती रहती है। यह कोई किसी से बात करता है तो पहले यह पूछता है कि आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हो। जब पुलिस वालों के अंदर ही यह बात हो कि वे पार्टीबाजी रखते हो, तो फिर उनसे इंसाफ की पब्लिक कैसे तव्वको कर सकती है। मुझे तो पुलिस की टाप हीरारकी के दिमागों मे भी कुछ खराबी नजर आती है, मैडीकली वे फिट नही है। उनका मैडीकली चैक अप भी करवा लेना चाहिए भाायद उन मे से किसी के दिमाग भी ठीक न हो। मैं इतना कहते हुए सरकार से दरख्वात करूंगा कि वे मेरी बातों की और सीरिसली सोचे और इनको ठीक करने की कोि ा ा करे।

श्री देवी दास (सोनीपत): चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं न तो गवर्नर ऐड्रैस पर बोला हूं और न ही बजट के ऊपर बोला हूं। अब मैं डिमांड नं 3, 8 और 10 पर बोलना चाहता हूं। डिमांड नं. 3 मे 15 करोड़ रूपया इस बजट के अधीन पुलिस के ऊपर खर्च करने के लिये रखा गया है। इसमे से एक करोड़ रूपया सी. आई.डी. यानी खुफिया पुलिस के लिये रखा गया है। मेरा अपना तजुर्बा है कि हरियाणा की खुफिया पुलिस सिर्फ पोलिटीकल लोगो की इंकवायरी करने और उनके आगे पीछे घूमने के सिवाए और

कोई काम नही करती है। सुजाता कांड जो गोहाना से सबसे बड़ा कांड हुआ था, उसका पता यह लगा सकती थी। लेकिन इसको तो पोलिटिकल आदमियों के पीछे घूमने से ही फुरसेत नही मिलती । इसके अलावा खानपुर मे अभी कांड हुआ है, सोनीपत भाहर के अंदर इतने कत्ल और डकैतियां होती रहती है, कभी सी.आई.डी. ने इनका सुराग निकालने की कोि ा ा नही की। चेयरमैन साहब, हम सी.आई.डी. एक करोड़ रूपया खर्च करने जा रहे है। मेरा कहना यह है कि ये लोग सिर्फ एम.एल.एज. पीछे घूमने, उनकी गतिविधयों को नोट करने के और काई काम नही करते। इसके साथ ही पुलिस के लिये एस.एच.ओ. से लेकर कांस्टेबल तक के लिये 10 करोड़ रूपया इस बजट मे मांगा गया है। मैं सोनीपत के अंदर हुए केसो की दो तीन मिसालें देना चाहता हूं। सोनीपत के अंदर अगर कोई चोनी हो जाये तो अब्बल तो मिलती नही अगर मिल जाये तो एस.एच.ओ. जब उस चोर से चोनी के बारे मे पूछता है तो अकसर चोर ठीक नही बताता कि उसने किसको माल बेचा है। चोर और दुकानदार जिसने चोर के माल खरीदा होता है, वे आपस मे मिले होते है। चोर सीधा एस.एच.ओ. को उस छोटे सुनारे की दुकान पर ले जाता है, जिसने उसका माल लेने से इंकार किया होता है। चोर जान बूझकर किसी ऐसे गरीब सुनारे का नाम ले देता है जिसका चोरी का माल खरीदने से कोई वास्ता नही होता। एस.एच.ओ. चोर के बताने पर सीधा पुलिस फोर्स लेकर उस गरीब सुनारे के पास पहुंच जाता है और उसको यह धमकी देता है कि अगर दो तोले सोना और 60 किलो चांदी भााम

तक न पहुंची तो तेरा चालान किया जायेगा। वह गरीब छोटा दुकानदार बेचारा मारा मारा एम.एल.एज. के पास फिरता है। अगर कोई एम.एल.ए. उस एस.एच.ओ. से टेलीफोन करके यह पूछे कि भई बता इसका कसूर क्या है जबकि सारे इलाके के मोहतबर आदमी यह कहते है कि यह ईमानदार है और इसने माल नही खरीदा। तो वह कहता है कि इसने तो चोरी का माल खरीदा है, चोर यह कहता है कि मैंने इसी आदमी को बेचा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कानून इस तरह से बनाया जाये ताकि किसी भी ईमानदार आदमी को नाजायज तंग न किया जा सके। पुलिस सिर्फ उसी आदमी से जाकर पूछे जिसके बारे मे उसके पपस पक्का सबूत हो कि उसने माल खरीदा है। जब इलाके के चार पांच मोहतबर आदमी यह लिखकर देते है कि इस आदमी ने चोरी का माल नही खरीदा है और उसके बावजूद भी अगर चोर है और वह असली दुकानदार जिसने वह माल खरीदा हुआ है, उससे मिला हुआ है। इसलिये मेरा कहना यह है कि इसके लिये कानून को चाहे जिस तरीके से भी बदलना पड़े, हमे बदलना चाहिए। हमारे सोनीपत मे तो इस वजह से ऐसे हालात हो गये है कि वहांपर कोई भी सुनारे की दुकान खोलने के लिये तैयार नही है। बैकवर्ड क्लासिज के लोग जो बोचारे छोटे छोटे गहने बनाते है, वे भी अपनी दुकाने बंद कर रहे है। नयी खोलने के लिये तो कोई तैयार नही है क्योंकि पुलिस उन लोगों को बिना वजह तंग करती है। मुझे सोनीपत कापता है कि वहां पर पुलिस के डर की वजह से सुनारों की दुकाने बंद हो रही है। वहां काएस.एच.ओ. जिसने उन

गरीब लोगो से रूपया वसूल किया है, अगर आप चाहे तो मैं उसका नाम बता सकता हूं।

अब मैं डिमांड नं. 10 के ऊपर आता हूं। डिमांड नं. 10 हैल्थ के बारे मे है। सोनीपत मे 150 बैड्स के हास्पिटल का एलान हो चुका है और उसके लिये जमीन भी एक्वायर हो चुकी है। जमीन एक्वायर होने के बाद जितनी जमीन ली गयी है और किजनी छोड़ी गयी है, मैं उस बात मे नही जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस काम के लिये सरकार का लाखो रूपया खर्च हो चुका है। इसलिये वहां पर जल्दी से जल्दी नया हास्पिटल बनाया जाना चाहिए। डी.एच.एस. आफिस जो चण्डीगढ़ मे है, तीन साल को मेरा अपना तजुर्बा है, एक आर्डर भी अगर सरकार का यहां से चला जाये जो वहां पर बैठे हुए क्लर्क की मर्जी है, उसको वह इम्पलीमैंट करे या न करे। यह बात सारे एम.एल.एज. भी जानते है, आप भी जानते है और मैं भी जानता हूं। दूसरा हरियाणा मे अस्पतालों को बूचड़खानो का नाम दिया जाता है। कहीं पर कोई बीमार चला जाये तो वह प्राईवेट अस्पताल का नाम पूछेगा, सरकारी अस्पताल मे कोई नही जायेगा क्योंकि उनको पता है कि वहां पर मरीज का इलाज होने तक हो सकता है उसकी जान ही चली जाये। सोनीपत वहां पर हस्पताल जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। चेयरमैन। चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांउ नंबर आठ पर आता हू। चेयरमैन साहब , 1977 से जब मैं एम.एल.ए. बना हुं। (व्यवधान)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, * * * *

* * * * *

(व्यवधान)

श्री सभापतिः यह सारी बात एक्सपंज कर दी जाये

(व्यवधान)

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): Chairman Sahib, these words are not in good taste and should be expunged.

Mr. Chairman: These words have already been ordered to be expunged.

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर (व्यवधान) मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि–

श्री सभापतिः आप बैठ जाइये (व्यवधान)।

श्री देवी दासः चेयरमैन साहब, मैं बता रहा था कि जब से मैं एम.एल.ए. बना हूं आज इस बा को तीन साल हो गये है मेरे हल्के मे म्यूनिसिपल कमेटी की सड़कों को छोड़कर एक किलोमीटर सड़क भी नही बनी है। हमारे मुख्य मंत्री जो पहले कोआप्रे ान मिनिस्टर थे, उस वक्त एलान भी करके आए थे कि ये सड़के जल्दी ही बना दी जायेगी लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे सड़के नही बनाई गई है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के मे दो सड़के पिनाना से सलादपुर

माजरा और चटिया से सांदल स्टे ान तक बनाने की कृपा करे। ये सड़के मंजूर हुई पड़ी है। इनके बारे मे जब ऐक्सियन से बत करते है तो जवाब मिलता है कि मिनिस्टर से बात करो। चेयरमैन साहब, इस बजट मे सड़को के लिये दस करोड़ रूपया रखा गया है, इसलिये सरकार को चाहिए कि जिन हल्को मे अभी तक एक किलोमीटर सड़क भी नही बनी है, वहां सब से पहले सड़क बनानी चाहिए।

जहां तक स्कूलों को अपग्रेड करने का सवाल है यह ठीक हे कि मेरे हल्के मे तीन स्कूल अपग्रेड कर दिये गये है इसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जब और डिमांड आएगी तो उन पर बोलने के लिये मुझे पांच मिनट ओर दिये जायें (व्यवधान) क्योंकि मैं न तो गवर्नर ऐड्रैस पर अभी तक बोला हूं और न ही बजट पर बोला हूं (व्यवधान)। चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता लेजिस्लेचर पार्टी के अंदर श्री मांगे राम गुप्ता ने कहा था कि चाहे आप सारे जनता पार्टी को नही छोडूंगा (व्यवधान)।

श्री सभापतिः आप डिमांड पर ही बोले।

श्री देवी लालः चेयरमेन साहब, ये कह रहे है कि चेयरमैनी कायम रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि एक साल तक चेयरमैन रहने का हमारा हक है और हमारी पार्टी ने कहा है कि चेयरमैन रहो। मैं सिद्धांत के लिये हजार चेयरमैनी छोड़ सकता

हूं। मैं इन लोगो की तरफ से नही हूं जिन्होंने गदि्दयों के लिये दलबदल किया है (व्यवधान)। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, बजट के अंदर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो दो लाख तक खरीद फरोख्त करने वाले दुकानदारो को सेल्ज टैक्स की असैसमैंट की छूट दी है इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। वैसे मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह छूट जनता पार्टी ने दी थी लेकिन इसका श्रेय चौधरी भजन लाल ले रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, अंत मे मैं दो बाते कहकर बैठ जाऊंगा एक तो यह है कि मेरे यहां अस्पताल बनना चाहिए जिसके लिये जमीन ऐक्वायर हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि सोनीपत से दूसरे प्रांतों को कोई बस नही जाती है। सिर्फ दिल्ली की बसें सोनीपत से जाती है और किसी दूसरे प्रांत को सीधी बसें नही जाती है। मेरी प्रार्थना है कि सोनीपत से दूसरे प्रांतो को बसे चलाई जाएं। धन्यवाद।

चौधरी हरि चुद हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चार दिन से अपने दोस्तों के विचार सुन रहा हूं। मैं डिमांड नंबर 2 पर अपने दोस्तों के लिये और जनता के लिये करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब का जो इंस्टीच्यू ान है, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। पिछले तीस साल मे, गवर्नर की जो पावर्ज थी वे कम कर दी गई और पैसा ज्यादा खर्च करना भुरू कर दिया। ये पावर्ज तो पोलिटि ायंज को चली गई लेकिन गवर्नर साहब के दफ्तर पर बहुत खर्च किया जाने लगां

डिप्टी स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान का, गुरबत और गरीबी मे दूनिया मे 125वां नंबर है। जो दे ा आजादी से पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, उस दे ा की आज हालत यह है कि वह संसार मे गरीबी के मामले मे 125वें नंबर पर है। मैं अपने दोस्तो को बताना चाहता हूं कि जो बजट होता हे वह गवर्नर ऐड्रैस का रिफलैक ान होता हैं बजट पर डिस्क ान होती है, डिमांडज आती है, फिर ऐप्रोप्रिए ान बिल आता है। ये सारी चीजें पिछले तीस साल से चल रही है। इसको बदलने की जरूरत है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला दे ा क्यों गुरबत के 125वें नम्बर पर है, इसका क्या कारण है ? डिप्टी स्पीकर साहब, इसका सब से बड़ा कारण है कि जो पे ा किया जाता है It is not a budget but a tug of war f economy between the rich sna the poor. The bureaucracy Govt. has always been on the side of the rich. Under these circumstances, income has never been distributed equally which is the main source of equality within this country.

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया भारतवर्श के सब से बड़े और महान नेता थे। उन्होंने हर जगह पर यह कहा कि यह जो न्दिुस्तान के बजट पे ा होते है, ये जनता को कंगाल बनादेंगे और हिन्दुस्तान का सत्याना ा कर देंगे। इस की सारी जिम्मेदारी डनहोंने कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहर लाल नेहरू पर डाली थी। इसके बाद दूसरी मिवाल देता हूं जे.के. हिकस की । तीसरी कुटे ान है श्री

बी.एन. गंगोली जी की और उसके बाद अगली कुटे ान है श्री गैडगिल साहब की। इन सभी के अपने अपने विचार थे, इन्होंने कहा था कि इस दे ा मे सिवाए क्र्प ान और गरीबी, कंगाली व भूखमरी के और कुछ नही होगा। इसका मेन कारण इस दे ा मे जो बजट पे ा होते है, उन पर डाला जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं यह बताना चाहता हूं कि 1947 के अंदर पाकिस्तान बना और इसका हवाला एक किताब 'फ्रीडम एट मिड नाईट' के पेज 224 पर दिया गया है। उसमे लिखा है कि * * * * * * डिप्टी स्पीकर साहब, उस वक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे श्री पटेल और फाईनैंस का विभाग श्री लियाकल अली खां जी को सौंपा गया था। हिन्दुस्तान के अंदर (विघ्न)

चौधरी खुर ाद अहमदः डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरे आनरेबल दोस्त हुड्डा साहब, जोकि बुजुर्ग है, ये बोल तो रहे है डिमांड नं.1 पर, जोकि विधान सभा से ताल्लुक रखती है पर वे इस की बजाये यहां पर हिस्टरी कह रहे है। नै ानल आरकाईवज के बारे मे कह रहे है। वे कौन सी डिमांड के साथ इसको कनैक्ट करते है। He should be relevant to the demands under discussion. (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी हरि चंद हुड्डाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान के अंदर क्या होता रहा। जब 1946 मे इंटैरम गवर्नमैंट बनी थी, उस वक्त मुहम्मद लियाकल अली खां के कहे अनुसार जितनी बड़ी बड़ी रैवेन्यू की पोस्टे थी, वे सारी की सारी हरिजनो को दे दी और बड़ी बड़ी पर टैक्स लगा दिये गये । यह भी कहा कि सारे हिन्दुस्तान मे इस से जातपात नही रहेगी और सो ालिजम आ जायेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, * *

* * * * * *

* * * *

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नंबर 8 पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आप अपनी स्पीच खत्म करे, आपका समय हो गया है।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः एक दो बाते कह कर मैं अपना स्थान लूंगा। मेरे हल्के मे छछरौली के पास एक सड़क है। छछरौली से बेचिराग मौजा तक वह सड़क जाती है। उस सड़क को जहां से लोग चाहते है, वहां से बी एण्ड आर वाले देते नही है और जहां से लोग नही चाहते है, वहां से बी एण्ड आर वाले देना चाहते है। आज से 10 साल पहले सरकार ने यह थोड़ा सा पो र्न गल्त बना दिया था, जिसके कारण लोगों को काफी तकलीफे हो रही है। इस गल्ती को छुपाने के लिये सरकार यह सड़क का सही टुकड़ा बनाना चाहती तो मेरा सरकार को सुझाव

है कि जिस तरह से गांव के लोग इस सड़क को चाहते है सरकार को चाहिए कि वहां से यह सड़क बना दी जाये ताकि लोगों को आने जाने मे किसी प्रकार की असुविधा न हो।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं यहां सरकार से एक और बात कहना चाहता हूं कि एक पुल है जिसका नाम है टटोली। यह पुल 10–15 साल पहले बड़ा टेढ़ा सा बन गया था। इस की तामीर पर भी बहुत सारी पैसा खाया जा चुका है। इस को मौके पर चौधरी भजन लाल और चौधरी देवी लाल जी, दोनो को दिखाया गया था और बताया गया है। उस वक्त श्री कक्कड़ भी वहां पर मौजूद थे लेकिन काफी समय बी चुका है, बी एण्ड आर वालो ने अभी तक इस पर कोई एक ान नही लिया है। सरकार से मेरी रिकवैस्ट है कि इस पुल की तरफ भी ध्यान दिया जाये ताकि गांवो के लोगो को, जिनको इस पुल से वास्ता पड़ता है, सुख का सांस मिल सके। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपध्यक्षः हुड्डा साहब, आप वाइंड उप करें।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे एक बात अंत मे कह कर मैं अपना भाशण खत्म करूंगा। गांवों मे प ाु धन बड़ा प्रिय होता है इसलिये कृशि के साथ साथ प ाुओं की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। किसानो को इससे काफी मदद मिलती है। गांवों मे प ाुओं को एक बीमारी लग जाती है और उस बीमारी को दूर करने के लिये एक टीका लगाया

जाता है, उसका नाम है इंटीसाईट। यह एक साल्ट का टीका होता है। जो डंगरों की सुरा की बीमारी का इलाज करता है। यह लोगों को अवेलेबल नही होता है और यह 60 रूपये की बजाये 100–100 रूपये ब्लैक मे बेचा जाता है। सरकार को पहले तो इस बात की रोकथाम करनी चाहिए कि किसानो के काम की वस्तुओ पर किसी किस्म की ब्लैक न हो। जो ब्लैक करते है उन पर एक ान हो। साथ ही सरकार को यह भी उचित प्रबंध करना चाहिए कि किसानो को समय समय पर ये सहूलियतें उपलब्ध हो सके ताकि किसानो की जो 5–5 और 10–10 हजार रूपये की भैंसे मर जाती है, उस नुकसान से वे रिजीफ पा सकें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, वाइंड अप करे।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आखिर मे इतना ही कहूंगा कि मंहगाई की वजह से इस वक्त हमारे दे ा मे 80 परसैंट किसान और मजदूर मर चुके है। इस कांग्रेस सरकार ने इन लोगो को तबाह करके रख दिया है। मेरा यह सुझाव है कि अगर आप इन लोगो को बुनियादी ढंग से ऊपर उठाना चाहते है तो चौधरी चरण सिंह जी की नीति को अपनाओ, और जो मैनीफैसटो लोकदल ने अपनी पार्टी का निकाला है, उसको अपनाओ, तभी आप इन गरीबों को ऊपर उठाने मे समर्थ हो सकते हो और हिन्दुस्तान को ऊपर उठा सकते हो। इन भाब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने

मुझे बोलने का समय दिया (ाोर) (इस समय कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये)

श्री उपाध्यक्षः श्री जगदी ा कुमार बैनीवाल। साहेबान, मैं यह कोि ा ा कर रहा हूं कि जो साहेबान बजट पर नही बोल सके, उनको अब बोलने का मौका दिया जाये।

स्मामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। * * * *

* (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः ये अलफाज सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिये जायें।

चौधरी जगदी ा कुमार बैनीवाल (दढ़ता कलां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले डिमांड नं. 2 पर बोलूंगा। इसके अंदर जुडि ाियरी और एग्जैक्टिव के पे स्केलज मे बहुत अंतर है और न ही जुडि ाियरी को एग्जैक्टिव के मुताबिक कोई सहूलियत मिलती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि जुडि ाियरी के पे स्केलज के बारे मे जरूर ध्यान रखा जाये और उनके साथ साथ न्याय किया जाये।

इसके बाद मैं डिमांड नंबर 3 के संबंध मे कुछ कहूंगा कि गृह विभाग से संबंधित है। पिछले साल 31–3–79 को चौधरी देवी लाल की सरकार ने डी.एस.पीज. के पे स्केल रिवाईज करने का वायदा किया था जोकि अब तक लागू नही किये गये है।

दूसरी बात यह है कि एक चौधरी राम स्वरूप इन्स्पैक्टर थे उनको दस हजार रूपये का एवार्ड दिया गया था जोकि बदले की भावना से वापिस ले लिया गया है। उन्होंने एक लाख रूपये की रि वत लेने से इंकार किया था इसलिये उनको यह दस हजार रूपये का एवार्ड दिया गया था । सरकार से मेरी निवेदन है कि वह एवार्ड उसको जरूर मिलना चाहिए। (विघ्न)

इसके बाद मैं डिमांड नं. 4 पर आता हूं। जिस तरह से पिछली सरकार ने बिजली का फ्लैट रेट तय किया था उसी तरह से पानी का भी घंटों के हिसाब से फ्लैट रेट होना चाहिए। चाहे 50 रूपये घंटा हो या 60 रूपये घंटा हो। ऐसा करने से किसान लोगों का बचाव हो सकेगा और एक दूसरे के नाम गिरदावरी का झगड़ा भी नहीं रहेगा।

इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 8, जो सड़कों के बारे में है, पर कुछ कहना चाहता हूं। मेरे हल्के दढ़वा कलां में जितनी सड़कों पर काम हो रहा था वह सारा रोक दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उन सड़कों पर दोबारा काम भाुरू करवाया जाए। दूसरे मैं कुछ सड़कें और बनाने के लिए सरकार से निवेदन करूंगा। वे हैं सहुवाला 2 से ताजिया खेड़ा और गुसाईयाना से खेड़ी तक। ये सड़कें जल्दी कम्पलीट की जाएं ताकि वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि जो एम. एल.एज. अपोजी ान में हैं, उनका काम चाहे न हो लेकिन पब्लिक का काम नहीं रूकना चाहिए, वह जरूर होना चाहिए।

इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 9, जो ि ाक्षा के बारे में हैं उस पर बोलना चाहता हूं। मेरे हल्के में दो–तीन स्कूल हैं जो डाउन ग्रेड कर दिये गये हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको फिर से अपग्रेड किया जाए। (ाोर एवं विघ्न) मैं सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री बलदेव तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका यान रूल 97 की तरफ दिलाना चाहता हूं और खास कर जो मंत्रिगण बैठे हुए हैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक आम सदस्य से ज्यादा जिम्मेदारी मंत्रिगण की है। वे इस हाउस को प्रोपरली और गरिमा के साथ चलाएं। रूल 97 में लिखा हुआ है:–

"Rule 97. Whilst the Assembly is sitting, a member:-

(i) shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the Assembly;

(ii) shall not interrupt any Member whil speaking by discrderly expression or noises or in any other disorderly manner....

(ix) shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt and shall not make running commentaries when speeches are being made in the Assembly."

श्री उपाध्यक्षः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा (विघ्न)

श्री बलदेव तायलः उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करने की आव यकता नहीं है। आपको पूर्णरूपेण इस गरिमामय

सदन में अधिकार है कि आप उनको हुकम दे सकते हैं, डायरैक्ट कर सकते हैं। यहां पर जो कांटिन्यूसली मंत्रियों द्वारा इन्ट्र ान की जाती है वह भाोभनीय नहीं है (ाोर)।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तायल साहब और संत कंवर जी ने एक अजीब बात की। ये दोनों नये मैंबर हैं। ये खड़े होकर रूल तो पढ़ देते हैं लेकिन इनको रूलों का पता नहीं है। लोक सभा के अन्दर भूतपूर्व स्पीकर सरदार हुकम सिंह की एक रूलिंग है कि जब तक मंत्री बैठा होता है तब तक वह मंत्री नहीं कहलाला है। जब वह जवाब देता है उस वक्त वह मंत्री कहलाता है। इसलिये जितना राइट इनका है उतना ही राइट हमारा हैं, ...।

श्री बलदेव तायल: उपाध्यक्ष महोदय, यह आव यक नहीं है कि जो पुराना मैम्बर हो वह आलम फाजिल हो (ाोर) कभी निरक्षर भट्टाचार्य इस सदन के मैम्बर रहे हैं, उनका जिक्र नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि उपाध्यक्ष महोदय के कहने के बाद किसी भी मंत्री या सदस्य को यह कहने का अधिकार नहीं है कि ....।

Mr. Deputy Speaker, by what he has said, he has cast an aspersion on the Chair. He may be asked to withdraw the remarks.

उपाध्यक्षः मेरा ख्याल है इन्होंने यह नहीं कहा था कि यह चलेगा। इन्होंने आपका एक बात की तरफ ध्यान आकर्शित

किया था कि इस प्रकार की, लोक सभा में स्पीकर महोदय की रूलिंग है कि जब कोई मंत्री खड़ा होकर डिबेट का जवाब दे उस वक्त उसे मंत्री ट्रीट किया जाए बाकी समय में वह मैम्बर के तौर पर है।

श्री बलदेव तायलः उपाध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में जो कुछ भी बोला जाता है वह रिकार्ड होता है। अभी मंत्री जी ने कहा कि .... यह एक्सपंज होना चाहिए (ाोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः यदि कोई भाब्द रिकार्ड में आया है तो मैं उसको एग्जामिन करूंगा और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि यह एक्सपंज किया जाए या नहीं।

चौधरी जगदी ा कुमार बैनीवालः डिप्टी स्पीकर साहब, जो उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने मेरे हल्के दढ़वा कलां के अन्दर स्कूल अपग्रेड किए थे इस सरकार ने उन स्कूलों को डाउन ग्रेड कर दिया है। डिप्टभ स्पीकर साहब, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर सबसे कम स्कूल मेरे हल्के के अन्दर हैं और आप रिकार्ड मंगवा कर देख लें कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम स्कूल अप ग्रे हुए हैं। यह अब की बात नहीं है, चौधरी बंसी लाल जी की और चौधरी देवी ला जी की आपस में बनती नहीं थी इसलिए इस जिले के अन्दर बहुत पहले से कुछ काम नहीं हुआ है। जिस समय चौधरी देवी लाल जी की सरकार बनी तो चौधरी भजन लाल की वजह से वहां पर काम नहीं हो सका। अब चौधरी

भजन लाल जी की हकूमत आई है जो उस वक्त भी उस जिले के बारे में एतराज किया करते थे, इसलिए उसी बेस पर चौधरी भजन लाल जी ने उन स्कूलों को डाउन ग्रेड कर दिया। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो चार गांवों के नाम बताता हूं, जिनके अन्दर बहुत ज्यादा स्कूलों की जरूरत है। जैसे रूपावास और गुर्सावाणा है, इन गांवों के स्कूलों को डाउन ग्रेड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से स्कूल अपग्रेड करने के बारे में जो नार्मज निर्धारित किए हुए हैं, इन गांवों के स्कूल वे सारे नार्मज भी पूरे करते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन गांवों के स्कूल जल्दी से जल्दी अपग्रेड किए जाएं ताकि वहां ि ाक्षा का काम सुचारू रूप से चल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमान्ड नम्बर 10 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे हल्का दढ़बा कलां में डिंग चौपटा में एक 50 बैठ का हस्पताल उस समय की जनता पार्टी की सरकार का मंजूर किया हुआ है लेकिन उस पर अभी तक काम भाुरू नहीं हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, जिन गांवों के नाम मैंने अभी बतायें हैं, यह चौपटा उन गांवों के सैंटर में पड़ता है और इस चौपटे में मंडी भी बनने वाली है। तो मरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर हस्पताल जल्दी से जल्दी बनाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मेरे हल्का दढ़बा कलां में जो डिस्पैंसरी है, उसकी हाल बहुत खराब है, उस डिस्पैंसरी की बिल्डिंग बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है। उस डिस्पैंसरी के अन्दर किसी सर्वेन्ट के रहने के काबिल भी

कोई कमरा नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस डिस्पैंसरी की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी ठीक करायसा जाए ताकि वहां का काम ठीक ढंग से चल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं डिमान्ड नम्बर 13 जोकि समाज कल्याण के बारे में हैं, पर कुछ कहना चाहता हूं। इस डिमान्ड के बारे मे मेरा सरकार से इतना ही निवेदन हैं कि मेरे हल्के के अन्दर पानी की बहुत कमी है। जिन गांवों के अन्दर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके नाम मैं आपके सामने बताता हूं। जैसे सहीदांवाली, नटार, दढ़बा कलां, जमाल, कागदाणा, तरकांवाली, डिंग मंडी और बकरियांवाली। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी सरकार से दरख्वास्त हैं कि मैंने जिन गांवों के नाम बताए हैं उनके अन्दर जल्दी से जल्दी वाटर सप्लाई करवाने की कृपा करें।

चौधरी नारायण सिंह (पटौदी–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एजूके ान की डिमान्ड पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एजूके ान के बारे में जो कुछ कदम उठाए हैं, वे बहुत ही सराहनीय कदम हैं। मेरे हल्के में एक कमला नेहरू कालेज है, उसको गवर्नमैंट ने टेक ओवर कर लिया है। इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वह कालेज बिल्कुल ही बंद होने जा रहा था और इस सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैने उस समय की

जनता पार्टी की सरकार से एक निवेदन किया था कि मेरे हल्के में एक दो लड़कियों के स्कूल हैं, उनको अपग्रेड किया जाए। उस समय की जनता पार्टी की सरकार में आर्य साहब एजूके ान मिनिस्टर होते थे, इन्होंने मेरे से कहा कि हो जाएंगें। उन गांवों के नाम फरूख नगर और करौला है। उन गांवों के स्कूल सारी जरूरतें पूरी करते थे लेकिन वे आज तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि पिछली दफा भी मेरी कांस्टीच्यूऐंसी में एक ही स्कूल अपग्रेड हुआ था कि और कांस्टीच्यूऐंसीज में दो दो स्कूल अपग्रेड हुए थे। मेरी कांस्टीच्यूऐंसी में नूरगढ़ गांव के स्कूल को अपग्रेड किया गया था इसके अलावा और कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमान्ड नंबर 10 पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सफाई कर्मचारियों के लिए जो 50–50 रूपए बढ़ाए है, उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का भाुक्रगुजार हूं लेकिन साथ में मैं एक यह अर्ज भी करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब उस आर्डर में यह करा दें कि जो 50–50 रूपए बढ़ाए गए हैं, वे सिर्फ बाल्मीकियों को ही दिए गए हैं। इस पैसे के लिए सिर्फ सफाई कर्मचारी ही एनटाईटल्ड हैं और कोई भी कर्मचारी एनटाईटल्ड नहीं है, मैं आपकी मारफत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सफाई मजदूरों को जो 50 रूपए बढ़ा कर दिए गए थे वे फरूख नगर और पटौदी क म्युनिसिपल कमेटियों ने, पिछले महीने

से बंद कर दिए हैं। वे कहते हैं कि ये पैसे सरकार ने सिर्फ 6 महीने के लिए दिए थे। इसलिए मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि वह पैसा उन सफाई मजदूरों के लिए आगे भी जारी रखा जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, तीसरी बात बड़ी जरूरी है। फरूखनगर और उसके आस पास छोटे छोटे कस्बे हैं। इन कस्बों में भौचालय जाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। इन कस्बों में लैटरीन्ज का इन्तजाम करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार औरतो को सड़कों पर ही बैठ जाना पड़ता है। इसके बारे मं मैंने डी.सी. को भ कहा था कि लैटरीन्ज बनवाई जाएं। उन्होंने कहा था कि बनवा देंगे लेकिन अभी तक इसकी इम्पलीमैंटे ान नहीं हुई है। मैं सरकार से गुजारि ा करूंगा कि ऐसे कस्बों में लैटरीन्ज का अव य प्रबन्ध किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हरिजन वैल्फेयर स्कीम के तहत एक परिवार के लिए जो दो हजार रूपया रखा गया है, यह बहुत कम है, यह कम से कम पांच हजार होना चाहिए। इतनी थोड़ी सी रा ि ा से हरिजनों का भला नहीं होने वाला। कम से कम पांच हजार कर दिया जाए तो बेहतर होगा। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

मास्टर जोगी राम (असंध अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग सं. 8 से 13 तक बोलना चाहता हूं। मैंने कई बारे बोलने की को ि ा ा की लेकिन मेरे कुछ भाई मेरे से पहले उठ

जाते थे और मेरी बात बीच में ही रहा जाती थी। सबसे पहले मैं डिमांड नं. 9, जो एजुके ान के बारे में है, पर बोलना चाहता हूं। आज हरियाणा में ि ाक्षा की स्थिति बड़ी भाोचनीय है। मैं निजी रूप से ि ाक्षा के बारे में जानता हूं, इस विभाग में काम करने वाले अध्यापकों की तन्खाहें और अन्य सुविधायें बहुत कम हैं, उनके साथ हमे ाा अन्याय होता आया है। मैं सरकार का ध्यान इस विश की ओर वि ाश रूप से आकर्शित करना चाहता हूं। देहातों में, खास तौर पर प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक, काफी मेहनत करने के बाद, काफी पैसा खर्च करने के बाद अध्यापक का रूप धारण करते हैं। उसके बाद कक्षाओं को पढ़ान के लिए जब वे विद्यालय में प्रवे ा लेते हैं तो उनके सामने वि ोश समस्याआं का बवंडर खड़ा होता है। वह सोचता है कि कोरी स्लेट के रूप में छोटा सा बच्चा तेरे सामने आया है, उसको इन्सान बनाना है। इसके साथ ही साथ उसक सामने घरेलू समस्यायें भी हैं, रोटी का मसला है, मकान का मसला है और दूसरी समस्यायें हैं जो उसको हर वक्त सताती रहती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह छोटी कक्षाओं को पढ़ाने वाला अध्यापक जो छोटे छोटे बच्चों का भविश्य बनाता है, उसका वेतन दूसरे अध्यापकों के मुकाबले में कम क्यों हैं ? इन अध्यापकों की तन्खाहें, माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ान वाले अध्यापकें से कम हैं। जहां तक मैं समझता हूं, जो अध्यापक छोटी छोटी क्लासिज को पढ़ाते हैं, उनका वेतन, उन अध्यापकों से ज्यादा होना चाहिए जो बड़ी क्लासिज को पढ़ाते हैं।

इन छोटे अध्यापकों को, बच्चों के मां बाप अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए सौंपते हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन मं बताना चाहता हूं कि देहातों के अन्दर, इन छोटे अध्यापको के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। दूसरे कर्मचारियों की तरह इनको मैडिकल भता नहीं दिया जा रहा। इनकी सर्विस पन्द्रह पन्द्रह साल की हो गई है लेकिन किसी को मैडिकल भता नहीं मिलता भाहरों के अन्दर जो बड़े और छोटे अधिकारी रहते हैं या वे लोग जो कालेजिज में लैक्चरार हैं, वे अपनी बन्धी हुई तन्खाह से काफी ज्यादा पैसा और लेते हैं। उनको मैडिकल भता मिलता है लेकिन गांवों में पढ़ाने वाले प्राथमिक अध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है। इन अध्यापकों को फ्लैट रेट पर मैडिकल भता दिया जाना चाहिए। इनीक तन्खाह का 5 प्रति ात या 10 प्रति ात जो भी सरकार उचित समझे, उनको वेतन के साथ मैडिकल भता मिलना चाहिए। मुझे आ ाा है कि सरकार इस तरफ गौर करेगी। इसके अतिरिक्त, बड़े बड़े कस्बों मे ंया दूसरी जगहों में जो अध्यापक रहते हैं उनको हाउस रेंट नहीं मिलता। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि देहातों और कस्बों में जो अध्यापक हैं, उनको हाउस रेंट दिया जाए। इसके बाद मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। भानिवार को स्कूलों में मीटिंग्ज होती हैं। सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिस पर हर साल तीन चार लाख रूपया खर्चा होता है। अध्यापक भानिवार को मीटिंग करने के लिए जाते हैं और पीछे क्लास ि ाक्षा से रहित हो जाती

है। इस मीटिंग में अध्यापक कोई रचनात्मक काम नहीं करते, वास्तव में इस मीटिंग से किसी को कोई फायदा नहीं है बल्कि जो रूपया खर्च होता है उसका दुरूपयोग होता है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी राम कि ान पदासीन हुए) ये अध्यापक कोई रचनात्मक काम नहीं करते। बजाये इसके कि दस बीस अध्यापक इकट्ठे हो जाएं, अपनी व्यक्तिगत बाते करें और व्यर्थ में समय नश्ट करें, और कोई काम नहीं होता। मेरा सरकार को एक सुझाव है कि ये मीटिंग्ज बंद कर दी जाएं ताकि पैसे का दुरूपयोग न हो।

अब मैं डिमांड नं. 12 के बारे में बोलना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, हरियाणा में लेबर की समस्या बड़ी अहम है। आज बेकार पढ़े लिखे लोग भी है। कई गांवों में अनपढ़ मजदूरों को ठीक तरह से मजदूरी न मिलने के कारण बहुत झगड़े हो रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि सरकार ने देहातों में मजदूरों की मजदूरी तो नि चत कर दी है लेकिन तहसील और जिला स्तर के अधिकारी इन बातों को, इन निर्दे ाों को गांवों तक क्यों नहीं पहुंचातें। ये बातें गांवों तक पहुंचाने में ये अधिकारी क्यों मदद नहीं करते ? अगर ये सब बातें गांवों तक पहुंचें तो मजदूर और जमींदार के बीच मे जो झगड़ा होता है, वह नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुरूक्षेत्र में भाना नाम का एक गांव हैं जिसमें पिछले डेढ़ साल से हरिजनों के ऊपर बन्दी लगी हुई है। गांव के लोगों

ने उनका बाई काट किया हुआ है और सरकार की जानकारी में यह बात लाई जा चुकी है। यह चौधरी देवी लाल के वक्त की बात है, उनके नोटिस में यह बात आई थी लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहं दिया। (विघ्न) मेरे भाई संत कंवर जी वैसे ही उतावले हो रहे हैं। मैंने तो किसी पोलिटिक्स में पड़ना चाहता हूं, न किसी की आलोचना करना चाहता हूं। जब मेरी कोई आलोचना नहीं करता तो मैं भी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं खुद उस गांव में गया हूं। बी.डी.ओ., एस.डी.एम. और डी.सी. को वहां बुलाया गया था, सभी लोगों को इकट्ठा किया गया था। (विघ्न) दो साल हो चुके हैं लेकिन अब भी वहीं स्थिति है। गांव के जो मजदूर हैं, हरिजन है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे सारे के सारे दिहाड़ी करने के लिए दूर कस्बों मे जा रहे हैं, दसूरे गांवों में अपनी दिहाड़ी के लिए जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि उन लोगों के मुफाद के लिए वह पाबन्दी हटाई जाए।

चेयरमैन साहब, अपने हल्के के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी मेरे हल्के में मूनक और असन्ध दो जगह गए थे और वहां पर बस स्टैन्ड बनाने की बात इनके सामने आई थी। वे वहां मंजूरी दे आए थे लेकिन अभी तक वहां काम भाुरू नहीं हुआ है। परिवहन मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वे कृपया इस काम को जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मेरे हल्के में एक मूनक ड्रेन है। उसके ऊपर पुल नहीं बना हुआ है। उस गांव की आधी जमीन उस ड्रैन से इधर है और आधी जमीन ड्रेन से उधर है। लोगों को अपने खेत में जाने के लिए दो किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। तो मेरी आई.पी.एम. साहब से गुजारि ा है कि वे इस ड्रे पर पुल अव य बनवा दें।

सभापति महोदय, म ुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी जब मेरे हल्के में गए थे तो मूनक से बौहली माइनर की मंजूरी देकर आए थे लकिन वे उसे बनवा न पाए। इसलिए मैं अपने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ये कृपया उसे बनवाने का कश्ट करें।

चेयरमैन साहब, अब मैं सदन का ध्यान एक वि ोश बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आज इस समाज के अन्दर एक साधनहीन है और एक साधन सम्पन्न है। एक के पास उत्पादन के साधन है और एक साधनहीन है। जो लोग यह समझते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत ताकत रखते हैं वे यह न भूलें कि जो भूखा मर रहा है, जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है वह एक दिन मजबूर होकर जिनके पास है उनसे छीन लेगा। (ाोर) सभापति महोदय 240 करोड़ रूपये के बजट के अन्दर 20 करोड़ या 24 करोड़ रूपया बैकवर्ड क्लासिज औरहरिजनों के ऊपर खर्च होना चाहिए था लेकिन केवल 60 लाख रूपया खर्च हो रहा है। जब इस क्लास की आबादी सारी

पापुले ान की 20 परसैंट बताई जाती है तो बजट की भी 20 परसैंट रा ि ा इनके ऊपर खर्च होनी चाहिए थी। (घंटी)

सभापति महोदय, मैं एक बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं। हरिजनों के उपर अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं। (विघ्न) बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है। (विघ्न) मुख्य मंत्री जी तो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं लेकिन नीचे जो अफसरान हैं एस.पी. और डी.सी. वगैरह ऐसा लगता है उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता। वे जातिवाद के जहर में फंसे हुए हैं। (ाोर)

श्री सभापतिः आर्डर प्लीज।

मास्टर जोगी रामः चेयरमैंन साहब, आखिर में मैं डिमांड नं. 8 के बारे में एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी अब आए हैं। असन्ध के अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. का एक सब–डिविजन हैं। उसे डेढ़ साल से कोई काम नहीं मिला है। मुझे पता है कि एस.ई. उस सब डिविजन का सारा काम ऐक्सियन करनाल से करवाता है। वहां के ऐक्सियन, एस.डी.ओ. और दूसरे सारे कर्मचारी खाली बैठे हैं। यही कारण है कि असन्ध पानीपत सड़क पर आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। (विघ्न)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापतिः बलदेव तायल।

सरदार सुखदेव सिंहः सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिन मैम्बर्ज को अभी तक टाईम नहीं मिला है उनको भी टाईम दिया जाए।

श्री सभापतिः सबको टाईम मिलेगा, आप चिन्ता न करें।

श्री बलदेव तायल (हांसी): सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने यह जो बजट पे ा किया है यह घाटे का बजट है। डिमांड नं. 1 पर बोलते हुए मैं आपका और इस सदन का ध्यान बढ़ती हुई कीमतों की ओर आकर्शित करूंगा। किसी भी दे ा के अन्दर जब तक घाटे का बजट रहेगा तब तक मुद्रा स्फीति होना आव यक है। मुद्रा स्फीति से यानी केवल कागजी मुद्रा के आधार पर किसी सरकार का चलना बिल्कुल ही अर्थ विहीन है। सभापति महोदय, घाटे के बजट को पूरा करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि कर लगाए जाएं। मैं वित्त मंत्री महोदय को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा की जनता को करों से राहत देकर कुछ न कुछ भला काम किया है परन्तु साथ ही एक बात की चेतावनी भी देता हूं। अगर इस किस्म के बजट आते रहे तो मंहगाई इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब जनता पिस कर रह जाएगी। डिमांड नं. 1 में सभापति महोदय, पहली आईटम मंत्रिपरिशद की है। इसमें लिखा है कि 6658400 रूपये मिनिस्ट्री के ऊपर खर्च किए जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस खर्च में कटौती की जा सकती है और कटौती करने से बजट का घाटा भी कम हो सकता है। सभापति जी, कहीं ऐसा न हो कि मंत्रिमंडल को घटाने की बजाए बढ़ाना भुरू कर दें और यह खर्चा 60 लाख से एक करोड़ हो जाये। मैं आपके जरिए मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि मंत्रिपरिशद को छोटा करके खर्चे को घटाया जायें।

12.00 बजे

चेयरमैन साहब, दूसरी मद लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग एक बहुत ही लाभकारी इन्स्टीच्यू ान है परन्तु कुछ सालों से इसकी गरिमा दिन प्रति दिन हरियाणा की जनता में गिरती जा रही है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि इस आयोग के अन्दर जितने भी व्यक्ति अप्वांयट किये जायें वे हरियाणा प्रदे ा के प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिए। उन पर हरियाणा की जनता यह सन्देह न कर सके कि मुख्य मंत्री के कहने से, मेरे कहने से किसी और की सिफारि ा से सिलैक ान हुआ है। सभापति महोदय, इन्साफ केवल मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि जनता में इसकी भावना पैदा होनी चाहिए। सरकार कोई ऐसे कानून या रूल्ज बनाये कि जितने भी आयोग में व्यक्ति नियुक्त हों वे रूल्ज के मुताबिक हों। वे रूल्ज भी ऐसे हों जिससे सरकार भी कुछ न कुछ बन्धी हो।

तीसरे जो सचिवालय का खर्चा यानी सामान्य सेवाओं का खर्चा हैं, इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी भी सीनियर ब्योरोक्रेसी है वह पिछले 7–8 महीनों से तकरीबन स्टैन्डस्टिल हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक पोजी ान है कि एक चपड़ासी का ट्रांसफर भी कोई बड़ा अधिकारी अपनी कलम से नहीं कर सकता है, सारी सता मंत्री और मुख्य मंत्री जी के हाथ मे आ चुकी है। इस बारे में केवल इतना ही कहूंगा कि ब्योरोक्रेसी को पोलिटीकलाइज नहीं होना चाहिए। उनको पोलेटिक्स से ऊपर उठकर सीधा निर्णय देना चाहिए। दे ा आज बड़े गम्भीर संकट में जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि दे ा बचे, जनता को राहत मिले तो इनको स्वयं फैसला करना पड़ेगा, कोई मंत्री फैसले के विरूद्ध जाता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी।

अब मैं डिमान्ड नम्बर तीन जो निर्वाचन के बारे में है, पर अर्ज करना चाहता हूं। निर्वाचन के बारे केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले इलैक ान में यह देखन में आया है कि सैंकड़ों वोटरों के नाम काट दिये गये और उनके वोट नहीं बनाये। वे वहां पर पांच दस साल से रह रहे थे लेकिन सैंकड़ों ऐसे आदमियों के नाम लिख लिए और वोट बना दिये गये जिनका वहां से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण चीज है इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से मांग करूंगा कि यह इलैक्टोरल रोल बिना भेद भाव के तैयार किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा पुलिस क व्यवहार के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं। कहीं ढानी मे, कहीं ख्चाानपुर में, कहीं हांसी के मिल मजदूरों की निरीह स्त्रियों के साथ केस हो रहे हैं लेकिन पुलिस विभाग उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से ढानी पीरान में एक माइनर लड़की का केस हुआ हैं जब इतना पुलिस पर खर्चा हो फिर भी वह उस बारे में सतर्क न हो तो यह प्रदे ा के लिए ठीक नहीं। पुलिस का फर्ज बनता है कि गरीबों पर और हरिजनों पर अत्याचार न हो। इस बात पर अंकु ा रखना पुलिस का फर्ज बनता है। छोटी बालिका के साथ इस प्रकार बलात्कार करना बड़ी दु:खदायी बात है। सभापति महोदय, पुलिस निरंकु ा हो तो रूल आफ अनारकी प्रिवेल होगा।

आज सारे हरियाणा में आतंक फैला हुआ है। कहीं बलात्कार, कहीं डाका और कहीं कत्ल हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं जनता को खुद कानून अपन हाथ में न लेना पड़े। मैं आपके जरिए निवेदन करूंगा कि जिनते भी बलात्कार के कांड है, इनकी इन्कवायरी मुख्य मंत्री महोदय चाहे अपने लैवल पर कायें, चाहे सदन की मार्फत करायें या चाहे जुडि ायरी की मार्फत करायें।

जेलों के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं कि जो जेलों के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं चाहे वे जेल वार्डर हैं, हैडवार्डर हैं उन सबकी ड्यूअीज पुलिस के बराबर ही होती है। उनकी तन्खाह भी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के

बराबर होनी चाहिए। इसलिए इस बात पर गम्भरतापूर्वर विचार किया जाये।

डिमान्ड नम्बर पांच एक्साइज एन्ड टैक्से ान के बारे में है। अभी कल ही अम्बाला में एक ठेके की आक ान हुई है। वह आक ान पिछलजे साल से 12 लाख रूपये कम में गया है। मैं आपके जरिए वित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्शि करना चाहूंगा कि जब सरकार ने लिबरल पालिसी अख्तियार की है तो फिर इस ठेके की नीलामी बढ़नी चाहिए थी, गिरी क्यों है ? जहां जहां भी आक ान होती है वहां पर इस बात की जांच करें। इस केस के अन्दर भी मुझे गोलमाल लगता है और फेवरटिज्म भी लगती है।

सभापति महोदय, मैं डिमान्ड नम्बर सात के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। हरियाणा सरकार की बड़ी भारी प्रैस है। वैसे तो वह प्रैस सरकारी सेवा करने के लिए है लेकिन उससे और भी पैसा उपलब्ध किया जा सकता है। मेरी मांग है कि इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये।

चेयरमैन साहब, मैं एक बात और सड़कों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। कहीं पर अगर सड़कें बनती हैं तो बड़ा सुन्दर काम है। अगर मुख्य मंत्री या मंत्रियों के हल्कों में आव यकता से अधिक सड़कें बनती हैं और दूसरे सदस्यों के हल्कों में बहुत कम मात्रा में सड़कें बनती हैं तो फिर भी इसके बारे में एक जस्टीफिके ान जरूर रहती है कि कहीं पर तो सड़कें

बनं यानी जनता का काम तो हुआ। लेकिन एक सजै ान मैं इस बारे में जरूर रखना चाहूंगा कि सड़कें बनाये जाने का कोई क्राईटेरिया अव य बनाया जाना चाहिए। सड़कें चाहे पापुले ान के हिसाब से या डुप्लीकेट रोड़ के हिसाब से बनाई जाये लेकिन कोई क्राईटेरिया जरूर फिक्स होना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक सिंगल रोड़ पूरी नहीं होती तब तक डुप्लीकेट रोड़ पर अंकु ा रखा जाये। यदि कहीं पर गिल रोड बनायी जानी है तो पहले वहां पर ही बनाई जाये। इन भाब्दों के साथ चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ?

श्री भागी राम (ऐलनाबाद–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मैं डिमांड नं 8–9 के बारे में खासतौर से अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मै आपका ध्यान जिला सिरसा में रानिया कस्बे की ओर दिलाना चाहता हूं। जिस समय चौधरी देवी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो वे रनिया गए थे। उन्होंने वहां बाजीगरों के मुहल्ले में जाकर यह एलान किया था कि जो यहां पर धानक, हरिजन और बाल्मीकि आदि जातियां सी हुई है, उनकी गलियों को पक्का करने के लिए दो लाख रूपये इस मुहल्ले को दिए जाते हैं। यह अनांउसमेंट चौधरी देवी लाल जी ने उस समय की थी जब वे मुख्य मंत्री थे। लेकन मुझे बड़े दु:ख के साथ्ज्ञ कहना पड़ रहा है कि अब चौधरी भजन लाल जी

के आने के बाद पता नहीं वह पैसा कहां चला गया। इसी प्रकार से रनियां कस्बे के अन्दर एक जोगी बस्ती है। वहां पर सपेरे रहते हैं उन लोगों ने बीन बजा बजा कर धर्म ाला के लिए 5 हजार रूपये इकट्ठे किए थे। जब चौधरी देवी लाल जी उनकी बस्ती मं गए थे तो वे उन लोगौं को धर्म ाला बनाने के लिए 15 हजार रूपये देकर आये थे। इस प्रकार से वह रा ि ा 20 हजार हो गई थी। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह पैसा सिरसा में पड़ा ह। चुनाव के दौरान उनसे यह कहा गया कि अगर वोट देंगे तो तुम का पैसा दे देंगे वरना नहीं। यह सरकार हरिजनों के साथ गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। इसी तरह से मैचिंग ग्रांटस की बात है। धनुर गांव में 40 हजार 5 सौ रूपये स्कूल के लिए मैंचिंग ग्रांट दी थी लेकिन इस सरकार ने उस गांव को अपने पैसे वापिस लेने पर मजबूर किया। मेरे सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि पंचायत ने उस पैसे को वापि ले लिया है, इसलिए यह स्कूल नहीं बन सकता। इसी प्रकार से केहरवाला कुसर को मैचिंग ान्टस दी गई थी यह ग्रांट भी चौधरी देवी लाल जी देकर के आये थे। उसको भी इस सरकार ने खत्म कर दयिा है। इसी तरह से हमारे एरिया के अन्दर चौधरी देवी लाल जी ने जो काम भाुरू किए हुए थे या जिन कामों के लिए पत्थर रखे हुए थे वे अब सारे के सारे बंद कर दिए हैं।

अब मैं डिमान्ड नं. 8 की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सड़कें

नई नई मंजूर की जाती है। लेकिन जो पहले से मंजूर भुदा सड़कें हैं उन्हें बनाये जाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं एक सड़क का नाम बताना चाहता हूं। वह है मौजूखेड़ा। इस सड़क को चौधरी देवी लाल जी ने मंजूर किया था। इस सड़क पर ईंटें भी डाल दी गई थी लेकिन अब चौधरी भजन लाल जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद उस सड़क से ईटों को उठवा लिया गया है। इसी तरह से हाबोली से 8 बुर्जी घुमोड़ा थेड़ सड़क पर गांव वालों ने मिट्टी डाल दी थी। यह सडक भी चौधरी देवी लाल जी ने बनवानी भुरू की थीं। लोगों ने 30–30 ट्रैक्टरों को लगा कर उस सड़क पर मिट्टी डाली लेकिन चौधरी भजन लाल जी की सरकार के आने के बाद उन सड़कों पर कोई काम नहीं हो रहा। चेयरमैन साहब, गांव में जो मजदूर अपने बच्चों को रोटी तक नहीं दे सकते थे वे भी एक–एक महीने तक लगातार मिट्टी डालते रहे ताकि यह सड़क पक्की हो जाये। लेकिन इस सरकार के आने के बाद वह बनानी बंद कर दी गयी। इसी प्रकार से करीआला से रानिया, रानिया से सुलतानपुर और रानिया से ढ़ाणी सतनाम सिंह की सड़कें भी कई बार मंजूर हुई लेकिन आज तक, कोई काम भुरू नहीं हुआ। करीआला से बणी सड़क पर मिट्टी डाल दी गई थी। अगर वह मिट्टी ऐसे ही पड़ी रही तो वह जाया हो जायेगी। इसी तरह नकोड़ा से नगराना रोड पर भी मिट्टी डाल दी है।

चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए सरकार से मांग करूंगा कि जिन सड़कों को मंजूरी चौधरी देवी लाल जी ने दी थी, उन सड़कों को जल्द से जल्द पूरा किया जाये। यदि उनके द्वारा मंजूर भाुदा सड़कों को बन्द रखेंगे तो लोग आपके खिलाफ ज्यादा होंगे।

चेयरमैन साहब, अब मैं थोड़ा ि ाक्षा के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में ि ाक्षा की बहुत कमी है। इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने 4–5 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया था (ाोर)

लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 4–5 स्कूल अपग्रड किये गये थे, व अब डाउन ग्रेड कर दिये गये हैं। यह हमारे साथ धक्का किया जा रहा है। (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापतिः कोई भी सदस्य बगैर परमि ान के बोलने का कश्ट न करे। (व्यवधान व भाोर)

श्री भागी रामः चेयरमैन साहब, ...

श्री सभापतिः चौधरी भागी राम जी, अब आप समाप्त कीजिये। आपका टाईम हो गया है।

श्री भागी रामः चेयरमैन साहब (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापतिः आप चेयरमैन कहने पर ज्यदा टाईम लगाते हो, डिमान्ड पर कम बोलते हो जरा जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री भागी रामः सिरसा जिला में ि ाक्षा की बहुत कमी है .....।

Mr. Chairman: No repetition please.

चौधरी भजन लालः सभापति महोदय, इनके बाद जो माननीय सदस्य इस हाउस में अब तक नहीं बोले हैं, मेहरबानी करके उनको समय दें।

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री भागी रामः मेरे जिले में 40 हाई स्कूल हैं और मेरे ख्याल में 50 मिडल स्कूल हैं जबकि दूसरे हरेक डिस्ट्रिक्ट में करीब 150, 175 या 200 स्कूल है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि जो स्कूल अभी डाउनग्रेड कर दिये गये हैं, उनको दोबारा अपग्रेड कर दिया जाये और इसके अलावा अगर वे 5–7 स्कूल और अपग्रेड कर दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। (व्यवधान व भाोर) (घंटी)

सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी): चेयरमैन साहब, मैं डिमान्ड नं0 पर कुछ कहना चाहूंगा। विधान सभा में पिछले दिनों स्पीकर साहब ने आ वासन दिया था कि जो विधान सभा के एम्पलाईज हैं, उनके ग्रेडज के बारें में वे सिम्पैथेटिक रूख

अपनायेंगे। इसके लिये मुझे बहुत खु ाी हैं और इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके अलावा मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। डिमान्ड नं0 1 में जो एम0 एल0 एज0 के लिये कर्जे का प्रवधान हैं उसके लिये रूल्ज कुछ ऐसे आकवर्ड हैं कि भाायद कोई भी लोन ले ही न सके। चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल से एक भी एम0 एल0 ए0 ने लोन लेने के लिये दरख्वास्त नहीं दी होगी। अगर किसी ने दी होगी तो उसको लोन नहीं मिला नही हैं। इसलिये मेरा कहना यह हैं कि वे दूसरों की बात को गौरसे सुनें। मै जो कुछ भी कहूंगा कम से कम ठीक ही बात कहूगा। अब मैं डिमान्ड नं0 3 हमारी गवर्नमैट ने पुलिस वालों की तनख्वाह में जो सुधार किया हैं, उससे ला एण्ड आर्डर में बड़ा सुधार हुआ हैं। हमारी पुलिस अब पहले से अच्छी तरह से मुस्तदी से काम कर रही हैं। हमारे एक सदस्य ने यहां पर खड़े होकर कालांवाली का जिक्र किया। माननीय सदस्य को, मैं यह अपील करूगा कि कहानियों नही घड़नी चाहिये। उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहनी चाहिए थी। उन्होंने यह कहा कि वहां पर एक आदमी को उठाकर ले गए। पता नहीं उन्होंनें कौन–कौन सी कहानियां बताने की कोि ा ा की,लेकिन वह हरकत में आयी और दूसरे दिन ही ाअदमी मिल गया। उसको ट्रेस कर लिया गया हैं। इस बात के लिये मैं अपने मुख्य मंत्री महोदय जी को घन्यवाद देना चाहता हूं । मै अपने अपोजी ान के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि किसी दूसरी स्टेट की कोई कहानी यहां पर बताने की कोि ा ा न करें। जो कहानी वे बतायें, कोई बात ज्यादा बढ़ा–चढ़ा कर न

बतायें। सच्चाई की बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमैंट ला एण्ड आर्डर को काबू करने के लिये बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। इसके लिये मैं इनको मुबारिकबाद देना चाहता हूं। एक सुजै ान भी मैं देना चाहता हूं। (व्यवधान एंव भाोर)

इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, श्री कन्हैया लाल पोसवाल, पदासीन हुए)

चौधरी जगदी कुमार बैनीवालः आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। इलैक ान के दौरान एक आदमी को इन्होंने सरेआम थप्पड़ मारा था, यह तो ला एण्ड आर्डर की पोजी ान हैं। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं।

सरदार सुखदेव सिंहः पुलिस के आदमी दफतरों में काम करते हैं, उनका पहले कुछ ग्रेड्ज में फर्क होता था, यानी जब वे फील्ड में होते थे तो कुछ ज्यादा मिलता था लेकिन जब वे दफ्तर मं आ जाते थे, तो उनको कुछ कम तनख्वाह मिलती थी। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, ये लोग ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं लेकिन इनको किसी ऐसी बात का तो पता ही नही। हमारे मुख्य मंत्री जी ने , हमारी इस कांग्रेस पार्टी की गवर्नमैंट ने यह किया हैं कि उनको बराबर पे दी जायेगी। उनके साथ जो पहले डिस्क्रिमे ान होती थी कि फील्ड में तो एक आदमी को जैसे एस0

एच0 ओ0, एस0 आई0 ए0 एस0 आई0 हैड कांस्टेबिल या कांस्टेबल को ज्यादा तनख्वाह मिलती थी लेकिन ज्यों ही वह दफ्तर में आता था, उसकी तनख्वाह कम हो जाती थी, वह समाप्त कर दी हैं। इसके लिये भी यह गवर्नमैंट बधाई की पात्र हैं।

अब मैं डिमान्ड नं0 5 के बारें में कुछ कहना चाहूगा। अपोजी ान के साथियों ने यह कहा कि ठेके कम पैसे से नीलाम हुए हैं। मेरे साथी बलदेव तायल जी ने यह कहा कि ठेके की रकम में कुछ कमी आयी हैं। चेयरमैन याहब, आप देखिये, एक तरफ तो ये कहते हैं और नारा लगाते हैं कि भाराब को बन्द करना चाहिए। चेयरमैन साहब, कमी तो उस वक्त आयी थी जिस वक्त स्टेट को गल्त एक्साईज पालिसी की वजह से 15 करोड़ रूपये का घाटा हुआ था। हमने 50–60 एम0 एल0 एज0 ने यह लिख कर दिया था कि यह पालिसी गलत हैं, इससे दे ा का भट्ठा ही बैठ जायेगा और हरियाणा का तो बहुत ही ज्यादा नुक्सान होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हैं कि उन्होंनें जबरदस्ती उस पालिसी को लागू किया जिससे स्टेट को 15 करोड़ स्प्ये का नुक्सान किसकी वजह से हुआ। स्टेट का इतना बड़ा नुक्सान कर दिया और फिर ये सरकार को क्रिटीसाईज करते हैं कि ठेके कम पैसों में नीलाम हुए है। ये हमे ाा चौधरी देवी लाल के टाईम की बात करते हैं। हो सकता हैं इस साल अकाल की वजह से नीलामी से कम रैवेन्यू आया हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन भाइयों को सोच समझ कर यहां पर बात कहनी

चाहिए वैसे ही एललगे ान लगााना भाोभा नहीं देता। मैंने एक दिन क्वै चन आवर के दौरान यह बात प्वांयट आउट की थी। एक बात के लिये हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उसने एक भी नया टैकक्स नहीं लगाया। हरियाणा में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान भर में लोग इस बात को एप्री ीयेट कर रहे हैं। (व्यवधान) मास्टर जी, आप तो मेरे पुराने साथी हैं, मैं पुराने जनसंघ की बात नहीं दोहराऊंगा। मैं घटकवाद की बात नहीं करूगा, डरिये नही। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा मे पहले ही काफी ज्यादा टैक्सिज लगे हुए हैं। उनकी पूरी रिकबरी होनी चाहिएं। कोई व्यक्ति अगर दोन नवम्बर का काम करता हैं तो उसे रोकने की पूरी कोि ा ा की जाएगी यह मुझे सरकार की तरफ से यकीन हैं। नाजायज भाराब के बारे में जो एक्साईज की पालिसी बनी हुई हैं, उसके बानने में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां एक्साईज वालों को ये पावर्ज नहीं हैं कि वे अकेले ही उस जगह पर रेड कर सकें जहां पर नाजायज भाराब निकलती हो। उनको पुलिस को साथ लेना पड़ता है। जब तक वह पुलिस का इन्तजाम करते हं तब तक उन लोगों को पता लग जाता हैं। चेयरमैन साहब, पुलिस को एडमिनिस्ट्रे ान कायम रखने, गुंडागर्दी को राकने और बादमा ाों को पकड़ने में काफी समय लग जाता है और जब एक्साईज वाले पुलिस कील मदद के लिए डिमान्ड करते हैं तो पुलिस स्पेयर नहीं हाती। इस बारे में मेरा सुझाव हैं कि जिस तरह से राजस्थान में हैं उसी तरह से यहां भी करत दिया जाए। चयेरमैन साहब, राजस्थान में ऐसा हक्ं कि एक्साईज

वाले बिना पुलिस की मदद के डायरैक्ट ही नाजायज भाराब निकलाने वालो पर रेड करते हं। इस डिपाटमैंट मे एक सैल खोल दिया जाए जिसका काम रेड करने का हो। चेयरमैन साहब, ऐसा करने से डिपार्टमैंट ज्यादा रेड कर सकता हैं।

चयेरमैन साहब, अब मैं डिमान्ड नम्बर 8 के बारे में कहना चाहता हू। मेरे से पहले कॉफी साथी इस बारे में बोल चुके हैं और कही–कहीं का नाम लेकर

बता रहे थे कि इन जगहों पर सड़क को नहीं रोका। यहजां तकि कि चुटाला में जहां के लिए पहले लाखों रूपया बजट में रखा गया था, वे सड़के भी बन रही हैं, उनको रोका नहीं गया हैं। कोई ऐसी सड़क तो हो सकती हैं जिसको किसी के खेत में निकाला जा रहा हो और उस आदमी ने इस जुल्म के खिलाफ कोई अपील की हो, उस सड़क को रोक दिया गया हो। जैसे कि मेरे खेत में सड़क निकाली जा रही हो मैं हाई कोर्ट मैं चला जाऊं और स्टे ले लूं। इस प्रकार की जो सड़क रोकी गई हैं उसक लिए मैं मिनिस्टर साह ब को धन्यवाद दनेा चाहता हू। अगर कहीं भी ऐसा किया गया हैं, वह पब्लिक इन्ट्रैस्ट में किया गया हैं, किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के इंट्रैस्ट में नहीं किया गया हैं।

चेयरमैन साहब, अब मैं एजुके ान के बारें में कहना चाहता हूं। मेरे भाई यहां काफी भाारे कर रहे थे कि हमारे हल्कों

में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। चेयरमैंन साहब, असल बात तो यह हैं कि कहीं पर चौदह स्कूल अपग्रेड हुए हैं, कही पर पांच स्कूल अपग्रेड हुए हैं। हरेक कांस्टीच्यूएंसी में कुछ न कुछ स्कूल अपग्रेड हुए हैं या नए खुले हैं। लेकिन यहां ये कह रहे थे कि कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ और न ही कोई नया स्कूल खोला गया। ऐसी बात कहना बड़ा अफसोसनाक हैं। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में तीन स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि जो दस–बारह स्कूल अपग्रेड नहीं किए गए वे क्राइटैरिया को पूरा नहीं करते थे इसके लिए इनको अफसोस नहीं करना चाहिए। चयेरमैन साहब, मैं इस बारें में एक बात और कहना चाहता हू कि मेरी कांस्टीच्यूएसी में अस्सी गांव हैं और केवल दो हाई स्कूल हैं। इनकी बिल्डिग्ज पचास साल पुरानी हैं और पिछले बीस साल से इनको खतरे वाली बिल्डिग घोशित किया हुआ हैं। इन दोनों बिल्डिंग को बनाने के लिए सी0 एम0 साहब ने एलान भी किया था लेकिन वे अभी बनी नहीं हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना हैं कि इन स्कूलों की बिल्डिग्ज को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए (व्यधान)

श्री सभापतिः अब आप खत्म करिए।

सरदार सुखदेव सिंहः चेयरमैन साहब, अब मैं अर्बन डिवैल्पमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। पुरानी गवर्नमैंट ने इस बारे मे मेरे हल्के को इग्नोर किया था। इस समय काफी बिल्डिग्ज

बन रही हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना हैं कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी की तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए।

डिमान्ड न0 9 के बारे में एक खास बात कहना चाहता हूं कि बडी़ खु ाी बात कहना चाहता हूं कि बड़ी खु ाी की बात हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जात –पात में वि वास नहीं करते। पहले जो सरकार थी वह पंजाबी के बारे मे बहुत बात करती थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। हमारे ये पुराने साथी भी पंजाबी के बारे में काफी बोलते हैं लेकिन ये कुछठ भी नहीं करना चाहते। मैं ि ाक्ष मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पंजाबी भाशा के लिए वि ो ा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री फतेह चन्द बिज पानीपतः चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का टाईम दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन साहब, मैं डिमान्ड नम्बर 6, 8, 9, और 11 के बारे में बोलना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, 1966 में हरियाणा और पंजाब और कुछ दूसरे मैम्बरान देहात और भाहर का सवाल उठाते रहे हैं। बजट के अंन्दर अगर किसी मैम्बर साहेबान कहने लगते हैं कि फलां भाहर के लिए इतना पैसा क्यों दिया जा रहा हैं (व्यवधान) आपके सामने एजुके ान के बारे में कई सवाल आते हैं जिनमें पूछा जाता था कि भाहरों में तो स्कूल गवर्नमैंट बनाती हैं और देहात में स्कूल की बिल्डिंग गांव वालों को बनानी पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता हैं। चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि भाहर किसी भी प्रान्त की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मरेर उन भइयों को भाहरों

की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। पिछले साल जब बजट पे ा किया गया था तो हमारे वित्त मंत्री बाबू मूल चंन्द जैन थे। उस वक्त आपने देखा होगा कि अपोजी ान और ट्रेजरी बैन्चिज के कुछ मैम्बर्ज ने उस बजट की कापियां फाड दी थी और उस वक्त यह कहा गया कि यह भाहरी बजट हैं। चेयरमैन साहब, भाहर किसी भी प्रांत की इकौनमी के लिए रीढ़ क हड्डी होते हैं इसलिए इनकी तरफ वि ोश ध्यान देने क ीजरूरत हैं। भाहरों के लिए जो ग्रांट दी जाती थी उसमें भी कुछ तबदीली करने की जरूरत हैं। चेयरमैन साहब, पिदले दिनों चौधरी देवी लाल पानीपत गए थे। उनके एक दोस्त ने उनको ब्रेकफास्ट पर बुलाया। जब वे ब्रेकफास्ट के लिए गए तो उन्होंनें देखा कि जगह–जगह पर सड़के टुटी हुई हैं, नालियों का पानी बाहर आ रहा हैं। वे कहने लगे कि यहां की हालत तो बड़ी खराब हैं। उसके बाद जब वे चण्डीगढ़ आए और कुछ म्युनिसिपल कमेटियों को पचास लाख रूपया दिया तो उनको याद दिलाया गया कि आप पानीपत की हालत को भूल गये। उस म्यूनिसिपल कमेटी को भी कुछ पैसा दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। चेयरमैन साहब, हालत आज यह हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने भाहर को दस लाख रूपया दें देंगे और दूसरे मिनिस्टर भी अपने–अपने भाहर को पांच–पांच लाख रूप्या दें देंगे और जो बाकी जो भाहर में रहते हैं उनको एक पाई भी नहीं मिलती। चेयरमैन साहब, पानीपत एक ऐसा भाहर हैं जहां पर पचास करोड़ रूपया का सालाना माल तैयार होता हैं और दूसरे प्रदे ाों को जाता हैं। तीस करोड़ो का माल फारेन कन्ट्रीज को

जाता हैं। आप किसी भी डिपाटमैटल स्टोर में चले जांए वहां पर आपको पानीपत के खेस और चाद मिलेगी लैकिन ग्रांट काह यह हाल हैं कि पिनछल`दसा साल से एक पैसा भी ग्रांट की भाक्ल में पानीपत को नहीं दिया गया। मेरी सरकार से प्रार्थना हैं कि ग्रांट बांटते समय इस चीज का ध्यान रखें कि जिन भाहरों को पहले ग्रांट दे दी गई हैं, उनको दोबारा न दी जाए और जिनको पहले ग्रांट नहीं दी गई हैं उनको दी जाए।

चेयरमैन साहब, अब मैं अख्तियार फण्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बारे में मैंने एक सवाल पूछा था कि तीन साल में अख्तियारी फण्ड में किस–किस म्युनिसिपल कमेटी को कितना–कितना दिया गया। इसका जवाब मुझे यह दिया गया कि यह इन्फर्मे ान फील्ड से कलैक्टर करनी पड़ेगी और यह मु कल काम हैं। चेयरमैन साहब, अख्तियारी फण्ड में से जो भी मिनिस्टर कहीं पैसा देता हैं उसकी सारी डिटेल्ज डिवैल्पमैंट कमि नर के दफ्तर में होती हैं। वहां से यह इन्फर्मे ान आ सकती थी कि फलां जगह फलां मिनिस्टर ने इतना रूपया दिया लेकिन मुझे यह जवाब दिया गया कि यह इत्तालह इकट्ठी नहीं की जा सकती। चयेरमैन साहब, सरकार ने यह इत्तलाह मुझे नहीं दी जबकि पिछले तीन–तील सालों की वह इत्तलाह सरकार के पास हैं, इन्होंनें केवल टालने वाली बात की। मेरी आपके द्वारा अपने हल्का मैं 10 प्रति ात से ज्यादा ग्रान्ट न दे और बाकी जो 90 प्रति ात पैसा हो वह स्टेट के दूसरे भागों मे लगाया जाए, क्योंकि यह पैसा

उनकी अपनी मर्जी पर नहीं होता कि एक ही हल्के में खर्च कर दें। इस फण्ड का यह मतलब होता हैं कि यह पैसा सारी स्टेट की बहबूदी के लिये खर्च किया जाए।

श्रम उप मंत्री(चौधरी लाल सिंह): चेयरमैन साहब,सरकार ने मुझे 26 तारीख को पानीपत में भेजा था और इनके हल्के मे मैं हजार रूपये की ग्रांट की अनाउंसमैंट कर के आया हूं।

श्री फतेह चन्द विज: चेयरमैन साहब, मैंने मिनिस्टरों के बारे में कहा, डिप्टी मिनिस्टरों के बारे में नहीं कहा। इससे अगो मैंचयेरमैन साहब, सड़को के बारे मुं कहना चाहता हूं। 1960 में यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण जिला मुजफ्फनगर के कुछ गांव हरिनयाणा में भाामिल हो गये, कुछ पानीपत में चले गये, कुछ करनाल में चले गये। इस स्टेट को बने कम से कम 20 साल का टाईम हो गया लेकिन आज तक उन गांवों में कोई सड़क नहीं बनाई गई हैं, जिस वजह से इन गावों के साथ कोई लिंक नही हैं। उधर यू0 पीव के लाग ऐसे हैं जो कि रोजाना नमाज पढ़ने के बाद खुदा से हय दुआ करते हैं कि बाढ़ आये और कुछ गांव इधर यू0 पी0 में मिल जाए। लेकिन इधर हमारे साथ यह सलूक हो रहा हैं कि कोई पूछने वाला नहीं। वहां पर किसी प्रकार की कोई सड़के का प्रीवीजन नहीं हैं। ये मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं जबकि ये मरे साथ इन इलाकों में गये तो यूं ही मगरमच्छ के आसूं बहाने लग गये कि आपक यहां पर कोई सड़क नहीं हैं। वहां पर एक हकीम साहब बैठे थे कहने लगे आप वोट वाली बात करेा।

20 सालों से ये लोग आ रहे हैं ओर कहते हैं कि सड़के बनायेंगें, घर सब कुछ वहीं का वहीं हैं, मुझें पर एक भोर याद आ गया

उमरे दराज मांग कर लाये थे चार दिन

दो अरजू में कट गये दो इन्तजार में।

श्री सभापतिः विज साहब, अब आप वाइंड–अप करें।

श्री फतेह चन्द विजः मेरा कहने का मतलब यह था कि अभी तक उन गांवो के साथ सड़को का किसी किस्म का लिंक नहीं हैं। मैंन मिनिस्टर साहब से यह नूछा कि आप वायदा करके आये थे तो अब आप इन गावों को सड़को से मिलवा दीजिए ताकि इनल गावों का लिंक दूसरी जगहों के साथ जुड सके। तो वे कहने लगे कि इनेा बनाने के लिये सीमेंट वगैरह और दूसरा मैटीरियाल नही मिल रही हैं। अब देंखगे कि सरकार इस बारे मे क्या पग उठा सकती हैं। इतनी बात कह कर टाल दिया। मेरा आपके द्वारा सरकार से यह निवेदर है कि सरकार इस तरफ अव य ध्यान दें।

इससे आगे चेयरमैन साहब, मैं एक बात और अपने एजुके ान मिनिस्टर व चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सरकार तबादलों के मामले में थोड़ी सी तबदीली लाए। खास कर एजुके ान डिपार्टमैंट में, क्योंकि यह जो 12 महीने ही तबादले होते रहते हैं यह बच्चो की पढ़ाई के साथ एक किस्म का खिलवाड़ होता रहता हैं और बच्चों की पढ़ाई खराब हो

जाती हैं। मेरा सुझाव है कि इसके लिये वक्त मुकर्रर कर दें कि इस वक्त पर तबादले हुआ करेंगे।

श्री सभापतिः गुड–सुजै ान।

श्री फतेह चन्द विजः होता क्या हैं, चैयरमैन साहब, एक आदमी की ट्रांसफर हो जाती हैं, दूसरा जाकर के स्टे ले आता हैं और उसके बाद उसी जगह के लिये तीसरा आ जाता हैं। मुझे पूर्ण आ ाा हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस तरफ ध्यान देंगे और इस में तबदीली जरूर करेंगे (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी पानीपत से दरियां, बैंड भीट्स और भी कई किस्म का सामान बाहर जाता हैं। और करोड़ो रूपये का वहां पर बिजनैस हैं। वहां पर आज से चार पांच साल पहले डिवैल्पमैंट के नाम से एक पार्क बनाया गया था जिस पर लगभग 30–35 लाख रूपया भाहर की डिवैल्पमैंट के लिये लगा दिया जाता तो भाायद भाहर की काफी तरक्की हो सकती थी। म्यूनिसिपल कमेटी का सारा पैसा इस पार्क पर ही लगा दिया जाता तो भाायद भाहर की काफी तरक्की हो सकती थी। म्यूनिसिपल कमेटी का सारा पैसा इस पार्क पर जो सड़के और नालियां हैं, वहां से बदबू मारती हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, वे जब वहां से गुजरते हैं तो मुंह के आगे रूमाल रख लेते हैं। स्पीकर साहब, आप कभी वहां जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पार्क में एक रिजस्टर रखा होता हैं, उसमें आने वाले अपना नाम दर्ज करते हैं। कि वहां पार्क में एक रजिस्टर रखा होता हैं, उसमें आने

वाले अपना नाम दर्ज करते हैं। मु कल से 100–110 आदमी राजाना वहां पर जाते होंगे और वह भाहर एक लाख से ज्यादा आबादी का हैं। इसलिये आगे से सरकार को चाहिये कि वहां की डिवैल्पमैंट के लिये कम से कम 20–25 लाख रूपया रख तकि वहां पर जो सड़कें और नालियां टूटी फूटी और गन्दी पड़ी हैं, उनको दोबारा बनाया जा सकें। अगर ऐसी जगह पर सफाई वगैरह का ध्यान न रखा गया तो वहां बहुत सी बीमारियों भी फैल सकती हैं। सरकार से मेरा बार–बार निवेदन हैं कि सरकार इस तरफ अव य ध्यान दें। (ाोर)

इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये

Mr. Speaker: I will give chance to every body but one by ony, one from treasury benches and oner from oppostion benches.(interrruption).

मैम्बर साहेबान, पहले कट मो ांज का नोटिस आया हुआ था इसलिये मैंने गिलोटीन का टाइम 1 बजे रखा था। चूकिं यह मूव नहीं हुई इसलिये यदि हाउस सहमत हो तो थोड़ा समय और डिस्क ान के लिए दे दिया जाए। उसके प चात् वित्त मंत्री के जवाब के बाद डिमांडज पर वोटिंग होगी।

आवाजें: ठीक हैं जी।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, मेरे पास उन महानुभावों की लिस्ट हैं जिन्होंनें इस डिबेट में बिल्कुल पार्टीसिपेट नहीं किया हैं। अगर वे बोलना चाहेंगे तो सब से पहले उनको बोलन `ाक मौका दिया जाएगा। मैं वह लिस्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं।

ट्रेजरी बैचिज

(1) चौधरी सुरेन्द्र सिंह (2) श्री के एल0 पोसवाल

(3) श्री सुमेर चन्द भट्ट (4) चौधरी भाकुरूल्ला

(5) चौधरी पीर चन्द (6) चौधरी जिले सिंह

(7) श्री राम कि ान (8) राव दलीप सिंह

लोकदल

(1) श्री प्रताप सिंह राठी (2) चौधरी टेक राम

(3) श्री जय नारायण वर्मा (4) चौधरी कर्मसिंह

(5) चौधरी ओम प्रका ा राणा (6) श्री मनी राम

(7) चौधरी फूसा राम

जनता पार्टी

(1) चौधरी जय नारायण (2) श्री मूल चन्द मंगला

(3) श्री फतेह चन्द विज

चौधरी पीर चन्द (रतिया–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 1,2,4,8,12 और 13 पर बोलूगां। स्पीकर साहब, जो बजट हमारे सामने वित्त मंत्री जी ने पे ा किया हैं ऐसा बजट मैंने आज तक कभी नहीं देखा क्योंकि यह पहला बजट पे ा किया गया हैं जिसके अन्दर कोई कर नहीं लगाया गया हैं। जैसें कि आपको पता हैं कि पिछली सरकारें इतना घाटा छोड़ गई थी लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंनें कोई नया कर नहीं लगाया हैं। यह इन्होंनें इसलिये किया कि इन्होंनें इस चीज को विचारा कि आज हरियाणा की जनता कश्ट में हैं और उनकी आमदनी कम हैं। इस बात के लिये मैं मुख्य मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और सारी कैबिनेट को बधाई देता हूं और आ ा करता हूं कि आगे के लये भी कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा।

मुझे इस सरकार से पूरी आ ाा हैं कि जो इस समय घाटा हैं उसको पूरा करने के लिये और अगर कोई पीछ लैकूना रहा हैं उसको ठीक करने के लिए यह पूरी कोि ा ा करेगी। डिमांड नम्बर दो के बारे में आपसे यही कहूंगा कि जुडि ियर के अन्दर पहले जब, ि ाड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की नियुक्ति होती थी तो उनको उसके लिये परीक्षा 33 प्रति ात नम्बर लेकर पास करनी पड़ती हैं लेकिन पिछली सरकार ने उसे 33 प्रति ात से बढ़ा कर 50 प्रति ात कर दिया था। इस वजह से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लड़को को काफी अर्से से कोई भी स्थान जुडि ियरी के अन्दर नहीं मिला हैं।

मैं मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सिस्टम में परिवर्तन लाकर पहले की तरह 33 प्रति ात कर दें। ऐसा करने से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लड़को को कुछ रियायत मिलेगी और वे इस सेवा में आ सकेंगे।

श्री अध्यक्षः अब आप वाइंड अप कीजिये।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, अभी तो मैंने भाुरू किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्षः आप दो मिनट में खम कीजिये।

चौधरी पीर चन्दः अब मैं डिमांड नम्बर 12 पर अपना सुझाव दूंगा। एम्पलायमैंट देने के लिये एस0 एस0 बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमि ान के अन्दर हरिजनों के साथ वे बे इंसाफी

हो रही हैं। अगर सौ वैकेसीज हो तो इनको 80 के बाद भाुरू किया जाता हैं। हरिजन लड़का चाहे जितना काबिल या लायक हो लेकिन उनको 80 लेना भाुरू किया जाता हैं। इससे उनको सब से बड़ा नुकसान होता हैं कि वे प्रोमो ान के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं। ऊपर वाले तो सुपरिन्टैंडैंट बन जाते हैं और वे क्लर्क के क्लर्क ही रह जाते हैं। क्योकिं जब तक ऊपर वाले 80 आदमी प्रोमोट नहीं होगे तब तक उनका नम्बर नहीं आएगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवदन करूंगा कि वे इस बे इंसाफी को दूर करें। इसको पंजाब पैट्रन पर कर दिया जाए। पंजाब में पहली वैंकेसी हरिजन को मिलती है और दूसरी, तीसरी तथा चौथी नान–हरिजनो को मिलती हैं और आगे इसे रे ाो से चलती रहती हैं। मैं कहता हूं कि कल तक पंजाब और हरियाणा एक ही थे। हम अलग अलग हुए उससे हमारी तरक्की तो जरूर हुई लेकिन भेद–भाव नहीं होना चाहिए। इसलिये सरकार से मेरा निवदेन हैं कि पंजाब पेट्रन को लागू करे हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लड़को के साथ न्याय किया जाए। इसके आलावा निगामें और कार्पोरे ाज के अन्दर इतनी गैर–इंसाफी हो रही हैं कि उनमें भाायद 2 प्रति त हरिजन भी नही होगे, नाम मात्र हैं।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि सभी विधन सभा भवन के सामने 25 आदमियों को पकड़ा गया हैं और पुलिस ने उनको बुरी तरह से घसीटा हैं।

Mr. Speaker: Anything which has happend outside the state is not the concern of this Hous. Since this incident has occurrred in the Chandigarth therritory this House is not concerned with it and hence there can be no debate on it here.

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस कमी को पूरा किया जाए। जहां तक एडहाक बेसिज पर नियुक्ति करने का संबंध है। इसमें किसी हरिजन को नहीं लिया जाता हैं। यानी भी डिपार्टमैंट में हरिजन लड़को को नहीं लिया जाता। अभी–अभी सरकार ने एक अच्छज्ञ काम किया हैं। मै उसकी सराहना किये बगैर भी नहीं रह सकता। सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया हैं कि उसने 16 हजार के करीब एडहाक कर्मचारियों को रैगुलर किया हैं। लेकिन इसमें गैर–इन्साफी यह हुई हैं कि इनमें हरिजन कोई नहीं था। यह तमाम अधिकार हमारा था। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एडहाक बेसिज पर नियुक्ति करते वक्त भी इनकी रिजर्वे ान उसी तरह से रखी जाए जैसे रैगुलर सर्विस में रखी जाती हैं। ऐसा करते से उनके साथ जो गैर–इन्साफी हो रही है वह दूर हो जाएगी।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): स्पीकर साहब, आज ऐजेन्डे पर कुल 13 **(13.00बजे)** डिमान्ड हैं और यदि हरेक डिमान्ड पर 2–2 मिनट के लिए भी बोला जाए तब भी 26 मिनट लग जाएंगे लेकिन मैं बहुत जल्द अपनी बात पूरी करने की कोि ा ा करूंगा.....

Mr. Speaker: Iam sorry, I cannot give you more than 5 minuter.

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले डिमान्ड नम्बर 13 को भ्रारू करता हूं जो कि वैल्फेयर डिपार्टमैंट के बारे में हैं। इससे पहले कि मैं इस डिमान्ड पर बोलना भ्रारू करूं अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं कि कल जब वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उन्होंनें मेरे ऊपर लगाया था। ईमानदारी के मामले पर उन्होंनें जो आरोप लगाया वे खुद जानते हैं कि किस बेसिज पर लगाया। उन्होंनें खुद किसी तरह पार्टी बदली और मैंने पार्टी नहीं बादली, इसलिए डन्होंने यह आरोप लगाने की चेश्टा की। (ाोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमने डैमोक्रेटिक सैट–अप के साथ वैल्फेयर स्टेट की कल्पना की हैं इसलिए, वैल्फेयर डिपार्टमैंट के बारें में एक सुझाव देना चाहता हूं। इस डिपार्टमैंट को एन्करेज किया जाए, बढ़ाया जाए और इसका पूरा आदर किया जाए। आज हमने बैकवर्ड क्लासिज और ि ाड्यल्ड कास्टस के लिए जितनी योजनांए इस बजट में रखी हैं, वे इस काम के लिए काफी नहीं हैं। जिस तरह से पिछली सरकार ने ि ाड्यूल्ड कास्टस के लिए चौपालों को प्रोविजन किया था, इस बार उस काम के लिए कम प्राविजन किया गया हैं। स्पीकर साहब, योजना में बुनियादी चिन्तन चाहिए। आज दे ा की 32 साल की आजादी और वैल्फेयर स्टेट के होते हुए भी हमने इधर पूरा ध्यान नहीं दिया। आज देहात के अन्दर, भाहरों के अन्छर और कस्बों के अन्दर जो गरीब औरतें हैं, वे अपनी लाज

की रखना चाहती हैं। उनके लिए भौचालयों की बुनियादी आव यकता को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव हैं कि गांव–गांव के अन्दर और कस्बों को बचा सकें। स्पीकर साहब, अभी अभी आनरेबल मुख्य मंत्री महोदय जी ने मेरे रैजोल्यू ान के जवाब में बैकवर्ड क्लासिज के लिए एक कार्पोरे ान बनाने की बात कहीं थी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं लेकिन इसके साथ–साथ मैं उनको ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि उस कार्पोरे ान से आर्थिक तौर पर और लोगों को फायदा उठाते रहें और बैकवर्ड क्लासिज के लोंगों को कोई फायदा न मिलें। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि उस कार्पोरे ान का नियन्त्रण, उस कार्पोरे ान की निगरानी बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को ही सौंपी जाए।

स्पीकर साहब, इसके बाद मैं डिमान्ड नम्बर 5 पर आता हूं जोकि एक्साइज एण्ड टैक्से ान डिपार्टमैंट के बारे में हैं मैंने सोचा था कि श्री बलवन्त राय तायल के होते हुए भाराब बन्दी की नीति पर अमल होगा लेकिन मुझे अफसोस हैं कि इसको दिलाना चाहता हूं कि हमने एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं की थी कि किसी बाप बढ़ाने के लिए लोगों को भाराबी बनाए, यह बहुत ही दु:ख की बात हैं। स्पीकर साहब, मैं नाजयज भाराब क बारे में कहना चहता हूं। भाराब के ठेको के संरक्षण में नाजायज भाराब बिकती हैं। गांव–गांव में भाराब के डिपे खुले हुए हुं।

श्री अध्यक्षः मैं नहीं समझता कि गवर्नमैंट में से कौन चाहता हैं कि सारे दे ा वाले भाराब पीयें।

श्री जय नारायण वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी व्यक्ति वि ोंश को नहीं कह सकता मैंने तो यह कहा हैं कि सरकार अपने रैवेन्यू के लालच में पड़ी हुई हैं। सरकार अपने रास्व को बढ़ाने के लिए अगर समाज र यह अछूत की बीमारी डालना चाहती हैं तो इससे बड़ी गलत बात और कोई नहीं हो सकती।

स्पीकर साहब, अब मैं एजूके ान के मामले पर बोलना चाहता हूं। इसी माले पर बोलते हुए बहिन कमला वर्मा ने एक बुनियादी बात पर सदन का ध्यान आकर्शित करवाया था। मुझे इस बात के लिए दुःख हैं कि आज सरकार ि ाक्षा के मामले में हमारे समाज को क्या बननाना चाहती हैं? क्या हमारे समाज में कोई आद र्ा हैं? यह सरकार बिना आद र्ाों का समाज बनाना चाहती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी ि ाक्षा की यह हालात हैं। स्पीकर साहब, मैं यह बात गम्भीर बात कह रहा हूं कि कालेंजो के स्तर पर और यूनिवर्सिटियों के अन्दर कबील से कबील टीचर्ज प्रोवाइड किये जाते हैं लेकिन जो प्राइमरी स्टेज की एजुके ान हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उसे निगलैक्ट किया जाता हैं। मूल रूप से बच्चों का भविश्य बनाने के लिए प्राइमरी ि ाक्षा के ऊपर अधिक जोर देने की जरूरत हैं, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं हैं।

इसके अलावा स्पीकर साहब, एक बात मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा हल्का बरवाला इतना बड़ा कस्बा हैं और उसके अन्दर आज से 15 साल पहले जो पनी की व्यस्था थी, आज भी वही व्यवस्था चल रही हैं। आज वहां के लोगों को पीने के लिए एक बाल्टी पानी के लिए तरसना पड़ता हैं। वे कहते हैं कि बरवाला के लए हमने एक लाख रूपया प्रोवाइड किया हैं। हमें एक लाख रूपए से मतलब नहीं हैं। हम तो यह चाहते हैं कि लोगो के लिए पानी की व्यवस्था की जानी चाहिएं। स्पीकर साहब, पौसवाल साहब के हल्के में एक चीकन गांव हैं उस गांव के अन्दर एक नदी पार करके जाना पड़ता हैं आज आजादी के 32 साल के बाद भी उस गांव में प ाुओं को और इन्सानों केा कटोरे से खोद कर पानी पीना पड़ता हैं। न वहां पर नहर का पनी हैं और न नदी का पानी हैं इसलिए सरकार उस तरफ भी ध्यान दें। (ाोर) अध्यक्ष महोदय, वहां आज तक कोई भी एम0 एल0 ए0 नहीं गया।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमति भाांति देवी): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीच सदन के अन्दर कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े रचानात्मक सुझाव दिए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगी कि इस थोड़े से समय के अन्दर हमने कितने ऐसे पग उठाए हैं, जोकि ि ाक्षा के हित में है। अनेंकों स्कूलों को पदोन्नत करना (अपग्रेड) , 12 अराजकीय कालेजों को टेक–ओवर करना, अराजकीय स्कूलों की ग्रांट बढ़ा कर 75 % कर देना, असमायोजित जे0 बी0 टी0

मास्टरों को मास्टर्ज ग्रेड देना, स्कूल लैक्चरर्ज को पदोन्नति के चांस देना, प्रान्तीय कैडर मास्टरों को 50 प्रति ात कोटा देकर मुख्य अध्यापकों के लिए चांस देना, दो वर्शीय एडहाक अध्यपकों को रैगुलर करने का निर्णय लेना, हरिजन छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लेना, मिडल एवं प्राइमरी स्कूलों में मुख्य अध्यापकों को 50 और 25 की रे ाो से अतिरिक्त वेतन देना, प्लान के अन्तर्गत स्कूलों में टाट पट्टी एवं दरियों का बच्चों के लिए प्रबन्ध करना, प्राइमरी स्कूलों में पार्ट टाईम सफाई कर्मचारी एवं पानी पिलानो वाले का प्रावधान करना, अराजकीय कालेजों में साइंस की ि ाक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंचिग ग्रांट सिंस्टम को लागू करना। इसके अतिरिक्त बहिन कमला वर्मा ने कई बड़े रचानात्मक सुझाव दिए है और मैं उनका स्वागत करते हुए बताना चाहूंगी कि राज्य में उपयुक्त संख्या में विज्ञान अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं फिर भी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त कालेज स्तर पर विज्ञान के विशयों को विद्यार्थियों में व्यापक रूप से प्रचलित करने के लिए प्राइवेट कालेजों में विज्ञान संकाय खोलने की योजना बनाई गई हैं जिसके अन्तर्गत उन्हें इस विशय के लिये ग्रांट दी जाएगी। प्राईवेट स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेजरीज के माध्यम से वेतन देने के मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया था परन्तु प्र ाासनिक आधार पर इसे उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि इसमें वित्तीय इम्पलीके ान्ज बहुत अधिक हैं इसलिए यह चीज सम्भव नहीं हैं। इसकी बजाए

इन स्कूलों को रिलीफ देने के लिए मेन्टेनेंस ग्रांट की प्रति ाता बढ़ा कर 75 प्रति ात कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, बहिन कमला वर्मा ने कहा था कि परीक्षा भाुल्क जो सरकार लेती हैं इसको हरिजन बच्चों से न लिया जाए, बन्द कर दिया जाए। बहिन जी ने कई रचनात्मक सुझाव दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि परीक्षा भाुल्क बोर्ड को अदा की जाती हैं और इसकी अदायगी छात्रों को ि ाक्षा विभाग द्वारा की जाती हैं। फिर भी इस सुझाव पर विचार करवा लिया जाएगा कि हरिजन छात्रों की परीक्षा भाुल्क देना ही न पड़े। यदि इसे उपयुक्त पाया गया तो इसे अडौप्ट कर लिया जाएगा। प्राथकिम ि ाक्षा को सुदृढ़ करन ेओर इसका स्तर ऊंचा करने के लिए विभाग द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं परन्तु इसके लिए पृथक निदे ाालय बनानी की जो मांग की गई हैं, यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। इस सम्बन्ध में हमने पंजाब और दूसरे प्रान्तों से रिर्पोट मंगवाई हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार मैं सदन को बताना चाहती हूं कि इस क्षेत्र में किसी प्रान्त को कोई सफलता नहीं मिली हैं। इसलिए हम यह काम करना ही नहीं चाहते। फिर भी हम प्राथमिक ि ाक्षा दे ा की रीढ़ की हड्डी हैं। कोरी स्लेट की तरह बच्चा अध्यापक के पास आता हैं इनका स्तर ऊंचा होना चाहिये, इस दि ाा में हम कदम बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, श्री जगदी ा कुमार बैनीवाल ने स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग की हैं। इन्होंनें दो स्कूलों के बारे में कहा कि इनको अपग्रेड किया जाए। में इनको बताना चाहती हूं

कि भूतपूर्व ि ाक्षा मंत्री ने जब उनके दस स्कूल अपग्रेड किये थे, उस वक्त इन दस स्कूलों में इन दोनों स्कूलों को क्यों इन्कलूड नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, श्री जोगी राम ने अध्यापकों के बारे मं कुछ सुझाव रखे। ठीक हैं, प्राथमिक अध्यापकों का स्तर ऊंचा होनी चाहिये। श्री जोगी राम जी ने अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने के बारे में जिक्र किया था। मैं उन्हें सूचित करना चाहती हूं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी हैं, भाायद वे इस रिपोर्ट को देख नहीं पाये हैं, सबसे ज्यादा वेतन अगर दिया है तो प्रईमरी अध्यापकों को दिया हैं। इन्होंनें गावों में अध्यापकों को मैडिकल भत्ता देने की बात भी सदन में कहीं। ठीक हैं, मैडिकल भत्ता मिलना चाहिये, लेकिन अगर फलैट रेट पर मैडिकल भत्ता दिया जाए तो वे लाग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं जिनके पांच–पांच हजार रूपये अपने बूढ़े मां–बाप की बीमारी पर खर्च हो जाते हैं। जो बीमार हैं, चाहे देहात का अध्यापक बीमार हैं, चाहे भाहर का अध्यापक बीमार हैं, वर्तमान सिस्टम के अर्न्तगत सरकार से मैडिकल भत्ता ले सकता हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के भत्ते का सम्बन्ध हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिये। लेकिन 60 हजार अध्यापकों का परिवार हैं, इनको ग्रामीण क्षेत्र भत्ता देने के लिए बहुत रूपया चाहिये। स्टेट पर वित्तीय बोझ बहुत बढ़ जायेगा लेकिन फिर हम इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, श्री जोगी राम ने सदन में यह बात भी

उठाई कि हर भानिवार को टीचर्ज की जो मीटिग होती हैं इसको बन्द किया जाए। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि उस मीटिंग का वि ोश महत्व हैं। इसमें वि ोश महत्वपूर्ण प्वायंट्स डिस्कस होते हैं। जैसे बहिन कमला वर्मा ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिये बात कहीं, इस किस्म के विशय, ि ाक्षा से सम्बन्धित विशय इस मीटिंग में डिस्कस होते हैं। जब तक हम नेय ढंगों से पुराने अध्यापकों को परिचित नहीं करवायेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। एक महीने में एक मीटिंग रखी जाती हैं जिसमें महत्वपूर्ण विशयों पर डिस्क ान होती है और इस मीटिंग का होना ि ाक्षा के हित में हैं।

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम ला सिंह): अध्यक्ष महोदय, डिमांडज पर बोलते हुए मेरे साथियों ने सड़कों के बारे में जिक्र किया कि कुछ हल्कों में सड़कें बनाई जा रही हैं और कुछ में नहीं बनाई जा रही। मेरे साथी ने कहा कि खादर के एरिये में बहुत सड़के बनाई जा रही हैं। मेरे साथी ने यहां पर एक भोर पढ़ा, भाायद किसी से लिखवाकर लाये होंगे, जब पढ़ने लगे तो वह गलत पढ़ दिया और फिर चेयरमैन साहब ने उसको कुरेक्ट किया। मैं इस तरफ न जाते हुए, समय के अभाव के कारण चन्द बातें कहना चाहूंगा। मेरे दो तीन साथियों ने सड़को के बारे हाउस में कई सवाल आये हैं और मैंने सप्लीमैंटरी सवालों के जवाब में सरकार की पालिसी बताई हैं। अब मैं दोबारा बता देना चाहता हूं कि वे गांव जो डायरैक्टरी के अन्दर हैं, उनके संगल

लिंक्स दिसम्बर, 1980 तक कम्पलीट करने हैं, जिनको अभी तक सड़क नहीं मिली हैं। सबसे पहले उन्हीं गावों को प्रायरिटी लैवल पर लेंगे जिनमें अभी तक सड़क नहीं मिली हैं। और सिंगल लिक्स बनने हैं। सिंगल लिंक्स बनाने के लिये आबादी का क्राइटेरिया रखा हैं। स्पीकर साहब, ग्रांटस पर डिस्क ान के दौरान यह बात भी आयी कि ब्लाक समितिज और मार्केट कमेटियों की सड़को की खस्ता हालत हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जिन ब्लाक समितियों से रैजोल्यू ान पास होकर हमारे पास आ गए हैं कि उनकी सड़को गवर्नमैंट टेक ओवर कर लें, ऐसी सड़को को टेक–ओवर करने का फैसला ले लिया हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने भी हाउस को अ योर करवाया हैं कि उन सड़को को लिया जा रहा हैं, ताकि उन सड़को की स्थिति सुधर सके। स्पीकर साहब, श्री देवी दास ने एक बात कहीं कि उनके हल्के के अन्दर एक भी सड़क नहीं बनाई। मैं आपकी मारफत हाउस को बताना चाहता हूं कि श्री देवी दास के हल्के में जितने गांव हैं वे सभी सड़को से जुडे हुए हैं।

श्री देवी दासः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, इन्होंनें कहा कि हर गांव में सड़क हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब से मैं एम0 एल0 ए0 बना हूं तब से एक किलोमीटर सड़क भी मेरे हल्के में नहीं बनी हैं।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं।

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, ये हर गांव में तीन–तीन, चार–चार सड़के बनवाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या हरियाणा के अन्दर इसी प्रकार के गांव और नहीं हैं? क्या हरियाणा में और लोग नहीं बसते जिनको पिछले 32 साल के अर्से में एक भी सड़क प्राप्त नहीं हुई? (व्यवधान) स्पीकर साहब, अब मैं दूसरे प्वायंट पर आता हूं। मेरे साथी श्री जोगी राम ने कहा कि असंध सब डिविजन के पास कोई काम नहीं हुआ हैं। मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूं कि असंध सब–डिविजन में 16 लाख रूपये का काम हुआ हैं जोकि तकरीबन एक सब–डिबिजन की लिमिट होती हैं। सब डिविजन आफिस की डिटेल में जाना नहीं चाहता, बड़ी लम्बी लिस्ट हैं और समय थोड़ा हैं। लेकिन मैं आनरबल मैम्बार को वि वास दिलाता हूं कि अगर इनको किसी बात की कोई ि ाकायत हैं तो वे मुझे लिखकर भेजें, मैं देख लूंगा। इन्होंनें एक सड़क के बारे में बताया कि पानीपत रोड़ फ्लड की लिखकर भेजें, मैं देख लूगा। इन्होंनें एक सड़क के बारें मे ंबताना चाहता हूं कि उस सड़क की वजह से काफी ख्चाराब हैं। मैं उनकी इतलाह के लिये बताना चाहता हूं कि उस सड़क की रिपेयर के लिए टै।डर इन्वाइट हो चुके हैं और इस रोड की रिपेयर का काम करने जा रहे हैं।

इसके अलावा मेरे साथी भागी राम जी ने कहा कि सिरसा के अन्दर कुछ सड़के मंजूर हुई थी लेकिन उनका काम टेक–अप नहीं किया गया। मैं हाउस की इतलाह के लिए एक बात

बताना चाहता हूं कि उस समय के मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी जिस जिले में ज्यादा इंट्रैस्ट रखते थे वहीं ज्यादा अनांउसमैंटस किया करते थे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जहां जहां डुप्लीकेट लिक्सं हैं वहां अगर बहुत जरूरी सड़क हुइ तो उसको जस्र बनवाएंगे क्योंकि हमने बाकी हरियाणा का भी ध्यान रखना हैं। जो इलाके बैकवर्ड हैं उनको हम प्रायरिटी देकर दूसरे फारवर्ड इलाकों के बराबर लाने की कोि ा ा कर रहे हैं।

चौधरी देस राजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर,। जो गांव डारैक्टरी में नहीं हैं क्या उनमें भी सजड़कें बनाई जाएंगी?

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं। यह तो प्वायंट आफ डिटेल हैं।

कंवर राम पाल सिंहः विज साहब ने एक बात कही थी। मैं आपकी मारफत उन्हें यह कहना चाहता हूं कि आज तक खादर के एरिया को काफी इग्नोर किया गया था लेकिन हमने खादर के एरिया के लिए भी काफी सड़के मंजूर की हैं। कुछक गांव, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं उनके लिए भी हम सोच रहे हैं ताकि वहां भी सड़के बनें, उनकी जिन्दगी काफी लम्बी हो और फलड् की वहजह से टूट न पांए। इस बार में हम स्टैप्स ले रहे हैं और जल्दी कोि ा ा कर रहे हैं कि उन गांवो को भी सड़को से जोड़ दें।

चौधरी देसी राज जी ने कहा कि डायरैक्टरी के अन्दर बहुत से गांव नहीं हैं और क्या सरकार वहां भी सड़के बनाएगी? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हिली एरिया में 150 और मैदानी एरिया में 250 को आबादी वाले नान–डायरैक्टरी विलेजिज का डैटा कोलैक्ट करके वहां भी सड़के बनाने का कोई फैसला लिया जाएगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः मै ंहाउस की सैन्सलेना चाहता हू कि क्या हाउस का समय पांच मिनट बढ़ा दिया जाए?

आवाजें: जरूर बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक हैं, हाउस का समय पांच मिनट बढ़ाया जाता हैं।

वर्श 1980–81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांट्स पर चर्चा तथा मतदान (पुनराम्भ)

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): स्पीकर साहब, पहले गवर्नर ऐड्रैस पर चर्चा हुई, फिर बजट पर बहस चली और अब डिमांडज पर बहस चल रही हैं। जिन लोगों ने बहस में हिस्सा लिया उन्होंनें अपने हल्के की तकलीफें बताई और कुछेक ने कहा कि इम्तायजी सलूक बतरा जा रहा हैं। विज साहब ने पानीपत म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में कुछ कहा। इसमें कोई भाक नहीं कि पानीपत भाहर एक ऐसा भाहर हैं जिस पर हर हरियाणवी नाज कर सकता हैं। वहां से 50 करोंड़ रूपये का सामान हर साल ऐक्सपोंर्ट होता हैं। यह उस भाहर के लिए गर्व की बात हैं। वहां की सड़के यदि खराब हैं या उनमें कोई बात हैं, उनको ठीक करना वहां की म्यूनिसिपल कमेटी का काम हैं। फिर भी सरकार ने पिछले साल हरियाणा के अन्दर 50 लाख रूपया म्यूनिसिपल कमेटीज को बतौर ग्रान्ट दिया। यह पैसा इसलिए दिया ताकि म्यूनिसिपल कमेटीज अपने इलाकों के अन्दर इस तरीके के काम कर सकें इस बजट के अन्दर इन म्यूनिसिपल की इमदाद के लिए 90 लाख रूपये रखे गए हैं।

स्पीकर साहब, एक बात यहां कही गई कि मंत्रि परिशद के ऊपर ज्यादा खर्च हो रहा हैं। यह ठीक हैं कि डिमांड के अन्दर 6658000 रूपये मंत्रिपरिशद के लिए रखे गए हैं लेकिन इसमें से 23,97,000 रूपया ऐसा हैं जो डिस्कि ानरी ग्रान्टस मे जाना हैं और तनख्वाह आदि में खर्च नहीं होना हैं। डिस्कि ानरी ग्रान्ट आप जानते हैं डिवैल्पमैंट के काम के लिए दी जाती हैं। तो मैं

सदन को स्पश्ट रूप में बताना चाहता हूं कि मिनिस्टरी के ऊपर केवल 42, 61, 000 तो मैं सदन को स्पश्ट रूप में बताना चाहता हूं कि मिनिस्टरी के ऊपर केवल 426100 रूपया खर्च होना हैं।

इसके बाद मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि सरकार ने बैकवर्ड कार्पोरे ान बनाने का फैसला किया हैं। यह तजवीज सरकार के ध्यान में काफी दिनों से थी। इस कार्पोरे ान को जितने पैसे की जरूरत होगी, सरकार देगी और बैकवर्ड लोगों की बैकवर्डनेस को दूर करने की कोि ा ा करेंगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा न कहते हुए यह आ ाा करता हूं कि हाउस इन 13 डिमांडज को जो आज इसके सामने हैं, अव य पास करेगा।

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब मैं डिमांडज फार ग्रान्टस को वोटिंग के लिए रखता हूं।

आवाजें: सबको इकट्ठा ही पुट कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। I will put them together,

Question in-

That a sum not exceeding Rs. 3691510 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 65977430 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that

will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 2- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 181237335 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 3- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 42483700 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 4- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 25221360 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 5- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 67016185 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 6- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 41120600 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 7- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 202571500 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 8- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 577456210 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 9- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 353166140 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 10- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 16500330 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 11- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 150740020 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 12 - Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 56121610 for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the couse of payment for the year 1980-81 in the charges munder Demand No. 13- Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.00 a.m. tomorrow the 19 th March, 1980.

13.27 Hours

(The Sabha then* adjourned till 9.00 hours on Wednesday, the 19th March)